हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

15 मार्च, 2002

खण्ड-1, अंक 8

अधिकृत विवरण

विषय सूची

शुक्रवार, मार्च 15, 2002

	पृष्ठ संख्या
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(8)1
नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	(8)17
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव -	(8)20
फरीदाबाद के क्षेत्र में प्राईवेट स्कूलों के थोड़े समय में बहुत बढ़ जाने व इन स्कूलों में विद्यार्थियों के दाखिले भी अत्याधिक दरों पर होने के संबंध में।	
वक्तव्य-	(8)21
शिक्षा राज्य मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी	
विभिन्न विषयों का उठाया जाना -	(8)[illegible]
सदन की मेज पर रखे गये कागज-पत्र	
वर्ष 2002-2003 के लिए बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)	(8)[illegible]
वैयक्तिक स्पष्टीकरण -	(8)30
श्री मांगे राम गुप्ता एम.एल.ए. द्वारा	
वर्ष 2002-2003 के लिए बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)	(8)31
वैयक्तिक स्पष्टीकरण -	(8)36
चौधरी बंसी लाल एम.एल.ए. द्वारा	
वर्ष 2002-2003 के लिए बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)	(8)37
बैठक का समय बढ़ाना	(8)57
वर्ष 2002-2003 के लिए बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)	(8)57
वैयक्तिक स्पष्टीकरण-	(8)61
श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा एम.एल.ए. द्वारा	
बैठक का समय बढ़ाना	(8)62
वर्ष 2002-2003 के लिए बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)	(8)62

मूल्य : 67 50

हरियाणा विधान सभा

शुक्रवार 15 मार्च, 2002

विधान सभा की बैठक विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में प्रात: 9.30 बजे हुई, अध्यक्ष (श्री सतबीर सिंह कादयान) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष : मैम्बर्ज साहेबान, अब सवाल होंगे।

Sports Stadium, Fatehabad

***1018. Ch. Lila Krishan :** Will the Chief Minister be pleased to state --

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct Sports Stadium at Fatehabad and ;

(b) if so, the time by which the aforesaid proposal is likely to be implemented ?

मुख्य संसदीय सचिव (श्री राम पाल माजरा) :

(क) हाँ, श्रीमान जी।

(ख) जैसे ही धनराशि उपलब्ध होगी प्रस्ताव का क्रियान्वन कर दिया जायेगा।

श्री लीला कृष्ण : स्पीकर साहब, जब से चौटाला साहब की सरकार बनी है तब से स्पोर्टस के मामले में इतना जोशो-खरोश है जो आज से पहले किसी सरकार में नहीं था। मैं चौधरी भजन लाल जी की सरकार में टूरिज्म मिनिस्टर था और चौधरी बंसी लाल जी की सरकार में भी वेयर हाउसिंग कारपोरेशन का चेयरमैन रहा हूँ। मैं खुद गवाह हूँ कि खेल के मामले में जितना जोशो-खरोश चौटाला साहब की सरकार में है उतना जोशो-खरोश पिछली किन्हीं सरकारों में भी नहीं रहा है। स्पीकर साहब, गवर्नमेंट की पालिसी है कि हर जिले में स्टेडियम बनने चाहिएं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से हिसार स्टेडियम में स्पोर्टस होस्टल है क्या उसी प्रकार से फतेहाबाद में बनाये जाने वाले स्टेडियम के अन्दर भी होस्टल आदि बनाया जायेगा।

श्री राम पाल माजरा : स्पीकर साहब, यह ठीक है कि हर जिला स्तर पर खेल स्टेडियम बनाये गए हैं। अभी 2 जिले कैथल और फतेहाबाद हैं जहां पर स्टेडियम बनाये जा रहे हैं। फतेहाबाद में जो स्टेडियम बनाया जा रहा है उसके लिए 14 एकड़ जमीन की आवश्यकता है। इसमें से 12 एकड़ जमीन तो अधिग्रहण कर ली गई है जबकि 2 एकड़ जमीन के कागजात तैयार हो रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, माननीय साधी ने पूछा है कि वहां पर स्टेडियम के

[श्री राम पाल माजरा]

अलावा और क्या बनेगा। इस बारे में मैं अपने साथी को बताना चाहूँगा कि वहां पर एक 400 मीटर का ट्रैक, पैवेलियन भवन और बहुउद्देशीय हाल बनेगा। इस स्टेडियम के लिए अभी तक 7 लाख 39 हजार रुपये जारी कर दिए हैं और इसकी चार दीवारी का काम तुरन्त प्रभाव से शुरू करने जा रहे हैं।

श्री जसवीर मलोर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या स्पोर्टस काम्पलैक्स गुड़गांव का कार्य प्रगति पर है। यदि प्रगति पर है तो उसके कब तक पूरा हो जाने की उम्मीद है।

श्री राम पाल माजरा : स्पीकर साहब, यह ठीक है कि अम्बाला और गुड़गांव में एस्ट्रोटर्फ का काम शुरू कर दिया गया है। इस काम को 2002-2003 में अर्थात् 6 महीने में कम्पलीट कर दिया जायेगा। इसके लिए टेण्डर आ गए हैं और गुड़गांव में नये स्पोर्टस काम्पलेक्स का काम हुड्डा द्वारा शुरू कर दिया गया है। यह काम वहां पर सैक्टर 38 में 45 एकड़ जमीन पर शुरू कर दिया गया है। इस स्पोर्टस काम्प्लैक्स को साढ़े आठ करोड़ रुपये में बनाया जा रहा है और इसके बनने तक इस काम्पलेक्स की लागत भी बढ़ जाने की उम्मीद है।

श्री रमेश कुमार खटक : स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से सी.पी.एस. जी से जानना चाहता हूँ कि स्टेडियम बनाये जाने के लिए क्या-क्या नार्म्ज रखे गए हैं।

श्री राम पाल माजरा : स्पीकर सर, इसके लिए दो स्तर हैं। जिला स्तर पर जो स्टेडियम बनाये जाते हैं वे कुछ बड़े बनाए जाते हैं और उनमें कुछ अतिरिक्त सुविधाएं दी जाती हैं लेकिन जो ग्रामीण स्तर पर स्टेडियम बनाए जाते हैं। उनके लिए 5 एकड़ जमीन ग्राम पंचायत दे और अपनी तरफ से 75 हजार रुपये सरकार के पास जमा करवाए। 75 हजार रुपये स्टेट गवर्नमैंट की ओर से दिए जाते हैं तब केस सैंटर गवर्नमैंट को भेजा जाता है और फिर मन्जूरी मिलने पर स्टेडियम बनाया जाता है।

श्री भगवान सहाय राक्त : अध्यक्ष महोदय, जैसे कि हमारे यहां जिला स्तर के स्टेडियम के साथ ही ग्रामीण स्तर पर भी स्टेडियम बनाने का प्रावधान है और जैसे कि अभी माननीय मुख्य संसदीय सचिव महोदय ने यह बताया है कि जो ग्राम पंचायत 75 हजार रुपये अपनी तरफ से जमा करवाएगी तो स्टेडियम बनाया जाएगा। मैं आपके माध्यम से सी.पी.एस. महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि जिन ग्राम पंचायतों ने 75 हजार रुपये जमा करवाए हुए हैं वे कितनी हैं और वहां पर स्टेडियमज कब तक बन कर तैयार हो जायेंगे।

श्री राम पाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने माननीय साथी को बताना चाहूँगा कि पहले तो केस गवर्नमैंट ऑफ इण्डिया को भेजा जाता है। स्पीकर सर, 27 खेल मैदानों के लिए 40 लाख रुपये आबंटित कर दिए गए हैं और उन पर काम शुरू कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त कुछ दरखास्तें और भी आई हैं स्टेट गवर्नमैंट उन दरखास्तों को एग्जामिन करेगी और फिर केस गवर्नमैंट ऑफ इण्डिया को भेजेगी जब कि कुछ केस ऑलरैडी गवर्नमैंट ऑफ इण्डिया को भेजे हुए हैं।

श्री अमर सिंह डांडे : स्पीकर सर, मेरे क्षेत्र नगरपालिका चीका में आठ एकड़ जमीन स्टेडियम के लिए दी हुई है और 75 हजार रुपये की राशि भी जमा करवाई हुई है, मैं आपके माध्यम से आदरणीय सी.पी.एस. महोदय से यह जानना चाहूँगा कि वहां पर स्टेडियम का काम कब तक शुरू हो जाएगा ?

श्री राम पाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, जैसे कि मैंने बताया है कि फोरमैल्टिज पहले पूरी करते हैं। जिन पंचायतों ने 75 हजार रुपये की राशि जमा करवा दी होती है उनके केसिज को स्टेट गवर्नमैंट की ओर से सैंटर गवर्नमैंट को भेजा जाता है और उसके बाद ही स्टेडियम का काम शुरू करते हैं।

श्री लीला राम : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सी.पी.एस. महोदय को यह बताना चाहूँगा कि

कैथल में अभी तक खेल स्टेडियम नहीं बना है जबकि वहां पर खेल स्टेडियम मन्जूर किया हुआ है। मैं आपके माध्यम से सी.पी.एस. महोदय से यह जानना चाहूँगा कि कैथल में खेल स्टेडियम कब तक बन कर तैयार हो जाएगा।

श्री राम पाल माजरा : स्पीकर सर, जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि दो जिले ऐसे हैं जहां खेल स्टेडियम नहीं है। जिला कैथल और जिला फतेहाबाद में स्टेडियम का काम शुरू नहीं हुआ है। कैथल जिला में उसके लिए जमीन की दिक्कत थी। इसके लिए हुड्डा में 30 एकड़ जमीन ऐक्वायर करने का फैसला किया है। जमीन ऐक्वायर करने के लिए दफा 4 तथा दफा 6 के तहत नोटिस जारी कर जमीन प्राप्त की जाएगी और वहां पर बाद में स्टेडियम तैयार किया जाएगा।

आई.जी (सेवानिवृत) शेर सिंह : स्पीकर सर, दो जगह पर हॉकी के लिए एस्ट्रोटर्फ बनाने जा रहे हैं वह अच्छी बात है। स्पीकर सर, हमारे देश में हॉकी का स्तर बहुत ही नीचे चला गया है जबकि पहले हमारी हॉकी का स्तर बहुत ही ऊंचा था। इन दोनों जगहों पर हम किस तरह की व्यवस्था करने जा रहे हैं खासतौर पर उन बच्चों के लिए जो कि बडिंग हैं, वही आगे चल कर उभर कर ऊपर आएंगे, क्या उन बच्चों के लिए किसी प्रकार की व्यवस्था करने जा रहे हैं या कुछ किये जाने की कोई परपोजल सरकार के पास है?

श्री राम पाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से इन्होंने अभी बताया है कि एस्ट्रोटर्फ के लिए काम शुरू किये जा रहे हैं। इसी प्रकार से बच्चों की उम्र के मुताबिक उनके कौशल को डिवैल्प करने के लिए नर्सरियां शुरू की गई हैं। विभिन्न बोर्डज तथा कारपोरेशन्ज से कहा गया है कि इन नर्सरियों में से ही बच्चों को डिवैल्प किया जाएगा और आगे जाकर स्कूलों और कॉलेजों में डिवैल्प होकर आगे जाएंगे। मैं माननीय साथी को बताना चाहूँगा कि बच्चों का जो स्किल है और जो प्रतिभाएं हैं ग्रामीण अंचल में उनको कलैक्ट करके उनको डिवैल्प किया जायेगा।

चौ. नफे सिंह राठी : स्पीकर सर, बहादुरगढ़ में ब्रिगेडियर होशियार सिंह स्टेडियम है और उस स्टेडियम के नाम पर मल्टीपरपज हॉल के नाम पर 10 लाख रुपये कई साल से आए पड़े हैं लेकिन 10 लाख में मल्टीपरपज हॉल नहीं बन सकता। मैं माननीय सी.पी.एस. जी से जानना चाहूँगा कि क्या उस पैसे से वहां पर एक रैसलिंग शैड बनाया जा सकेगा ?

श्री राम पाल माजरा : स्पीकर सर, वैसे तो जिस परपज के लिए पैसा आया है वह उसी परपज के लिए खर्च होना चाहिए। अगर माननीय साथी उस पैसे को किसी दूसरे परपज के लिए यूज करना चाहते हैं तो वे परपोजल बना कर भेजें ताकि उसी काम के लिए पैसे लगाने के लिए हम विचार कर सकें। (विघ्न)।

श्री बलवन्त सिंह मावना : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि मेरे हल्के के जुलाना गांव के अन्दर स्टेडियम के लिए नार्मज के हिसाब से पैसा जमा करवा दिया गया है, वहां पर कब तक काम शुरू होने की सम्भावना है।

श्री राम पाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी बताया है और अब फिर बता देता हूँ कि जिनकी तरफ से 75 हजार रुपए और पांच एकड़ जमीन दे दी गई है, वहां पर काम जल्दी शुरू हो जाएगा। हमारे पास 27 खेल मैदानों के लिए पैसा आ चुका है और हमने गवर्नमैंट ऑफ इण्डिया को दरख्वास्तें भेजी हुई हैं, जितने भी केस हैं उनको एग्जामिन कर लिया गया है और कार्य प्रोसैस में है। गवर्नमैंट ऑफ इण्डिया से पैसा उपलब्ध होने पर कार्य पूरा कर दिया जाएगा।

श्री राम फल कुण्डू : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि सफीदों में भी खेल का मैदान बनाने की परपोजल इनके पास बनकर आई थी, क्या वह सरकार के विचाराधीन है। अगर हां

[श्री रामफल कुण्डू]
तो कब तक कार्य पूरा कर दिया जाएगा ?

श्री राम पाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, इस बारे में भी मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि सफीदों के बारे में भी यही नार्मज हैं जो कि मैंने जिला स्तर के बारे में बताएं हैं। अगर इन्होंने फारमैलेटीज पूरी की होंगी और 75,000 रुपया जमा करवा दिया होगा तो मैं इनको यह बताना चाहूँगा कि यह कार्य प्रोसैस में है और उस पर जरूर कार्यवाही होगी।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, अम्बाला और गुड़गांव में जो एस्ट्रोटर्फ लगाया जा रहा है यह बहुत ही सराहनीय कार्य है। मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि यह एस्ट्रोटर्फ अम्बाला कैन्ट में जो मौजूदा फुटबाल स्टेडियम है जहां पर दूसरी खेल एक्टिविटिज भी होती हैं और बाकी मल्टीपरपज काम भी होते हैं उसमें भी एस्ट्रोटर्फ लगाया जा रहा है या अलग से स्टेडियम बनाया जा रहा है।

श्री राम पाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, एस्ट्रोटर्फ लगाने का जो अम्बाला में प्रोविजन किया गया है वह अलग से लगाया जाएगा। अम्बाला और गुड़गांव में एस्ट्रोटर्फ लगाने का काम जल्दी ही शुरू हो जाएगा।

Posting of Doctors in C.H. Jhajjar

***999 Sh. Daryao Singh Rajora** : Will the Minister of State for Health be pleased to State whether there is any proposal under consideration of the Govt. to post the Doctor for night duty in the Civil Hospital, Jhajjar, if so, the time by which the doctor will be posted there ?

स्वास्थ्य राज्य मंत्री (डॉ. एम.एल. रंगा) : जी नहीं, सामान्य अस्पताल, झज्जर में चिकित्सा अधिकारी रात्रि में काल ड्यूटी पर उपलब्ध होता है।

श्री दरियाव सिंह राजौरा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि झज्जर जिले से 80 किलोमीटर के बीच में अस्पताल में रात की ड्यूटी पर डाक्टर की कोई व्यवस्था नहीं है। वहां पर रात की ड्यूटी पर डॉक्टर होना बहुत जरूरी है। कई बार तो मुझे मौका मिला है कि दिन वाले डॉक्टर को बुलाने के लिए रात को जगाना पड़ता है इसलिए वहां पर लोगों को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। एक-एक और डेढ़-डेढ़ घंटा बैठने के बाद डॉक्टर आता है इतने में मरीज की हालत पतली हो जाती है। इसके अलावा किसी को कोई छोटी-मोटी चोट लग जाती है तो उसको रोहतक के लिए रैफर कर दिया जाता है। वहां तक जाते-जाते मरीज की हालत और खराब हो जाती है इसलिए वहां पर मंत्री जी रात के डॉक्टर की व्यवस्था करने की कृपा करें।

डॉ. एम.एल. रंगा : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो रोहतक का मैडिकल कॉलेज और अस्पताल झज्जर से 30-35 किलोमीटर दूर है और रिवाड़ी के बारे में बताया कि वह रोहतक से 80 किलोमीटर दूर पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने साथी को बताना चाहूंगा कि हमारे परम आदरणीय मुख्य मंत्री जी की प्राथमिकता है कि जहां पर जिला हैड क्वार्टर है, जहां पर जिला है वहां पर कैजुअल्टी सर्विस दी जाए। अध्यक्ष महोदय, पिछली बार बजट में इन्होंने देखा होगा कि 15 लाख 50 हजार रुपये का प्रावधान था और मई में स्टाफ सैंक्शन कर दिया था और आज वहां पर कैजुअल्टी के नाम पर स्टाफ सैंक्शन है। इसके साथ ही मैं माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि हमारे यहां जहां-जहां पर रिक्त वैकेन्सियां हैं तो उनके लिए हमने 200 पदों को एडवरटाईज करके इन्टरव्यू ले लिए हैं और उनकी जहां-जहां जरूरत है वहां-वहां लगा दिया जाएगा तथा साथ ही जहां पर भी कैजुअल्टी सर्विस की जरूरत है वह भी शुरू कर दी जायेगी।

प्रो. राम भगत : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि नारनौंद में एक

सी.एच.सी. है। उसके बारे में मैं सरकार से पिछले दो सालों से रिक्वैस्ट कर रहा हूँ। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : राम भगत जी, आप रिलेटिड प्रश्न ही पूछें। यह झज्जर के बारे में प्रश्न है और आप उससे रिलेटिड सप्लीमैंटरी पूछें।

प्रो. राम भगत : अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछ रहा हूँ कि हमारे नारनौंद में जो सी.एच.सी. है वहां पर कोई लेडी डॉक्टर नहीं है, मंत्री जी वहां पर लेडी डॉक्टर कब तक भेजने का कष्ट करेंगे।

डॉ. एम.एल. रंगा : अध्यक्ष महोदय, मैं इनको यह बताना चाहूंगा कि हमारे 200 डाक्टर्ज की सूची यथा शीघ्र आने वाली है और हम सबसे पहले नारनौंद में लेडी डाक्टर लगाएंगे।

श्रीमती वीना छिब्बड़ : स्पीकर सर, अम्बाला में एक बहुत सुंदर हॉस्पीटल है लेकिन उसके अंदर कोई एक्सरे विशेषज्ञ नहीं है और वहां जो अल्ट्रा साउंड मशीन है वह भी बेकार पड़ी हुई है। एक्सरे करने वाला है लेकिन उसके बारे में रिपोर्ट देने वाला कोई डॉक्टर नहीं है। अगर वहां पर कोई एक्सरे विशेषज्ञ आ जाए तो अल्ट्रा साउंड का काम वहीं पर हो सकता है। अब यह है कि लोग वहां आ जाते हैं लेकिन बाद में उनको बाहर से जाकर अल्ट्रा साउंड करवाना पड़ता है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से आपके माध्यम से पूछना चाहूंगी कि क्या वे वहां पर कोई रेडियोग्राफर लगाने की व्यवस्था करेंगे। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहूंगी कि जितने भी एम.डी. डॉक्टर्ज हों, उनको पोस्टमार्टम के कार्य में न लगाया जाए। जब वे पोस्टमार्टम के लिए जाते हैं तो बाद में पोस्टमार्टम के केसिज में इनको न्यायालयों में गवाही के लिए जाना पड़ता है नतीजा यह होता है कि इनसे अपना इलाज करवाने के लिए अस्पतालों में जनता की लाइने लगी रहती हैं लेकिन ये वहां पर उपलब्ध नहीं होते। इसलिए मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगी कि आपात् स्थिति को छोड़कर पोस्टमार्टम के लिए एम.डी. डॉक्टर्ज के बजाए अन्य डॉक्टर्ज की ड्यूटी लगायी जाये ताकि बाद में अगर दूसरे डॉक्टर्ज को गवाही के लिए कोर्टस में भी जाना पड़े तो जनता को कोई दिक्कत न हो। इसी तरह से अध्यक्ष महोदय, एम.डी. डॉक्टर्ज की ड्यूटी रात को भी अस्पताल में न लगायी जाए। जब ये रात को ड्यूटी पर होते हैं तो दिन में ये अस्पताल में लोगों का इलाज नहीं करते। लोगों की वहां पर बड़ी-बड़ी लाइनें लगी रहती हैं लोगों को पता ही नहीं होता कि इनकी ड्यूटी रात को थी। लोग दूर-दूर से गांवों से आते हैं। इसलिए मंत्री जी इस बारे में भी ध्यान दें।

डॉ. एम.एल. रंगा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सम्मानित सदस्या को बताना चाहूँगा कि जो सुपर स्पेशलिस्टस या स्पैशलिस्टस डॉक्टर्ज हैं, उनका इस बारे में ध्यान रखते हैं कि दिन में ही उनकी सेवाएं ली जाएं। यह दूसरी बात है कि अगर कोई डॉक्टर छुट्टी चला जाए तो मजबूरी में उनकी ड्यूटी रात को भी लगानी पड़ती है लेकिन आगे से जरूर इस विषय में ध्यान रखा जाएगा कि जो एम.डी., एम.एस. या सुपर स्पेशलिस्ट डाक्टर्ज हैं उनकी दिन में ही ड्यूटी लगायी जाए। इसके अलावा इन्होंने इनकी ड्यूटी पोस्टमार्टम के लिए न लगाने के बारे में भी कहा। अध्यक्ष महोदय, अगर पोस्टमार्टम के केसिज में एम.डी. की ड्यूटी कोर्टस में गवाही देने के लिए लगायी जाती है तो उनकी जगह दूसरे डॉक्टर्ज की व्यवस्था की जाती है उनकी जगह पर कोई न कोई डॉक्टर जरूर बिठाया जाता है ताकि वह मरीजों की देखभाल कर सके।

श्रीमती वीना छिब्बड़ : स्पीकर सर, लोग जिन डॉक्टर्ज से अपना इलाज पहले से ही करवा रहे होते हैं वे उन्हीं को बाद में भी दिखाना चाहते हैं।

डॉ. एम.एल. रंगा : अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से इन्होंने एक्सरे विशेषज्ञ वहाँ पर लगाने की बात कही। अम्बाला जिले का यह सौभाग्य है कि यूरोपियन कमीशन ने जहां करनाल और यमुनानगर जिले को लिया है वहीं उसने अम्बाला जिले को भी लिया है। यूरोपियन कमीशन द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि यदि इन अस्पतालों

[डॉ. एम.एल. रंगा]

में कोई डॉक्टर्ज या विशेषज्ञ सरकार के पास नहीं हैं तो वह प्राइवेट डॉक्टर्ज को अंगेज करके उसको पैसा देकर काम चला सकते हैं। फिर भी मैं माननीय सदस्या को कहना चाहूंगा कि वहां पर रेडियोग्राफर की व्यवस्था यथाशीघ्र की जायेगी। अध्यक्ष महोदय, अगर कोई जहर खाकर मर जाता है या जैसे कई बार ऐक्सीडैंटस हो जाते हैं तो ऐसे केसिज में एम.डी. डॉक्टर की पोस्टमार्टम के लिए ड्यूटी लगायी जाती है इस अवस्था में सुपर स्पेशलिस्टस या स्पेशलिस्टस से ही यह कार्य करवाना अनिवार्य हो जाता है। ऐसे केसिज में कोर्टस में उनको गवाही देने जाना ही पड़ता है इसलिए उनकी जगह दूसरे डॉक्टर्ज को कोर्टस में नहीं भेजा जा सकता। फिर भी दूसरे डाक्टर्ज मरीजों को अटैंड करते हैं।

श्री भागी राम : स्पीकर सर, इसमें कोई दो राय की बात नहीं यह कि क्वैश्चन पर्टीकुलर झज्जर के बारे है। स्पीकर सर, कांग्रेस के समय में ऐसा होता था कि यह क्वैश्चन फलां चीज से संबंधित नहीं है इसलिए आप दूसरा क्वैश्चन पूछें। वे केवल टालने के लिए ऐसा करते थे क्योंकि उस समय के वजीर तैयारी करके ही नहीं आते थे। वे ऐसे ही कह देते थे कि आप दोबारा से क्वैश्चन पूछें लेकिन अध्यक्ष महोदय, हमारे वजीर ऐसे हैं कि पूरी तैयारी करके आते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या उनके पास ऐसी शिकायतें आयी हैं कि जिन जगहों पर डॉक्टर्ज की ड्यूटी हैं और वहीं पर सरकारी अस्पतालों में उनकी घरवाली भी डॉक्टर्ज हैं और उन्होंने अपना प्राइवेट अस्पताल खोल रखा है तथा वहां पर सरकारी अस्पताल की दवाइयां प्राइवेट अस्पताल में ले जाकर यूज करते हैं। ऐसी कितनी शिकायतें इनके पास आयी हैं कृपया यह बताएं।

डॉ. एम.एल. रंगा : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो इनका यह सवाल इस प्रश्न से संबंधित नहीं है लेकिन फिर भी मैं इनको बताना चाहूंगा कि इस विषय में हमारे पास 28 शिकायतें आयी हैं जिनमें से हमने 18 को चार्जशीट किया हुआ है। हमारा फ्लाईंग स्कावड होस्पीटल्ज में जाकर इस बारे में देखता है। यदि आगे भी इस तरह की शिकायतें हमारे पास आएंगी तो हम अवश्य कार्यवाही करेंगे। अगर सम्मानित सदस्य को इस बारे में कहीं से कोई शिकायत है तो वे बता दें।

श्री भागी राम : स्पीकर सर, ऐलनाबाद में इस तरह की शिकायत आयी है।

डॉ. एम.एल. रंगा : स्पीकर सर, ऐलनाबाद में हमने कार्यवाही की है वहां पर स्टाफ नर्स के खिलाफ कार्यवाही की गयी है। यदि इस बारे में कोई और भी शिकायत आएगी तो हम उस पर भी कार्यवाही करेंगे।

श्रीमती अनीता यादव : स्पीकर सर, जमालपुर गांव जाखड़ खाप के लोगों की कमाई से बना हुआ एक अस्पताल है लेकिन वहां पर 6 महीनों से कोई डॉक्टर ही नहीं है (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : आप केवल झज्जर के बारे में पूछें।

श्रीमती अनीता यादव : स्पीकर सर, यह मेरे क्षेत्र सांल्हावास से संबंधित समस्या है। वह अस्पताल बड़ी ही आस्था से बनाया गया था और किसानों ने अपनी कष्ट कमाई देकर बनवाया था वहां आज छह महीने से कोई डाक्टर नहीं है। इसी तरह से नाहड़, पी.एच.सी. में कोई डॉक्टर नहीं है, यदि वहां कोई गाइनाकॉलोजिस्ट लेडी डॉक्टर भेज दें तो और भी अच्छा रहेगा। इसी तरह से कौंसली की पी.एच.सी. में भी कोई डॉक्टर नहीं है वहां भी लेडी डॉक्टर या कोई जैंटस डॉक्टर भेज दें तो वहीं फर्स्ट ऐड की सुविधा हो जाएगी और इससे मरीजों को सुविधा हो जायेगी। अध्यक्ष महोदय, मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि इन तीनों जगहों पर डॉक्टर भेजे जाएं।

डॉ. एम.एल. रंगा : अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार की प्राथमिकता यह थी कि जिन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कोई डॉक्टर नहीं है वहां डॉक्टर नियुक्त किए जाएंगे। इस बात को ध्यान में रखकर हमारी सरकार ने आते ही दिसम्बर, 1999 में 323 डॉक्टरों की नियुक्तियां करवाई। जनवरी 2000 में 58 डॉक्टरों की व 2001 में 183

डॉक्टरों की नियुक्तियां करवाई। आज के दिन हमारे पास डॉक्टरों के कुल 1677 पद हैं जिनमें से 1428 डॉक्टर कार्यरत हैं, 249 डॉक्टरों के पद खाली हैं उसमें से दिसम्बर, 2001 में 200 डॉक्टरों के पद ऐडवर्टाइज किए जा चुके हैं और जनवरी में उनका इन्टरव्यू लिया जा चुका है तथा अगले महीने तक उनकी नियुक्ति कर दी जायेगी। जहां तक बहन अनीता यादव ने बताया है उनके यहां भी इन डॉक्टरों में से डॉक्टर नियुक्त कर दिए जायेंगे। इसी बीच में 30 डॉक्टर्ज पी.जी. करके आने वाले हैं उनमें से जो स्पैशियैलिटीज प्राप्त महिला डॉक्टर होगी वह इनके यहां नियुक्त कर दी जायेगी।

श्री देवराज दीवान : अध्यक्ष महोदय, अभी-अभी हमारे साथी श्री भागी राम जी ने डॉक्टरों के बारे में बताया। मैं बताना चाहूँगा कि हमारे सोनीपत में भी एक सरकारी डॉक्टर ने प्राइवेट अस्पताल अपनी बीवी को खोल दिया है। उसके बारे में मैंने मुख्य मंत्री जी को शिकायत की थी तो उसका ट्रांसफर कर दिया था लेकिन कुछ दिन बाद उसका ट्रांसफर कैंसिल हो गया और वह वहीं का वहीं रहा। अब वह सरकारी अस्पताल के सारे केस अपनी बीवी के पास भेजता है कि वे चैकअप वहाँ कराओ, टैस्ट वहाँ कराओ। खुलेआम यह हो रहा है इसके बारे में सारे सोनीपत को पता है, सी.एम.ओ. को भी पता है लेकिन सी.एम.ओ. भी ऐसा ही है।

श्री अध्यक्ष : देवराज दीवान जी, आप भी कमाल करते हैं। यदि कोई शिकायत है तो लिखकर दें। यह हाउस में करने वाली बात नहीं है।

श्री भगवान सहाय रावत : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि रात्रि में डॉक्टर नियुक्त करने के प्रश्न के उत्तर में जो कुछ मंत्री महोदय ने बताया है। उसके बारे में मैं भी कुछ जानना चाहूँगा। हरियाणा में डॉक्टरों की नियुक्तियां करने के बाद से ही यह उम्मीद की जा रही थी कि सभी जगह डॉक्टर लगा दिये जाएंगे। पिछले सदन में भी मैंने यह बात उठाई थी कि हथीन अस्पताल में, उटावड़ व मांगल जाट पी.एच.सी. में डॉक्टर नहीं है और कहने पर टेम्परेरी अरेंजमैंट के तहत वहाँ डॉक्टर लगा दिए थे अब वहां फिर डॉक्टर नहीं हैं, क्या वहां परमानैंट डॉक्टर अप्वाइन्ट करने की कोशिश करेंगे। अध्यापकों की तरह डॉक्टर भी शहरों में बैठे हैं गांव में जाने को तैयार नहीं हैं, क्या मेवात जैसे क्षेत्र में परमानैंट डॉक्टर नियुक्त किए जाएंगे ?

डॉ. एम.एल. रंगा : अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने स्वास्थ्य नीति के तहत पहली बार निर्णय लिया है कि जो नये डॉक्टर नियुक्त किए जाएंगे उन्हें रूरल एरिया सर्विस कंपलसरी की हुई है। जहां तक मेवात एरिया में डॉक्टर दिए जाने की बात है इनकी बात ठीक है कि जब भी हम मेवात में किसी डॉक्टर को भेजते हैं तो वे कोई न कोई बहाना लेकर पोस्टिंग कैंसिल करा लेते हैं। फिर भी उस एरिया से डॉक्टर नियुक्त होंगे उनको वहां पोस्टिंग किया जाएगा ताकि वे ट्रांसफर कैंसिल न करवाएं।

Repair of Water Works

*1054 **Ch. Jagjit Singh** : Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to repair the following water works, Charkhi Dadri Sub Division :--

(1) Imlota water works;
(2) Patuwas water works ;
(3) Paintawas Khurd water works;
(4) Chhapar water works;
(5) Misri water works ; and
(6) Bhageshwari water works ?

मुख्य संसदीय सचिव [श्री राम पाल माजरा] : जी नहीं श्रीमान।

चौ. जगजीत सिंह सांगवान : अध्यक्ष महोदय, मैंने जलघरों के जो नाम दिए हैं उनमें क्रम संख्या 4 पर छापर नाम दिया हुआ है। छापर कोई गांव नहीं है। छपार गांव है इसके बारे में दिखवा लें कि कहीं नाम गलत होने की वजह से जवाब में नहीं कह दिया हो।

श्री अध्यक्ष : अंग्रेजी में छपार ही लिखा हुआ है। ठीक लिखा हुआ है।

चौ. जगजीत सिंह सांगवान : सर, हिन्दी में छापर लिखा है इसलिए मैंने कहा है। अध्यक्ष महोदय, मैंने जो क्वैश्चन दिए थे उसमें इनकी मरम्मत के साथ-साथ इनमें पानी भरने के लिए भी कहा है, कई सालों से पैंताबास खुर्द मिसरी, इमलोटा में पानी नहीं भरा गया है। इमलोटा, छपार के जलघरों को चलाया भी नहीं गया है उसके ऊपर मंत्री महोदय क्या करने जा रहे हैं इस बारे में बतायें।

श्री राम पाल माजरा : स्पीकर सर, माननीय साथी ने विशेष तौर से इमलोटा के जलघर की बात की है। यह ठीक है कि 1999 में इमलोटा का जलघर 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की कैपेसिटी के हिसाब से बनाया गया था। यह ठीक है कि दुबलधन माईनर के टेल एंड पर होने की वजह से इसमें पानी उपलब्ध नहीं हो रहा था परन्तु अब 20-25 दिनों से पानी की रोटेशन ठीक चल रही है और पानी भी ठीक पहुंच रहा है। इसकी कमी पूर्ति को पूरा करने के लिए दो सैलों टयूबवैल्ज लगाये गये हैं इसलिए अब वहां पर पानी ठीक जा रहा है। इसी प्रकार से पैंताबास कलां के जलघर की बात है, यह जलघर बधवाना डिस्ट्रीब्यूट्री से जुड़ा हुआ है इसकी पानी की कमी को पूरा करने के लिए चार सैलों टयूबवैल्ज लगाये गये हैं। पैंताबास कलां का जलघर 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की कैपेसिटी के हिसाब से बनाया गया है और इसका पानी अब ठीक सप्लाई किया जा रहा है। इसी प्रकार से पैंताबास खुर्द का जलघर 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की कैपेसिटी के हिसाब से बनाया गया है। यह मानहेक माईनर से जुड़ा हुआ है इसकी कमी पूर्ति करने के लिए दो सैलो टयूबवैल्ज लगाये गए हैं और रोटेशन से पानी पहुंच रहा है फिर भी मेरे साथी की जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि पहले यह जलघर चार गांवों को फीड करने के लिए 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से बनाया गया था लेकिन अब कितलाना गांव के लिए अलग से जलघर 72.32 लाख रुपये की लागत का इस योजना में स्वीकार कर दिया गया है। उसका काम 90 प्रतिशत पूरा हो चुका है। अब बाईफ्रकेट करने के बाद इसकी कैपेसिटी ठीक हो जायेगी। इसी प्रकार छपार का जलघर 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की कैपेसिटी के हिसाब से बनाया गया है और उसका पानी संतोषजनक ढंग से दिया जा रहा है। इसी प्रकार से मिसरी का जलघर 30 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की कैपेसिटी के हिसाब से बनाया गया है। उसकी आगुमेंटेशन का काम 60 प्रतिशत पूरा हो चुका है और यह काम मई, 2002 तक, पूरा हो जायेगा। इसी प्रकार से भागेश्वरी के जलघर की बात है। वहां पर रोटेशन में पानी की कमी की वजह से पानी की कमी हो गई थी और इस कमी को पूरा करने के लिए दो नलकूप लगाये गये हैं लेकिन अब वहां पर पानी पहुंच गया है। इस प्रकार से 6 जलघरों की माननीय साथी ने बात की है। इन सब का कार्य अब ठीक होने जा रहा है और इनकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि इस सरकार ने पानी की व्यवस्था को संवारने के लिए बहुत कार्य किये हैं। यह सारी इस सरकार की उपलब्धियां है अगर फिर भी माननीय साथी को कोई शंका है तो मैं उनको आंकड़े दिखा सकता हूँ वे चैक कर लें।

श्री कृष्ण लाल : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से चीफ पार्लियामैंटरी सैक्रेटरी महोदय से जानना चाहता हूँ कि असन्ध कस्बा एक सब डिवीजन है वहां पर 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की कैपेसिटी का जलघर था। लेकिन पिछले दिनों माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने अढ़ाई करोड़ की लागत से वहां पर वाटर वर्क्स का उद्घाटन किया है और वह वाटर वर्क्स चालू हो चुका है। वहां पर 125 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से कैपेसिटी हो

गई है और माननीय मुख्य मंत्री महोदय वहां पर सीवरेज सिस्टम लगाने की मंजूरी देकर आये हैं। क्या मंत्री महोदय बताएगें कि वहां पर सीवरेज सिस्टम लगाने की व्यवस्था करने का काम करेंगे, क्योंकि वहां पर सीवरेज सिस्टम लगाने के नार्म्स पूरे हो चुके हैं।

श्री राम पाल माजरा : स्पीकर सर, वैसे तो यह प्रश्न जलपूर्ति के बारे में था। लेकिन मेरे माननीय साथी श्री कृष्णलाल पंवार ने सीवरेज व्यवस्था के बारे प्रश्न किया है। यह ठीक है कि सीवरेज व्यवस्था वहीं पर लगायी जाती हैं जहां पर 10 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पानी की सप्लाई की जाती है। इन्होंने कहा कि असन्ध में 125 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन की कैपेसिटी हो गई है तो नार्म्स तो पूरे हो चुके हैं इसलिए सीवरेज व्यवस्था लगाने बारे में विचार कर लिया जायेगा।

10-00 बजे **श्री धर्मवीर सिंह :** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि भिवानी जिले के तीन गांव ऐसे हैं जहां पीने का पानी नहीं है और फसल कटने का समय आने वाला है इसलिए सरकार इस पर कोई विचार करेगी।

श्री अध्यक्ष : धर्मवीर जी, जो गांव सवाल में कहे गए हैं आप इन्हीं गांवों के बारे में ही पूछें।

श्री धर्मवीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, भिवानी जिले के ये तीन गांव खापड़ियावास, झारीवास और खारीवास इन्हीं गांवों के साथ लगते हैं वहां पीने का पानी बिल्कुल नहीं है और फसल कटने का समय आने वाला है और गर्मी का भी मौसम आ रहा है तो क्या सरकार इन गांवों में पानी की व्यवस्था के लिए कोई कदम उठा रही है।

श्री अध्यक्ष : धर्मबीर जी, आप पीने के पानी की बात कर रहे हैं या सिंचाई के पानी की बात कर रहे हैं।

श्री धर्मवीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं पीने के पानी के लिए ही कह रहा हूँ।

श्री राम पाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहूँगा कि वैसे इन योजनाओं में तो इन गांवों का कहीं कोई जिक्र नहीं है फिर भी मेरे साथी धर्मवीर जी ने कहा है कि उनके यहां पीने के पानी की व्यवस्था की जाए तो मैं इनको बताना चाहूँगा कि इस सरकार के मुखिया का पहला काम प्रदेश की जनता को स्वच्छ पानी पिलाना है।

Distribution of Power Utilities

***888 Dewan Pawan Kumar :** Will the Chief Minister be pleased to state --

(a) whether any addition of distribution transformers has taken place in the system of the distribution of the Power Utilities ; and

(b) if so, the details thereof for the last five years ?

मुख्य संसदीय सचिव (श्री राम पाल माजरा) :

(क) हाँ श्रीमान, वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए तथा बिजली की गुणवत्ता प्रदान करने के लिए बिजली कम्पनियों द्वारा 19651 वितरण ट्रांसफार्मर और जोड़े गए हैं।

(ख) पिछले पांच वर्षों के लिए जोड़े गए वितरण ट्रांसफार्मरों का वर्ष अनुसार एक विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

[श्री राम पाल माजरा]

विवरण

पिछले पांच वर्षों के दौरान बिजली कम्पनियों द्वारा प्रणाली में जोड़े गए वितरण ट्रांसफार्मरों का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार से है :

वर्ष	प्रणाली में जोड़े गए वितरण ट्रांसफार्मर
1997-1998	2887
1998-1999	3599
1999-2000	3504
2000-2001	4465
2001-2002 (31-1-2002 तक)	5196
योग	19651

दीवान चन्द कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूँगा कि जो 2001-2002 में इन्होंने 5196 ट्रांसफारमर्स वितरण करने के बारे में कहा है, मैं इनसे यह जानना चाहता हूँ कि इनमें से कितने पुराने जले हुए ट्रांसफारमर्स की जगह नए लगाए गए हैं और कितने नये ट्रांसफारमर्स नई जगह पर लगाए गए हैं।

श्री राम पाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहता हूँ कि जहां ओवर लोड था वहाँ पर ये नए ट्रांसफारमर्स लगाए गए हैं। इनमें पुराने ट्रांसफारमर्स की कोई बात नहीं है। ये ट्रांसफारमर्स एडीशनल लगाए गए हैं।

Spurious Seeds

***839. Shri Krishan Lal** : Will the Minister for Agriculture be pleased to state whether any sample of suprious agricultural seeds have been taken in the State during the period from 1st July, 1996 to 23rd June, 1999 and from 24th June, 1999 to 31st March, 2001; if so, the details thereof together with the action taken in this regard ?

कृषि मंत्री (सरदार जसविन्द्र सिंह सन्धू) : अपेक्षित सूचना विधानसभा के पटल पर प्रस्तुत की जाती है।

सूचना

बीज की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु बीजों के नमूने नियमित रूप से लिये जाते हैं। एक जुलाई, 1996 से 23 जून, 1999 तक की अवधि में बीजों के कुल 6096 नमूने लिये गये, जिनमें से 331 नमूने निम्न स्तर के पाये गये। 24 जून, 1999 से 31 मार्च, 2001 तक बीजों के कुल 4289 नमूने लिये गये और विश्लेषण उपरान्त 224 नमूने निम्न स्तर के पाये गये।

निम्न स्तर के सभी 555 नमूनों से सम्बन्धित दोषी बीज विक्रताओं के विरुद्ध कार्यवाही की गई है। 33 मामलों में बीज की बिक्री रोकी गई तथा 58 विक्रेताओं के लाइसैंस रद्द किये गये। 32 बीज विक्रेताओं के विरुद्ध न्यायालय में केस दायर किये गये जिनमें से 9 केसों का निर्णय हो चुका है तथा 23 मामले अभी भी न्यायालयों में लम्बित हैं। 425 मामलों में जहां पर निर्धारित न्यूनतम बीज मानकों की तुलना में मामूली कमी पाई गई, उन विक्रेताओं को चेतावनी दी गई । शेष बचे 7 निम्न स्तर के नमूनों में से 2 नमूने बीज विक्रेताओं/उत्पादकों की प्रार्थना पर तथा 5 नमूने विभाग के पुराने मिनिकिट बीज से गुणवत्ता जांचने हेतु लिये गये थे जिस पर कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की जानी थी।

श्री कृष्ण लाल : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मंत्री जी ने सवाल के जवाब में उत्तर दिया है कि निम्न स्तर के सभी 555 नमूनों से सम्बन्धित दोषी बीज विक्रेताओं के विरुद्ध कार्यवाही की गई है। 33 मामलों में बीज की बिक्री रोकी गई तथा 58 विक्रेताओं के लाइसैंस रद्द किए गए। 32 बीज विक्रेताओं के विरुद्ध न्यायालय में केस दायर किए गए जिनमें से 9 केसों का निर्णय हो चुका है तथा 23 मामले अभी भी न्यायालयों में लम्बित हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले मंत्री महोदय से पूछना चाहूँगा कि जो 555 नमूने दोषी पाए गए हैं उनमें से कौन-कौन सी फसलों के सैम्पल लिए गए हैं, 33 मामलों में बीज की बिक्री पर रोक लगाई गई है उन कम्पनियों के नाम क्या-क्या हैं, जिन 9 केसिज में कोर्ट का फैसला हुआ है उसमें कोर्ट ने किसके हक में क्या फैसला किया है और जो 58 लाइसैंस रद्द किए गए हैं उन कम्पनियों के नाम क्या-क्या हैं।

सरदार जसविन्द्र सिंह सन्धू : अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी ने सबसे पहले यह पूछा है कि किन-किन फसलों के नमूने भरे गए हैं, वह लिस्ट तो लम्बी है आपकी इजाजत से मैं पढ़कर सुना देता हूँ।

1 जुलाई, 1996 से 31 मार्च, 2001 की अवधि में लिए कुल नमूनों तथा निम्न स्तर के नमूनों का फसलवार विवरण निम्न प्रकार से है :-

(नमूने संख्या में)

फसल	1-7-96 से 31-3-97	1-4-97 से 31-3-98	1-4-98 से 31-3-99	1-4-99 से 31-3-2000	1-4-2000 से 31-3-2001
1	2	3	4	5	6
कपास	27	262	156	408	280
मूंग	1	25	16	21	15
धान	57	209	152	317	355
ज्वार	19	118	61	73	38
गुआर	2	3	1	5	14
अरहर	5	27	4	10	14
बाजरा	304	328	431	264	240
उड़द	2	3	1	2	5
मक्का	10	12	10	3	9
सरसों	600	383	277	183	192
चना	31	13	5	11	20
बरसीम	9	17	11	5	15
गेहूँ	332	451	599	852	967
मटर	9	6	4	1	1
जौं	12	2	10	5	13
सूरजमुखी	98	87	90	11	18

[सरदार जसविन्द्र सिंह सन्धू]

1	2	3	4	5	6
सब्जियां	221	284	130	65	—
जई	1	—	—	—	—
तिल	—	3	1	—	1
ढैंचा	—	1	—	—	1
मसर	—	1	—	2	2
योग	1740	2235	1959	2238	2213
निम्न स्तर	63	80	130	168	114

सर, 1-7-96 से लेकर 31-3-99 तक 5934 नमूने भरे गए और 1-4-99 से लेकर 31-1-2002 तक 6815 नमूने भरे गए हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरे साथी ने दूसरा प्रश्न यह भी किया कि जिन 9 मामलों में फैसला हुआ है उसके बारे में भी विस्तार से बताया जावे। मैसर्ज एच.डी.सी. कलानौर, रोहतक को डिसचार्ज्ड ड्यू टू लिमिटेशन पीरिवड किया गया। अमरजीत सिंह एण्ड संज पटौदी को 28-7-97 को सी.जी.एम. कोर्ट की तरफ से फाइन किया गया। तंवर ट्रेडिंग कारपोरेशन, भिवानी को 21-11-2000 को डिस्चार्ज किया गया। लक्ष्मी एग्रो स्टोर, भिवानी को भी 8-6-2000 को डिस्चार्ज किया गया। कृष्ण चन्द बीज भण्डार, भिवानी को डिस्चार्ज ओन दी ग्राउंड ऑफ रिटैस्टिंग किया गया। ग्रहलाद राय कृष्ण कुमार, भिवानी को भी 9-8-97 को रिटैस्टिंग फाउंड पास किया गया। विकास बीज भण्डार, डिगवां, भिवानी को 500 रुपये जुर्माना किया गया। अशोक कुमार को भी 1000 रुपये फाइन किया गया। हिन्दुस्तान एग्रीकल्चर जिन्टैक्स आर.एम.एच.डी.सी., उमरी को भी 5 हजार रुपये पर एकड़ के हिसाब से 4 शिकायतों के विरुद्ध 35000 रुपये फाईन किया गया।

श्री कृष्ण लाल : स्पीकर साहब, मंत्री जी ने अपने लिखित रिप्लाई में बताया है कि 33 मामलों में बीज की बिक्री रोकी गई तथा 58 विक्रेताओं के लाइसैंस रद्द किये गए। कृपया मंत्री जी जिन 33 मामलों में बीज की बिक्री पर रोक लगाई गई है उनके तथा जिन 58 विक्रेताओं जिनके लाईसेंस रद्द किए गए हैं, उनके नाम भी बताने का कष्ट करें।

सरदार जसविन्द्र सिंह सन्धू : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने अपने मूल सवाल में जो दो बातें पूछी थी उनका मैंने जवाब दे दिया। यदि ये इनका नाम पूछना चाहते हैं तो इसके लिए अलग से नोटिस दे दें।

श्री पूर्ण सिंह डाबड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि आज दिन-प्रतिदिन नई-नई सीड प्रोडक्शन की कम्पिनयां आ रही हैं जिससे किसानों का बड़ा भारी नुकसान हो रहा है क्योंकि ये कम्पिनयां अन सर्टिफाईड बीज बेचती चली जा रही हैं। मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ऐसी कम्पिनयों के खिलाफ सरकार क्या कदम उठा रही है ?

सरदार जसविन्द्र सिंह सन्धू : अध्यक्ष महोदय, किसानों को सर्टिफाईड बीज मिल रहा है, नकली बीज नहीं मिल रहा। मैं अपने साथी सदस्य को बताना चाहता हूं कि सरकार इस बारे में पूरी तरह से फिकरमन्द है। इस बात का यही सबूत है कि हर साल हमारा उत्पादन पहले से बहुत ज्यादा बढ़ रहा है।

श्री भागी राम : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में बताया है कि 32 व्यक्तियों के

विरूद्ध न्यायालय में केस दर्ज हुआ है और इनमें से 9 का फैसला हो गया है और 23 मामले अभी भी विचाराधीन हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जिन 9 केसों में कोर्ट का फैसला हो गया है या जो 23 मामले कोर्ट में लम्बित हैं क्या वे अब भी बीजों की दुकान कर रहे हैं या नहीं कर रहे।

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू : अध्यक्ष महोदय, जिन के खिलाफ कोर्ट में मामला लम्बित है उन सबके लाइसैंस रद्द किए हुए हैं। जिनका मामला कोर्ट में पैण्डिंग है, उनका कोर्ट का फैसला आने पर ही सरकार कोई फैसला लेगी।

श्री भगवान सहाय रावत : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो लोग नकली बीज बेचते हैं या नकली खाद बेचते हैं और जिनके खिलाफ कोर्ट से जुर्माने होते हैं उनको ब्लैक लिस्ट करके सरकार उनकी पब्लिसिटी करेगी ताकि किसान ऐसे लोगों के बारे में जान सकें तथा जो फार्मरज सैंटर्ज है वहां पर और बी.डी.ओ. सैंटर्ज हैं वहां पर इस तरह की जानकारी उपलब्ध करवाने का कोई प्रावधान होना चाहिए ताकि किसान उनसे दोबारा बीज न खरीदें और सावधानी बरत सकें।

सरदार जसविन्द्र सिंह सन्धू : अध्यक्ष महोदय, जिस भी बीज व्यापारी के खिलाफ मुकद्दमा दर्ज हो जाता है और उसको अदालत से सजा हो जाती है तो दोबारा उसको लाइसैंस नहीं दिया जाता है। उस मामले में हमारा जो क्राईटीरिया होता है उसमें कम से कम 85% जर्मिनेशन होना जरूरी होता है। यदि किसी केस में 83 या 84% आ जाए तो पहली बार वार्निंग दे दी जाती है लेकिन बार-बार नहीं होना चाहिए। इससे कम जर्मिनेशन होने पर हम उसका लाइसैंस तुरन्त रद्द करते हैं और दोबारा उसको लाइसैंस भी नहीं देते हैं।

श्री अध्यक्ष : कृषि मन्त्री जी, मान लीजिए बाप की दुकान का लाईसैंस कैंसल हो जाता है और उसी दुकान में अगर उसका बेटा लाइसैंस लेता है तो क्या आप उसको परमिट करेंगे ?

सरदार जसविन्द्र सिंह सन्धू : अध्यक्ष महोदय, अगर कोई दुकान है और किराये पर है और किरायेदार बदलता है या दूसरी फर्म वहां पर काम करने को तैयार हो जाए तो आज उसको रोकने का कोई प्रावधान नहीं है।

राव इन्द्रजीत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल, जो सवाल पूछा गया है उससे डायरैक्टली सम्बन्धित तो नहीं है लेकिन चिन्ता का विषय है इसलिए मैं आपकी इजाजत से इस बारे माननीय मन्त्री महोदय से जानकारी चाहूँगा।

श्री अध्यक्ष : राव साहब, आप सम्बन्धित सवाल ही पूछें।

राव इन्द्रजीत सिंह : स्पीकर सर, मेरा सवाल सीड से सम्बन्धित ही है। अध्यक्ष महोदय, सीड बाहर से आता है और सर्टिफाईड सीड के तौर पर हाई यील्डिंग वैरायटी उनको कहा जाता है और उसको प्रोपेगेट करते हैं और बहुत से लोग तो उसके बाद उसको सीड के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। स्पीकर सर, जो हाई यील्डिंग वैरायटीज हैं उनको लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और जो हमारी डोमैस्टिक सीड है जैसे कि हम गेंहूँ की फसल बोयें उसकी थोड़ी बहुत फसल हम रख लें ताकि उसको सीड के तौर पर इस्तेमाल कर लें। यह आज के दिन तो प्रिवेलेंट है लेकिन जो सीड बाहर से आता है उसका रिजर्मिनेशन बहुत कम होता है या नहीं हो पाता है। इस सीड का इस्तेमाल करने के साथ-साथ हम इसी सीड पर निर्भर हो जाते हैं उस विदेशी सीड के ऊपर जो हमारे देश के अन्दर और प्रदेश के अन्दर आ रहा है। (विघ्न) स्पीकर सर, मेरा क्वैश्चन यह है कि हमारा किसान या जमींदार जिस सीड के ऊपर निर्भर होता जा रहा है और यह शंका है कि आने वाले समय के अन्दर सारा सीड हमारे देश के अन्दर और प्रदेश के अन्दर इस्तेमाल में आ जाए और हम विदेशी सीड पर मल्टीनैशनल सीडस कम्पनीज के ऊपर निर्भर न हो जाएं

[राव इन्द्रजीत सिंह]

इसके लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ताकि जो सिलसिला अब चल रहा है वह खत्म हो जाए, क्या सरकार इसके लिए चिन्तित है ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सारे हाउस को अवगत करवाना चाहूँगा कि सरकार की हरचन्द यह कोशिश है कि किसान को अच्छा सीड मिले। इसके लिए हमने अपनी सीडस कारपोरेशन से सब किस्म के सीडस तैयार करते हैं लेकिन कई दफा कुछ किसान जो अपने आप को प्रोग्रैसिव फारमर्ज कहते हैं विदेशी मल्टीनेशनल कम्पनीज से, जिन पर हम पाबन्दी नहीं लगा सकते, क्योंकि इनकी सरकार के समय में लिब्रेलाईजेशन की आड़ लेकर उनको छूट दे दी गई और कुछ ऐसी कम्पनियां भी बन गई जो केवल व्यापारिक दृष्टि से कम्पनीज खोल लेते हैं लेकिन जहां कहीं भी ऐसी कोई शिकायत मिलती है और इन्क्वायरी करने पर वह कसूरवार पाया जाए तो उसे ब्लैकलिस्ट करते हैं तथा ब्लैकलिस्ट कम्पनी को फिर दोबारा सीड बेचने की अनुमति नहीं हो सकती है। स्पीकर सर, फिर भी हम कोशिश करेंगे जहां कहीं से कोई शिकायत आएगी हम फौरन उस पर ऐक्शन लेंगे और किसान को अच्छे से अच्छा सीड उपलब्ध करवाने का हर सम्भव प्रयास करेंगे। (विघ्न)

Construction of Roads

***1009. Shri Ranbir Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state --

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct the following roads of district Bhiwani :-

(i) from Pichopa Kalan to Siswala ;

(ii) from Gopalwas to Tilauri ;

(iii) Balkara to Kalali;

(iv) Dandama to Sirsali;

(v) Haraudi to Kalanwala ; and

(b) if so, the time by which the aforesaid roads are likely to be constructed ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) :

(क) हाँ, श्रीमान जी, उपरोक्त क्रमांक (ii) पर सड़क को छोड़कर।

(ख) यह दर्शाना सम्भव नहीं है कि क्रमांक (i), (iii), (iv) और (v) पर सड़कों का कब तक निर्माण हो जायेगा।

श्री रणबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्री जी का और मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इन्होंने नम्बर 1, 3, 4 और 5 की सड़कों को मन्जूरी दे दी है। जहां तक नम्बर 2 वाली सड़क का सवाल है तो माननीय अध्यक्ष महोदय, गोपालवास से तौलौरी की ढाणी को यह सड़क जाती है। इससे बाढ़डा, लोहारू और महेन्द्रगढ़ ये तीन विधान सभा क्षेत्र जुड़ते हैं। इसके साथ ही 2 जिलों के आवागमन का रास्ता भी खुलता है इसलिए मैं सी.पी.एस. साहब से कहना चाहूँगा कि सरकार इस सड़क को दोबारा से बनाने के बारे में विचार करें।

मुख्य संसदीय सचिव (श्री राम पाल माजरा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना

चाहूँगा कि जब हमारी सरकार ने सत्ता सम्भाली तो हरियाणा में सड़कों का ताना-बाना पूरी तरह से तहस-नहस था। सड़कों पर बड़े-बड़े खड्डे थे। उस वक्त नई सड़कें बनने की कोई योजना नहीं थी। आज हरियाणा प्रदेश ने इस सरकार के द्वारा मार्किटिंग बोर्ड के तहत रिमार्केबल नई सड़कें बनाने का काम किया है और हरियाणा बनने के बाद यह पहली बार हुआ है। मेरे साथी ने यह पूछा है कि यह सड़क बनेगी या नहीं बनेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन में यह बताना चाहूँगा कि पिछली सरकार के वक्त जब हम यहां पर प्रश्न पूछा करते थे तो उसका जवाब न में आता था। आज मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में यह हुआ है कि पिछली सरकार के वक्त में जो जवाब न में आते थे वे अब हाँ में आते हैं। इन सड़कों का जवाब जो मैंने हाँ में दिया है और मेरे माननीय साथी ने उसके लिए धन्यवाद भी किया है तो मैं इनको यह बताना चाहूंगा कि इन सड़कों पर काम एक साल में पूरा कर दिया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, वहां पर मिट्टी का काम होगा, अर्थवर्क का काम होगा वहां पर एक लेयर, दो लेयर और तीसरी लेयर पड़ेगी। यह काम बहुत ही लम्बा होता है और इस पर बहुत ज्यादा खर्चा होने जा रहा है। मैं अपने साथी रणबीर सिंह जी को बताना चाहूँगा कि इतना काम होने जा रहा है। हमारे हरियाणा प्रदेश में बहुत विकास के काम हुए हैं। मैं चौधरी भजन लाल जी को बताना चाहूँगा कि मेरे पास एक किताब है और यह हरियाणा के विकास की पौथी है अगर मैं इसको यहां पर पढ़कर सुना दूं तो आप कह देंगे कि आपको इस पर पूरा-पूरा विश्वास है और आप इससे सन्तुष्ट हैं। इस किताब में हरियाणा की एक-एक कांस्टीचुएंसी का अगला प्रोग्राम है कि अगले एक साल में कहां-कहां पर क्या-क्या होने जा रहा है और पीछे क्या हुआ था ? जो काम हो रहे हैं उसकी असैसमैंट भी साथ-साथ हो रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं इनको बताना चाहूँगा कि सिर्फ कहने से ही काम नहीं होता है, काम किए जा रहे हैं और हर काम जो हो रहा है या नहीं हो रहा है उनकी असस्मैंट भी हो रही है, उनकी मोनिटरिंग भी हो रही है। अध्यक्ष महोदय, यह विकास की पौथी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के नेतृत्व में विशेष तौर पर P.W.D. से आज मैं लेकर आया हूँ। अगर विपक्ष के नेता मुझे इजाजत दें तो मैं आपके समक्ष इसको रख दूं और सदन में इसको पढ़कर सुना दूं, अगर नहीं, तो जो माननीय साथी ने 5 सड़कों के बारे में पूछा है उनके बारे विशेष जानकारी सदन में दूं। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, जो पहली सड़क है वह 5.33 किलोमीटर लम्बी है और उस पर लागत 32 लाख 55 हजार आएगी। इसी के साथ जो दूसरी सड़क बलकरा से कलाली तक 7.70 किलोमीटर है लगभग पौने आठ किलोमीटर और इस पर सरकार का खर्चा 43 लाख 44 हजार रुपये आएगा। इसके अलावा डांडमा से सिरसली सड़क 3.30 लाख रुपए की बनेगी और इसी प्रकार अगली सड़क हड़ौदी से कालुंवाला पर 9 लाख रुपये खर्च होंगे। अध्यक्ष महोदय, ये सड़कें एक वर्ष में पूरी हो जाएंगी।

श्री रमेश कुमार खटक : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि हमारी सरकार के आने के बाद कितनी सड़कें P.W.D. के द्वारा मंजूर की गई हैं और कितनी सड़कों पर काम किया गया है। इसके अलावा कितनी सड़कें मार्किटिंग बोर्ड द्वारा बनाई गई हैं। जो सड़कें बनी इन सब सड़कों पर पर-किलोमीटर के हिसाब से कितना-कितना खर्चा आया है ?

श्री राम पाल माजरा : स्पीकर सर, मैं माननीय साथी को बताना चाहूँगा कि एक किलोमीटर की सड़क पर लगभग 8 लाख रुपये खर्च होते हैं। हरियाणा प्रदेश में 29085 किलोमीटर लम्बी सड़कें हैं। इसमें राष्ट्रीय उच्च मार्ग 1346 किलोमीटर हैं, राज्य स्तर के मार्ग 2461 किलोमीटर, मुख्य जिला सड़कें 17582 किलोमीटर लम्बी हैं और कृषि विपणन बोर्ड की 6125 किलोमीटर सड़कें हैं। अगर ये यह भी पूछना चाहते हैं कि P.W.D. की सड़कों पर कितना काम हुआ है और मार्किटिंग बोर्ड से सड़कों पर कितना काम हुआ है तो अध्यक्ष महोदय, मेरे पास वहां पर दो बड़ी-बड़ी पौथियां हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं इनको पढ़कर सुना देता हूँ। इसके साथ ही मैं आपके माध्यम से विपक्ष के नेता की भी इनको पढ़ने की इजाजत चाहूँगा। (शोर एवं व्यवधान) इस बारे में माननीय साथी रमेश खटक जी ने पूछा है। (शोर एवं व्यवधान)

चौधरी जय प्रकाश : स्पीकर सर, बरवाला शहर में कोई सड़क किसी फेज में नहीं बनी है वहां की सारी

[चौधरी जय प्रकाश]
सड़कें टूटी पड़ी हैं। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : आप सभी बैठें। (विघ्न)

श्री राम पाल माजरा : स्पीकर सर, मेरे साथी जय प्रकाश जी ने पूछा है। इनकी समझ थोड़ी सी कम है इसलिए मैं इनको बताना चाहता हूँ कि पहले फेज, दूसरे फेज और तीसरे फेज सड़कों के बनाने के लिए रखे गये हैं। पहले फेज का काम पूरा हो गया है और दूसरे फेज का काम इसी महीने शुरू कर दिया जाएगा। स्पीकर सर, आपने देखा होगा कि पहले फेज में जितनी सड़कें बनायी गयीं या मरम्मत की गयी, वह सब अच्छी की गयी, बेहतरीन की गयी। स्पीकर सर, हरियाणा की जनता इस बात की गवाह है कि यमुनानगर के इलैक्शन में उसने चाहे बिजली की बात हो, पी.डब्ल्यू.डी. की बात हो, नहरों की बात हो या मार्केटिंग बोर्ड द्वारा सड़कें बनाने की बात हो, सब पर मोहर लगायी है। हरियाणा की जनता ने विकास पर मोहर लगाकर डॉ. गम्भीर को हजारों वोटों से जिताया है और इन भाइयों को तीसरे नम्बर पर पहुँचाया है। (विघ्न) स्पीकर सर, हरियाणा की जनता ने विकास के ऊपर मोहर लगायी है। ये लोग तो सुनना नहीं चाहते। (विघ्न) जब इस सरकार ने हरियाणा में सत्ता संभाली थी उस समय सड़कों की क्या पोजीशन थी और आज सड़कों की क्या पोजीशन है, यह हरियाणा की जनता खुद जानती है। स्पीकर सर, डॉ. गंभीर ने इनको तो तीसरे स्थान पर पहुंचा दिया है। इनको याद होगा कि यमुनानगर के इलैक्शन में इनके साथ क्या हुआ था। **(इस समय कई माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े हो गए)**

श्री अध्यक्ष : आप सभी बैठें। अब राठी साहब अपनी सप्लीमैंट्री पूछेंगे।

चौधरी नफे सिंह राठी : स्पीकर सर, यह बात ठीक है कि हरियाणा में बहुत बढ़िया सड़कें बनायी गयी हैं और हरियाणा में विकास के कार्य बहुत तेजी से चल रहे हैं। स्पीकर सर, हम तो दिल्ली के बोर्डर पर बसते हैं वहां पर कई रास्ते ऐसे हैं जो दिल्ली को जाते हैं। जब हम दो साल पहले दिल्ली जाते थे तो दिल्ली साईड की सड़कें बढ़िया होती थीं और हमारी साईड की सड़कों में गड्ढे होते थे लेकिन अब हमारी तरफ की सड़कें बढ़िया हैं और उनकी तरफ की सड़कों में गड्ढे हैं। मैं आपके माध्यम से सी.पी.एस. साहब से जानना चाहूंगा कि जो सड़कें पी.डब्ल्यू.डी. से ट्रांसफर होकर मार्केटिंग बोर्ड के पास आयी हैं उन पर पहले काम शुरू भी हो गया था लेकिन उनकी छोटी-मोटी रिपेयर का कार्य अब कौन सा डिपार्टमैंट करवाएगा ?

श्री राम पाल माजरा : स्पीकर सर, काफी सड़कों की रिपेयर का काम मार्केटिंग बोर्ड द्वारा करवाया गया है। जितनी भी सड़कें उन्होंने टेकअप की थीं उन पर रिपेयर का काम पूरा कर दिया गया है फिर भी अगर कहीं कोई सड़क रह गयी होगी तो उसके ऐस्टीमेटस वगैरा नहीं पहुंचे होंगे इसलिए उसकी रिपेयर नहीं हो पायी होगी। स्पीकर सर, मैं मांगेराम जी को बताना चाहता हूँ कि जींद जिले में जब इनका राज था, जब ये 1991 से लेकर 1996 तक मंत्री थे उस समय मार्केटिंग बोर्ड द्वारा 6.86 किलोमीटर ही सड़कें नयी बनायी गयी थी। इसके लिए ही ये अपने आपको तीस मारखां वित्त मंत्री कहते हैं। जबकि इस सरकार के समय में वहां 31 किलोमीटर नयी सड़कें बनायी गयी हैं। (विघ्न) इन पर एक करोड़ 81 लाख रुपये लगे हैं। स्पीकर सर, मैं इनको केवल बानगी के तौर पर यह बता रहा हूँ।

Water works of Bawwa Village

*** 953. Smt. Anita Yadav :** Will the Chief Minister be pleased to state whether Govt. is aware of the fact that water works of village Bawwa, Distt. Rewari has been completed since long and the pipe has also been laid in the village ; if so the time by which the said water works is likely to

be made functional ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : जी हाँ, श्रीमान् ; गांव बब्बा का जल घर पहले ही चालू है।

श्री अध्यक्ष : आनरेबल मैम्बर्ज, अब प्रश्न काल समाप्त होता है।

नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Widening of the Faridabad-Badarpur National Highway

*1029. **Shri Rajinder Singh Bisla :** Will the Chief Minister be pleased to state--

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to widen the Faridabad-Badarpur (Delhi) National Highway in the State.

(b) whether there is also any proposal under consideration of the Government to complete fly over on the Faridabad-Badarpur National Highway in the State ; and

(c) if so, the details thereof ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) :

(क) नहीं, श्रीमान् जी।

(ख) नहीं, श्रीमान् जी।

(ग) उपरोक्त (क) तथा (ख) पर उत्तर के दृष्टिगत प्रश्न ही नहीं उठता।

Amount spent on the repair of National Highways

*946. **Shri Ram Phal Kundu :** Will the Chief Minister be pleased to state the details of the amount spent on the repair and upgradation of National Highways in the State during the last two years ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : राष्ट्रीय राजमार्गों का दर्जा बढ़ाने के लिये 92.43 करोड़ रुपये तथा 102.53 करोड़ रुपये और मरम्मत पर 16.10 करोड़ रुपये और 19.69 करोड़ रुपये क्रमशः वर्ष 1999-2000 तथा 2000-2001 में खर्च किए गए थे।

Road constructed under Prime Minister Road Plan

*940. **Dr. Raghuvir Singh Kadian :** Will the Chief Minister be pleased to state the total length of roads in kilometers constructed under Prime Minister Road Plan during the last two & half years in Beri Constituency ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत 15 अगस्त, 2000 से जब से यह योजना शुरू हुई है, बेरी निर्वाचन क्षेत्र में कोई नई सड़क नहीं बनाई गई है।

Rewari Lift Irrigation Scheme

***961. Sh. Rambir Singh :** Will the Chief Minister be pleased to State the time by which the Rewari Lift Irrigation Scheme will be completed together with the area which will be benefitted therefrom ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : रेवाड़ी उठान सिंचाई योजना पर कार्य 31-3-2003 तक पूरा होने की सम्भावना है। इस योजना से 37352 हैक्टेयर क्षेत्र लाभान्वित होगा।

Number of persons registered with Employment Exchanges

***824. Capt. Ajay Singh Yadav :** Will the Chief Minister be pleased to state :

(a) the number of unemployed persons registered with the employment exchanges in the State during the year 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000 and 2000-2001 to date ; and

(b) the number of persons out of those referred to in part (a) above have been given employment during the said period in Government and Private Sectors separately.

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) :

(क) तथा (ख) : श्रीमान्, सूचना सदन के पटल पर रखी जाती है।

सूचना

(क)

वर्ष	वर्ष के दौरान पंजीकृत प्रार्थियों की संख्या
1997-1998	2,54,755
1998-1999	2,93,818
1999-2000	2,73,423
2000-2001	2,34,108
1-4-2001 से 31-1-2002	1,64,687

(ख) राज्य के रोजगार कार्यालयों द्वारा सरकारी क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र में सजीव रजिस्टर पर दर्ज प्रार्थियों में से रोजगार पर लगवाये गये प्रार्थियों की अलग-अलग संख्या निम्न अनुसार है :

वर्ष	सरकारी क्षेत्र	निजी क्षेत्र	कुल
1997-1998	5682	14285	19967
1998-1999	3705	9880	13585
1999-2000	1311	4142	5453
2000-2001	1261	4179	5440
1-4-2001 से 31-1-2002	527	3887	4414

Repair/Widening of Roads

*1005. **Smt. Sarita Narain :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the road from Kalanaur to Pilana is in dilapidated condition ; if so, the time by which it is likely to be repaired ;

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government to widen the following roads of Kalanaur Constituency :—

(i) Kalanaur to Nigana;

(ii) Dobh-Balb Marodi;

(iii) Chimani and Kalanaur to Pilana ; and

(c) if so, the details thereof, togetherwith the time by which these roads are likely to be widened ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) :

(क) नहीं श्रीमान् जी, सड़क यातायात योग्य है। फिर भी वर्ष 2002-03 में इस सड़क की मरम्मत और मजबूत करने का प्रस्ताव है।

(ख) (i), (ii) तथा (iii) हाँ, श्रीमान् जी।

(ग) इन सड़कों की 37.04 कि.मी. लम्बाई को पर्याप्त धन की उपलब्धता के आधार पर 31-3-2004 तक चौड़ा करने की संभावना है।

Setting of Sub-Station at Chang & Bhiwani

*1027. **Shri Shashi Parmar :** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a 33 K.V. Sub-station at village Chang in Mundhal Constituency and 132 K.V. Sub-Station in Bhiwani City ; if so, the details thereof ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : हाँ श्रीमान्, गांव चांग में एक 33 के.वी. उपकेन्द्र 1.10 करोड़ रुपये की लागत से निर्माण करने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है। औद्योगिक क्षेत्र भिवानी में एक नया 132 के.वी. उपकेन्द्र तथा सम्बन्धित प्रसार लाइनों का 4.62 करोड़ रुपये की लागत से निर्माण करने का कार्य पहले ही शुरू किया गया है। कार्य को टर्न की आधार पर निर्माण करने के लिए नियतन किया गया है।

Laying of Sewerage in Ratia

*1034. **Shri Jarnail Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of Govt. to provide sewerage system in Ratia City ; if so, the details thereof ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : नहीं श्रीमान् जी। प्रश्न ही नहीं उठता।

Judicial Complex, Tohana

*1038. **Sardar Nishan Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Govt. to construct a Judicial Complex at Tohana ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : जी हाँ।

Sewerage in Narnaund

*1025. **Prof. Ram Bhagat :** Will the Chief Minister be pleased to state the time by which the sewerage work in village Narnaund in Narnaund Constituency is likely to be completed ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : नारनौंद में सीवरेज का कार्य मार्च, 2003 तक कमीशन किये जाने की संभावना है।

Construction of National Highway, Panipat-Jhajjar

*936. **Shri Shadi Lal Batra :** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any porposal under consideration of the Government to construct National Highway from Panipat to Jhajjar via Rohtak and Jhajjar to Rewari?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : पानीपत से झज्जर वाया रोहतक तथा झज्जर से रिवाड़ी सड़कें पहले ही राष्ट्रीय राजमार्ग हैं।

Construction of Grain Market, Hodel

*957. **Shri Udai Bhan** : Will the Minister for Agriculture be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a new modern grain market in the Hodel City in district Faridabad ; and

(b) if so, the time by which it is likely to be constructed ?

कृषि मंत्री (सरदार जसविन्द्र सिंह सन्धू) : (क) व (ख) होडल शहर में नई अनाज मंडी बनाने बारे प्रस्ताव की प्रारम्भिक जाँच चल रही है। अत: इस समय कोई समय-सीमा नहीं बताई जा सकती।

Vridh Aashram

*1030. **Sh. Ram Kumar Nagura :** Will the Minister of State for Social Welfare be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Govt. to construct Vridh Aashram in villages Rajaund & Aleva in Rajaund Constiuency, if so, the detail thereof ?

समाज कल्याण राज्य मंत्री (श्री रिसाल सिंह) : नहीं, श्रीमान् जी।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव—

फरीदाबाद इत्यादि क्षेत्र में निजी स्कूलों की अत्याधिक वृद्धि सम्बन्धी—

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I have received a calling attention notice from Shri Rajinder Singh Bisla, M.L.A. regarding the mushroom growth of Private Schools in the area of Municipal Corporation, Faridabad etc. I admit it. Shri Rajinder Singh Bisla, M.L.A., may read his notice.

श्री राजेन्द्र सिंह बिसला : मैं इस महान् सदन का ध्यान नगर निगम, फरीदाबाद के क्षेत्र में प्राइवेट स्कूलों

के थोड़े समय में बहुत बढ़ जाने व इन स्कूलों में विद्यार्थियों के दाखले भी अत्याधिक दरों पर होने के संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथा अत्यावश्यक विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ। ये प्राइवेट स्कूल सरकारी एजेंसियों से मार्किट में ऐसी भूमि की प्रचलित कीमत की तुलना में, बहुत सस्ती दर पर भूमि प्राप्त कर लेते हैं। इन निजी स्कूलों के प्रबन्धकों द्वारा दाखलों तथा स्कूल फीस इत्यादि-इत्यादि अत्यधिक दरों पर वसूल करके जनता का शोषण किया जा रहा है क्योंकि ऐसे स्कूलों के दाखिले के लिए कोई निहित मानदण्ड निर्धारित नहीं किए गए हैं। मैं चाहता हूँ कि सरकार को इस अत्यावश्यक लोक महत्व के विषय की तुरन्त जाँच पड़ताल करनी चाहिए तथा लाभदायक संशोधनात्मक पग उठाए जाने चाहिएं तथा इन स्कूलों में विद्यार्थियों के दाखिले के लिए कुछ मानदण्ड निर्धारित करने चाहिएं। सरकार इस संबंध में सदन के पटल पर एक वक्तव्य देकर अपनी स्थिति स्पष्ट करे।

वक्तव्य-

शिक्षा राज्य मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी-

श्री अध्यक्ष : अब शिक्षा राज्य मंत्री अपना वक्तव्य देंगे।

शिक्षा राज्य मंत्री (चौ. बहादुर सिंह) : नगर पालिका क्षेत्र फरीदाबाद में 373 प्राइवेट तथा 148 सरकारी स्कूल चल रहे हैं केवल 4 विद्यालयों को नगर पालिका फरीदाबाद द्वारा स्थान अलाट किये गये हैं। इनमें से 2 स्थान निर्धारित कीमत पर अलाट किये गये और 2 स्थान नगर पालिका फरीदाबाद द्वारा बाजारी कीमत पर खुली बोली द्वारा अलाट किए गए। हुड्डा द्वारा 72 विद्यालयों को जमीन अलाट की गई है इनमें से 7 अलाटमैंट चालू नीति के अधीन खुली बोली द्वारा अलाट की गई हैं। शेष 65 स्थान भिन्न-भिन्न समय उस समय पर चालू नीति के अधीन निर्धारित कीमत के आधार पर अलाट किये गये। हुड्डा की वर्तमान नीति के अनुसार 50 प्रतिशत विद्यालय स्थान शिक्षा विभाग के लिए आरक्षित हैं जिन्हें 99 वर्ष के पट्टे के आधार पर मात्र 100 रुपये प्रति वर्ष की सामान्य पट्टा शुल्क पर अलाट किये जाते हैं, शेष 50 प्रतिशत स्कूल स्थान प्राइवेट पार्टी (रजिस्टर्ड शिक्षण संस्थान, नियास) को नीलामी के द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर अलाट किये जाते हैं :—

1. कब्जा लेने के 2 वर्ष के अन्दर-अन्दर उन्हें भवन निर्माण करना होगा।
2. यदि भूमि का उपयोग अलाट किये गये उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाता तो भूमि उस पर किये गये निर्माण सहित हुड्डा को वापस चली जायेगी।
3. किसी भी स्थिति में भूमि के स्थानान्तरण की अनुमति नहीं दी जायेगी।
4. विद्यालयों में 10 प्रतिशत सीट समाज के आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए आरक्षित की जायेंगी और ऐसे छात्रों से वही फीस ली जायेगी जोकि राजकीय विद्यालय के छात्रों से ली जाती है इसके अतिरिक्त 10 प्रतिशत सीट उन छात्रों के लिए भी आरक्षित की जायेंगी जिनके बारे में फीस का निर्धारण उनके योग्यता एवं साधनों के आधार पर व्यक्ति विशेष केस में किया जायेगा।

इनमें से बहुत से स्कूल हरियाणा सरकार से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करके केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बन्धता प्राप्त करते हैं। ऐसे विद्यालयों का पाठ्यक्रम, परीक्षा पद्धति तथा प्रशासकीय कार्य केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा दिये गये निर्देशों अनुसार संचालित किए जाते हैं। छात्रों के दाखले बारे अराजकीय बिना अनुदान प्राप्त विद्यालय अपने स्वयं के नार्म का अनुसरण करते हैं। फीस तथा फण्ड प्रबन्धकों द्वारा अपने स्तर पर लिये जाते हैं।

अराजकीय विद्यालयों का समुचित संचालन करने के लिए हरियाणा विद्यालय शिक्षा अधिनियम, 1995

[चौधरी बहादुर सिंह]

दिनांक 4-6-1999 को अधिसूचित किया गया था जिसमें विद्यालयों की मान्यता प्रवेश फीस तथा फण्ड आदि बारे व्यवस्था की गई है। इन प्रावधानों के अन्तर्गत प्रत्येक मान्यता प्राप्त विद्यालय में फीस उस विद्यालय द्वारा प्रदान की जा रही सुविधाओं के अनुरूप ही निर्धारित की जायेगी। इस फीस के अतिरिक्त सरकार से स्वीकृति प्राप्त किये बिना कोई और शुल्क नहीं लिये जायेंगे। विद्यालय शुल्क और अन्य प्रकार की सभी निधियां इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाये जाने वाले नियमों अनुसार ही लिये जायेंगे। इस अधिनियम के अन्तर्गत नियम बनाये जा रहे हैं और इस बारे जिनके द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जनहित को पूर्णत: सुरक्षित रखा जावे। राज्य सरकार द्वारा इन नियमों को बनाने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। आगामी कार्यवाही कमेटी की सिफारिशें प्राप्त होने पर की जायेगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सम्मानित साथी से खासतौर से अनुरोध करना चाहूँगा कि हम इस बारे में रूलज बनाने जा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूँ कि वे अपने सुझाव इस बारे में लिखकर दे दें उनके सुझाव अगर ठीक लगे तो उनका विचार मान लिया जायेगा।

श्री राजेन्द्र सिंह बिसला : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो काल अटैंशन नोटिस आपके माध्यम से इस हाउस में दिया है उसके बारे में मेरी मंशा यह है कि यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। फरीदाबाद नगर निगम का जो क्षेत्र है उसमें इतने कान्वेंट स्कूल और सी.बी.एस.सी. से एफिलिएटिड स्कूल हैं विशेषकर हुडा के सैक्टरों में ये इंस्टीच्यूशंज सस्ते रेट पर जमीन ले लेती हैं और सरकार को यह जमीन देनी पड़ती है। इन इंस्टीच्यूशंज वालों की जहां बिल्डिंग बनाने के बाद सारी की सारी संस्था की 100 प्रतिशत कमर्शियलाइज सोच हो जाती है, व्यापारिक सोच हो जाती है। अध्यक्ष महोदय, आप मेरे इस कथन के साथ सहमति प्रकट करेंगे कि 20-25 साल पहले तब शहरों में इन कान्वेंट स्कूलों की भरमार नहीं थी उस समय गरीब किसान, मजदूर, एस.सी.और बी.सी. परिवारों के बच्चे जो गांवों के हाईस्कूलों से मैट्रिक करने के बाद भी आई.ए.एस., आई.पी.एस., डाक्टर, इंजीनियर और राजनीति में बड़े-बड़े पदों को सुशोभित करते थे। लेकिन आज गांव के और विशेषकर शहरों के सरकारी स्कूलों के बच्चे आगे नहीं आ रहे हैं। इन बच्चों को आगे आने से उन स्कूलों ने रोक दिया है जो पूंजीपति वर्ग की संस्थाओं ने शहर का सारा एरिया कैप्चर कर लिया है। अध्यक्ष महोदय, यह अति चिन्तनीय विषय है और चुनौती सरकार की समझ के सामने है और जब बड़े से बड़े राजनैतिक लोग और सामाजिक संस्था के लोग उनको कहते हैं कि गांव का बच्चा है, किसान परिवार का बच्चा है और मैरिट का बच्चा है तो भी उनको इन शिक्षण संस्थाओं में एडमिशन नहीं दिया जाता है। यह एक बड़ा विशियस सर्कल बन गया है। जो बच्चा 95 परसैंट अंक लेकर आता है उनको इन शिक्षण संस्थाओं में दाखिला दिया जाता है और पैसे के बल पर जिन्होंने एग्जामिनेशन वगैरह के ऊपर कैप्चर कर रखा है उन्हीं के बच्चों के पास किया जाता है। डॉक्टर, इंजीनियर्ज, आई.ए.एस. और आई.पी.एस. और जो समाज के पूंजीपति लोग हैं उन्हीं के बच्चों को ही वहां दाखिला दिया जाता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से और विशेषकर मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इस व्यवस्था को पैसे वालों ने जो कैप्चर कर लिया है, आपके होते हुए मुझे पूरी आशा है कि इस सिस्टम को ठीक कर लिया जाएगा। इन संस्थाओं में जहां किसान, गरीब का बच्चा आ नहीं सकता इस व्यवस्था को ठीक किया जाए और पूंजीपति विशियस सर्कल को तोड़ दिया जाए।

चौधरी बहादुर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने जैसा बताया है कि इस मामले में हम रूल्ज बनाने जा रहे हैं उसमें ये लोग भी अपने सुझाव दें ताकि इसमें खास तौर से ध्यान दिया जा सके। अध्यक्ष महोदय, मैं इनके फरीदाबाद के एक गांव में एक स्कूल में गया था, वह एक क्रिश्चयन स्कूल है। उस स्कूल का बड़ा अच्छा स्टैंडर्ड था। उस स्कूल में 700 बच्चे थे और 700 बच्चों में से 650 बच्चे गरीब थे। इसलिए यह बात नहीं है कि गरीब बच्चों को एडमिशन नहीं मिलता है। लेकिन एडमिशन और फीस के रूलज बनाने के बाद इसको ठीक तरीके से चलाएंगे और उसमें इनका सहयोग जरूरी है, ये अपने सुझाव दें, मेरे विचार में केवल सवाल पूछने से बात नहीं बनती। इनके सुझाव

आएंगे और उन पर विचार करके हम उसको मानने की कोशिश करेंगे।

श्री राजेन्द्र सिंह बिसला : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो निवेदन किया है लगता है आदरणीय मंत्री जी मेरी भावनाओं को समझ नहीं पाए। आज मैरिट जैसी चीज नहीं रही है। बैक डोर से दाखिले हो रहे हैं। मंत्री जी जिस स्कूल का जिक्र कर रहे हैं, यह ठीक है कि वह स्कूल निश्चित रूप से अच्छा स्कूल है। वह स्कूल देहात के अन्दर है, वहां ज्यादातर बच्चे गांव के हैं इसलिए जो बात इन्होंने की है मैं उसकी ताईद करता हूँ लेकिन जो दूसरे कान्वेंट स्कूलज हैं वहां बकायादा बिना रसीद दिए कई-कई लाख रुपये डोनेशन लिया जाता है। जो समाज का 80 प्रतिशत वर्ग है जो कमाकर खाने वाला वर्ग है, जो अनाज पैदा करता है और जो देश के लिए लड़ता है उनके बच्चों के इन स्कूलों में दाखिले नहीं होते। गांवों की जब जमीनें एक्वायर की जाती हैं तो आश्वासन दिया जाता है कि गांव के बच्चों को इन स्कूलों में एडमिशन दिया जायेगा। उपाध्यक्ष महोदय बैठे हैं ये भी इस ढिल-मुल नीति की वजह से प्रभावित हैं। हमारे प्रयासों के बाद भी साधारण परिवार के इन्टैलीजैंट और मैरिट वाले बच्चों को इन स्कूलों में दाखिला नहीं दिया जाता है। फरीदाबाद में ए.पी.जे.एस. और दिल्ली पब्लिक स्कूल हैं, वहां एक भी गांव के इंटैलीजैंट बच्चे को दाखिला नहीं दिया जाता। पैसे वालों के बच्चों को ही दाखिला मिलता है। कृपया इस धारणा को तोड़कर इस व्यवस्था को ठीक करवाया जाए।

चौधरी बहादुर सिंह : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने बताया कि हम रूल्ज बनाने जा रहे हैं उसमें सारा प्रोवीजन रखेंगे कि कितनी फीस होनी चाहिए, एडमीशन का क्या तरीका होना चाहिए। मैरिट के हिसाब से तो दाखिले चल रहे हैं और वे जारी रहेंगे। बाकि रूल्ज में प्रावधान रखेंगे कि कौन से स्कूल में कितनी फीस होनी चाहिए, उन स्कूलों में दाखिले का क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। ये सारी रूल्ज बनने के बाद समस्या का समाधान हो जाएगा। (शोर एवं व्यवधान)

विभिन्न विषयों का उठाया जाना--

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैंने रूल्ज ऑफ प्रोसीजर एण्ड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन दि लैजीस्लेटिव असैम्बली के रूल 73 ए. के अंडर फीमेल फयोटीसाइड के बारे में शोर्ट डयूरेशन डिस्कशन का नोटिस दिया था। उसके बारे में आपने क्या फैसला दिया है।

श्री अध्यक्ष : कैप्टन साहब, यह डिस अलाउ कर दिया गया है।

सदन की मेज पर रखे गए कागज-पत्र

Mr. Speaker : Now, a Minister will lay the papers on the Tabie of the House.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh) : Sir, I beg to lay on the table --

The Education and Langauges Department notification No. S.O. 38/H.A. 12/1999/Ss. 8 and 24/2001 dated the 29th March, 2001, regarding Haryana Aided Schools (Special Pension and Contributory Provident Fund) Rules 2001, as required under section 24(3) of Haryana School Education Act, 1995.

The Audit Report on the Accounts of Haryana Financial Corporation for the year ended 31st March 2000, as required under section 619-A(3) (b) of the Companies Act, 1956.

[Prof. Sampat Singh]

The Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year ended 31st March, 2001 (Civil) of the Govt. of Haryana in pursuance of the provisions of clause (2) of Article 151 of the constitution of India.

The Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year ended 31st March, 2001 (Revenue Receipts) of the Government of Haryana in pursuance of the provisions of clause (2) of Article 151 of the Constitution of India.

The Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year ended 31st March, 2001 (Commercial) of the Government of Haryana in pursuance of the provisions of clause (2) of Article 151 of the Constitution of India.

वर्ष 2002-2003 के लिए बजट पर चर्चा (पुनरारम्भ)

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now general discussion on the budget for the year 2002-2003 will be resumed. जैसा कि आप जानते हैं कि बजट पर बोलने के लिए 9 घंटे का समय रखा गया है और विभिन्न पार्टियों को उनकी स्ट्रैंथ के हिसाब से समय निर्धारित किया गया था। कांग्रेस पार्टी के लिए 120 मिनट, बी.जे.पी. के लिए 36 मिनट, इण्डियन नेशनल लोकदल के लिए 282 मिनट, हरियाणा विकास पार्टी के लिए 12 मिनट और एम.सी.पी. व आर.पी.आई. के लिए 18 मिनट का समय रखा था तथा निर्दलीय उम्मीदवारों के लिए 66 मिनट का समय रखा गया था। कांग्रेस की तरफ से मांगे राम गुप्ता जी 63 मिनट बोल चुके हैं और कांग्रेस ने 15 मिनट का समय बी.जे.पी. को दे दिया था जो श्री कृष्ण पाल गुज्जर ने ले लिया। (विघ्न)

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, कृष्णपाल जी को उसके समय में तो बोलने नहीं दिया और आप कह रहे हैं कि हमारा समय भी उसको दे दिया गया। यदि हमारा समय उसके साथ जोड़ा जा रहा है तो उसे दोबारा बुलाया जावे।

वित्त मंत्री (प्रो. सम्पत सिंह) : अध्यक्ष महोदय, आप चौधरी भजन लाल जी को समय बता दें कि कांग्रेस को कितना समय दिया गया है और बी.जे.पी. को कितना समय दिया गया है ?

श्री अध्यक्ष : चौधरी भजन लाल जी कांग्रेस पार्टी को बजट पर बोलने के लिए 120 मिनट का समय दिया गया था जिसमें से 63 मिनट मांगेराम गुप्ता जी बोल चुके हैं और 15 मिनट का समय आपके कहने पर बी.जे.पी. को दे दिया गया। अब कांग्रेस के लिए सिर्फ 42 मिनट का समय बचा है। (विघ्न)

प्रो. सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, चौधरी भजन लाल जी के कहने पर ही आपने बी.जे.पी. को 15 मिनट अधिक समय दिया है यह रिकार्ड की बात है। यह हाउस की कार्यवाही में भी आया हुआ है। इन्हें अपनी कल की बात पर कायम रहना चाहिए। आपकी स्पीकिंग है उसको ये चैलेंज नहीं कर सकते। अध्यक्ष महोदय, चौधरी भजन लाल जी का ताजा-ताजा समझौता बी.जे.पी. के साथ हुआ है और ये आज ही इस समझौते को तोड़ रहे हैं। इनके कहने पर ही 15 मिनट का समय बी.जे.पी. को दिया गया था। इन्होंने यमुनानगर में जो समझौता किया था उसको निभावें। (विघ्न)

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, हम झूठ नहीं बोलते। बी.जे.पी. के सदस्य तो अपने समय में भी नहीं बोल पाये और आप कह रहे हैं कि हमारा समय भी उन्हें दे दिया गया।

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, यदि चौधरी भजन लाल जी 15 मिनट के लिए ही अपनी दोस्ती तोड़ेंगे तो ये तीन साल साथ कैसे निभायेंगे। अध्यक्ष महोदय, 15 मिनट का समय इन्होंने बी.जे.पी. को देकर जो फिराखदिली दिखाई है उसको निभाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, इसी दोस्ती को निभाने के लिए तो कांग्रेस विधायकों ने राज्यसभा के मैम्बर के लिए निर्दलीय कंडीडेट के फार्म भरवायें हैं, यह पार्टी की अनुशासनहीनता है और इस बारे में इन्हें उनके खिलाफ डिसीप्लीनरी एक्शन लेना चाहिए। लेकिन इन्होंने अपनी दोस्ती को निभाने के लिए ही इंडिपैंडैंट फार्म फाईल किए हैं ताकि दूसरों के वोट बटोर सकें। (शोर एवं व्यवधान)

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, दोस्ती निभाने के बारे में मैं चौटाला साहब को बताना चाहूंगा कि दोस्ती न निभाने की बात हमने इनसे सीख ली है। बी.जे.पी. ने इनका साथ दिया लेकिन बी.जे.पी. का बहुत सत्यानाश किया है। हम तो थोड़ी बहुत सहायता कर रहे हैं अगर ये करने देंगे तो।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, चौधरी भजन लाल जी दोस्ती के बारे में चौधरी बंसी लाल जी से पूछें कि कांग्रेस से दोस्ती करने के बाद उनकी क्या दुर्गति हुई ?

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, हमने अपनी मर्जी से इनका साथ नहीं दिया था, मेरे दोनों बेटे उस समय विधायक थे और वे समर्थन देने से मना कर रहे थे लेकिन मजबूरी में समर्थन देना पड़ा और उसी की वजह अध्यक्ष महोदय चौटाला साहब आज यहां बैठे हैं।

प्रो. सम्पत सिंह : स्पीकर सर, हम उस चौधरी बंसी लाल जी की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आये थे लेकिन कांग्रेस ने चौधरी बंसी लाल जी का साथ दिया और कुछ दिन बाद ही साथ छोड़ दिया।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, उस समय मेरे दोनों बेटे अंत तक समर्थन न देने के लिए अड़े रहे थे लेकिन मजबूरी में समर्थन देना पड़ा।

प्रो. सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने बंसी लाल जी का समर्थन करके उनका भी काम ठप्प करवा दिया और अपना भी। (शोर एवं व्यवधान)

नगर एवं ग्राम आयोजना मंत्री (श्री वीर पाल सिंह) : स्पीकर साहब, श्री कृष्ण पाल गुर्जर जी कल बजट पर चर्चा करते हुए फिल्मी अन्दाज में हाउस में गलत जानकारियां दे रहे थे। स्पीकर साहब, इस महान सदन में लिखा हुआ है कि गैर जिम्मेदाराना ढंग से बोलने या गलत बोलने पर वानि दोनों ही स्थितियों में मनुष्य पाप का भागी होता है। (विघ्न) उन्होंने हमारे विभाग के बारे में गैर जिम्मेदाराना बात कही और गलत कही। यदि मैं इसे झूठ शब्द का इस्तेमाल करते हुए संबोधित करूंगा तो फिर यह शब्द अनपार्लियामैंटरी बन जायेगा। वे कल यहां पर गलत बात कहते हुए अपनी लम्बी चौड़ी बात कह रह चले गए। यहां पर दर्शक साथी भी बैठे थे और प्रैस के भाई भी बैठे हुए थे। उन्होंने चौधरी भजन लाल को अपना राजनीतिक गुरु बनाकर ... (विघ्न) इन्होंने उनको क्या पाठ पढ़ाया फिल्मी अन्दाज में ऐसा माहौल बनाया कि मेरे विभाग से संबंधित वे यहां पर गलत बात कह गए और यहां पर आरोप पर आरोप लगाते रहे। (विघ्न)

चौधरी भजन लाल : मैं ऐसे आदमी को चेला नहीं बनाता। (विघ्न)

श्री वीर पाल सिंह : कल आपने अपनी पार्टी के समय में से उसको बोलने के लिए 15 मिनट दिए हैं तो क्या अब मैं अपने विभाग के बारे में, अपनी पार्टी के बारे में या अपनी सरकार के बारे में उन्होंने हमारे ऊपर जो आरोप लगाये हैं उनके बारे में सदन को नहीं बता सकता। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, इस महान सदन की मर्यादा जो भंग हुई है, सदन की भावनाओं को जो चोट लगी है उस बारे में ठीक-ठीक जानकारी से सदन को अवगत कराना मेरा

[श्री धीरपाल सिंह]
दायित्व बनता है। (विघ्न)

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर साहब, इस वक्त संबंधित मैम्बर सदन में उपस्थित नहीं है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : आप बैठ जायें। (विघ्न) ये कोई आरोप नहीं लगा रहे। ये हाउस को जानकारी देने के लिए बोल रहे हैं। (विघ्न)

चौधरी भजन लाल : आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : चौधरी भजन लाल जी, आप पहले इनकी ब्यान से बातें सुनें, उसके बाद ही आप कुछ कहना। (विघ्न) आप फिर बोल लेना, आप बैठ जाएं। (विघ्न)

चौधरी भजन लाल : ये भी ऐसे बोल नहीं सकते। (विघ्न)

श्री धीर पाल सिंह : चौधरी साहब, मैं बोलूंगा। मैंने आपसे टाईम नहीं लिया। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : चौधरी भजन लाल जी, आप बैठिये। (विघ्न)

श्री धीर पाल सिंह : स्पीकर साहब, कृष्ण पाल जी की तरफ से पहला प्रश्न यह आया कि किसी जनसेवा ट्रस्ट की एक एकड़ जमीन हुड्डा की तरफ से ट्रांसफर की गई जिस कारण करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस महान सदन को यह जानकारी देना चाहता हूँ कि उन द्वारा कही गयी बात असत्य और काल्पनिक बात थी। (विघ्न) चौधरी भजन लाल जी द्वारा मनगढ़ंत बात थी। (विघ्न) अगर एक इंच जमीन भी हमारे विभाग द्वारा इस ट्रस्ट को दी गई हो तो मैं गुनहगार हूँ। अध्यक्ष महोदय, हमारे द्वारा इस ट्रस्ट को एक इंच जमीन भी नहीं दी गई, फिर भी ये आरोप पर आरोप लगाते चले गये। उनके द्वारा आरोप लगाया गया कि एक संस्था को इतना लाभ पहुंचाया गया है इस बारे में मैं कहना चाहूंगा कि उनकी तरफ से जो चर्चा की गई है वह गैर जिम्मेदाराना ढंग से की गई है और हाउस को गुमराह करने का काम किया गया है। मैं इसकी निन्दा भी करता हूँ और हाउस को मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हुड्डा की एक इंच जमीन भी इस ट्रस्ट को ट्रांसफर नहीं की गई। अध्यक्ष महोदय, दूसरा विषय था..... (विघ्न)

चौधरी जय प्रकाश : शोपिंग कम्पलेक्स तो बना था (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : जय प्रकाश जी, आप बैठिये। (विघ्न)

चौधरी जय प्रकाश : क्या पूछना भी पाप है। (विघ्न) ******

श्री अध्यक्ष : जय प्रकाश जी, आप बैठ जाएं। (विघ्न) इनकी कोई बात रिकार्ड न की जाये। (विघ्न) आप बैठिये। आप को जो देना है वह लिख कर दे दें। (विघ्न) बगैर इजाजत के बीच में बोलना भी पाप है।

श्री धीर पाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, गुर्जर साहब का दूसरा विषय डी.एल.एफ./यूनिवर्सल को वाणिज्य सेंटर के लिए जमीन देने के बारे में था। स्पीकर साहब, उन्होंने दिनांक 6-1-1999 को ग्राम सनकोड़ा जिला गुड़गांव के लिए लाइसैंस के लिए एप्लाई किया। इस इलाके में 30-1-1999 को 215 एकड़ जमीन के लिए सैक्टर 30 में अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू हुई और सैक्शन 6 का नोटिस हुआ। (विघ्न) स्पीकर साहब, दिनांक 30-1-1999 को ए-क्लास के जो निर्माण थे वे छोड़े गए और उसके बाद 171 एकड़ जमीन जो सैक्टर 30 में बचती है..... (विघ्न)जब चौधरी भजन लाल का राज आ गया तो ..... (विघ्न) कल ये कांग्रेस के भाई कहने लगे कि हमारे 15 मिनट उनको

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

दे दें। हमारे को ये कहते हैं कि 100 करोड़ रुपये का घपला हुआ। अध्यक्ष महोदय, चौधरी साहब, जब मुख्य मंत्री थे तो 23-5-1995 को मै. ईस्ट इण्डिया कम्पनी को होटल बनाने के लिए लाइसैंस दिया गया। 171 एकड़ में से इनके वक्त में 30 एकड़ जमीन होटल बनाने के लिए दी तो इससे आप अन्दाजा लगाये कि कितना घपला हुआ होगा। (विघ्न) मैं यह मान सकता हूँ कि जब ये हम पर 100 करोड़ रुपये के घपले का आरोप लगाते हैं तो इनके वक्त में 6 गुना अधिक लाइसैंस दिया गया तो फिर उसके हिसाब से इनके वक्त में 600 करोड़ रुपये का घपला हुआ होगा।

चौधरी साहब, आप भी सहमत होंगे 171 एकड़ जमीन पर माननीय हाईकोर्ट ने स्टे दिया हुआ था और जितने भू-पति थे जमीन के मालिक थे सभी पार्टीज जो हाईकोर्ट में गई हुई थीं उनको हाईकोर्ट ने स्टे दिया हुआ था और उसके बाद स्पीकर सर, 171 एकड़ जमीन में से केवल 12 एकड़ जमीन पर अवार्ड हो पाया बाकी पर इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि कोर्ट ने स्टे दिया हुआ था। स्पीकर सर, अगली बात यह है कि जो श्रीमान् जी बोल रहे थे, कृष्ण पाल जी, वह स्वयं उस समय मंत्री थे। 30-7-1998 को हरियाणा मन्त्री परिषद् की बैठक होती है और उस बैठक में यह निर्णय होता है कि 33 भू-पतियों के पास सैक्शन-4 से पहले अपनी जमीन है या मलकियत है और वह लाइसैंस के लिए एप्लाई करना चाहते हैं तो स्पीकर साहब उसको लाइसैंस दिया जाए, नॉर्म के आधार पर उसकी भूमि रिलीज की जाए। यह हरियाणा मन्त्री परिषद् का फैसला था और वे श्रीमान् जी स्वयं उस मीटिंग में शामिल थे मैंने रिकार्ड में उसकी हाजरी देख ली है। स्पीकर सर, उसके बाद जैसे मैंने आपसे निवेदन किया 6-1-1999 को यह आवेदन आया और विभाग ने उस पर कार्यवाही की। कार्यवाही करने के बाद विभाग ने उनसे लिखित में यह लिया कि हाईकोर्ट में जो केस पैंडिंग हैं उनको वापिस लिया जाएगा, पार्टीज ने लिख कर दिया कि हम केस वापिस लेंगे और उसके साथ जमीन का जो लाइसैंस है वह हरियाणा मन्त्री परिषद् के अनुमोदन के बाद दिया गया। स्पीकर सर, बिइंग ए मिनिस्टर मैं उनकी बात को चैलेंज करता हूँ अगर एक तारीख को कोई कार्यवाही हुई हो तो मेरा रिजाईन स्वीकार कर लिया जाए या जो गलत जानकारी हाउस में दी गई है और गलत बात कही गई है चौधरी भजन लाल जी के कहने पर जो ड्रामा हुआ उन पर ऐक्शन होना चाहिए। (विघ्न)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : स्पीकर सर, चौधरी भजन लाल जी की पुरानी आदत रही है कि ये दोस्ती निभाते हैं और मैं भी इनकी इस बात का कायल हूँ। (विघ्न) क्योंकि इनकी दोस्ती चौधरी बंसी लाल जी से भी रही है और मैं परमात्मा से दुआ करूंगा कि इनकी दोस्ती बी.जे.पी. से निभ जाए। (विघ्न) इनको यह दोस्ती जरूर निभानी चाहिए थी लेकिन कई मर्तबा क्या होता है कि हम प्रयास करते हैं लेकिन फिर भी मार पड़ती है। स्पीकर सर, एक कहावत है कि तेली के गई फिर भी रुखा खाया दोस्ती भी निभाई लेकिन राज्य सभा के पेपर्ज भी दर्ज नहीं हुए। (विघ्न) दोस्ती भी निभाई इसके लिए इनके कुछ साथियों ने धर्म परिवर्तन भी कर लिया और पार्टी में अनुशासन नहीं रहा, इंडिपैंडेंट के तौर पर दस्तखत भी किए और पेपर भी फाईल किए और उधर दोस्ती भी निभाई। स्पीकर सर, जो लोग एक रेल में इकट्ठे सफर नहीं कर सकते उन लोगों की दोस्ती भी सिरे नहीं चढ़ी और राज्य सभा के पेपर भी रिजैक्ट हो गए। (विघ्न)

चौधरी भजन लाल : कायदे के मुताबिक तो पेपर रिजैक्ट नहीं हो सकते हैं। (विघ्न) आप मेरी बात सुनिये (विघ्न) ******

श्री अध्यक्ष : चौधरी भजन लाल जी, उन्होंने कोई खास बात नहीं कही है इसलिए आप अपनी सीट पर बैठें। चौधरी भजन लाल जी जो कुछ कह रहे हैं वह रिकार्ड न किया जाए। (विघ्न)

चौधरी भजन लाल : स्पीकर सर, आपको क्या पता है कि उन्होंने कितनी बड़ी बात कह दी है। एक बात

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

[चौधरी भजन लाल]
में ही उन्होंने सारी बात कह दी है (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : चौधरी भजन लाल जी, आप अपनी सीट पर बैठें। चौधरी धीरपाल सिंह जी बोल रहे हैं उनको अपनी बात कम्पलीट करने दें उसके बाद आप अपनी बात कह लेना। (विघ्न) इनकी कोई बात रिकार्ड न करें।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय ******

श्री अध्यक्ष : चौधरी भजन लाल जी, आप अपनी सीट पर बैठें इनकी कोई बात रिकार्ड न करें। (विघ्न)

11-00 बजे **श्री अध्यक्ष :** भजन लाल जी, बंसी लाल जी उठकर चले गये हैं अब आप क्या बोल रहे हैं ?

चौधरी भजन लाल : चौधरी जय प्रकाश सांगवान का नोमिनेशन रिजैक्ट हो गया है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : चौधरी भजन लाल जी, आप अपनी सीट पर बैठ जाएं आपके दोस्त तो सदन से बाहर चले गए हैं।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि कायदे के मुताबिक वह रिजैक्ट नहीं हो सकता है। अध्यक्ष महोदय, आप माईक वाले को बोलें कि माईक खोलें।

श्री अध्यक्ष : आप जो भी बोलना चाहते हैं वह बोलें मुझे सब सुन रहा है।

चौधरी भजन लाल : आप जब उनको कहते हैं तो वे माईक ऑन कर देते हैं और आप जब कहते हैं तो वे माईक बंद कर देते हैं।

श्री अध्यक्ष : इनको मेरी यह बात तो माननी पड़ेगी ही। मैं जब कहूँगा तभी वे माईक ऑन करेंगे।

चौधरी भजन लाल : यह कोई बात नहीं है। अब आप यह क्यों नहीं कहते कि सैक्रेटरी ने नोमिनेशन पेपर आपके आदेश से रिजैक्ट कर दिया होगा। वह प्रिजाईडिंग आफिसर है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नहीं-नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। यह कानूनी प्रक्रिया है, इलैक्शन प्रोसीजर है इसमें किसी से कोई भेदभाव नहीं बरता जाता है। (शोर एवं व्यवधान)

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि दोस्ती निभाना हर आदमी का फर्ज है। जहां तक निभा सके निभानी चाहिए। हमने आपकी भी निभाई, इनकी भी निभाएंगे और B.J.P. की निभाएंगे।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : भजन लाल जी, आप सदन में कांग्रेस के बतौर अपोजिशन के नेता यह कह रहे हैं कि आप B.J.P. से दोस्ती निभाएंगे। अब आप बाद में मुकर मत जाना कि आपने यह बात नहीं कही है।

चौधरी भजन लाल : ओम प्रकाश चौटाला जी, ऐसा नहीं है। मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि दोस्ती का क्या मतलब है, किसी के साथ ज्यादती हो, अन्याय हो, चाहे वह आदमी HVP, BJP या आपकी पार्टी का हो हम उस पर भी ज्यादती नहीं होने देंगे। हम उसकी भी मदद करेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री धीर पाल सिंह : स्पीकर सर, कृष्ण पाल जी ने 18-7-2000 के बारे में खास दबाव डाला कि एक दिन में सारा काम हो गया। मैं उनको यह बताना चाहूँगा कि हमारे सी.ए. हुड्डा ने 18-7-2000 को फाईल कमिश्नर के पास भेजी, कमिश्नर साहब ने वह फाईल 3 दिन के बाद 21-7-2000 को आगे भेजी थी। उसके बाद मुख्य मंत्री

* स्पीकर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

जी ने उस फाईल को 14-9-2000 को एप्रूव किया था। कृष्ण पाल जी ने कहा कि यह सारी प्रक्रिया सिर्फ एक घंटे में पूरी हो गई थी। उन्होंने यह बात सदन में कह कर सदन को गुमराह किया है। 19-7-2000 को वह फाईल डाउन जाती है और फिर मंत्री परिषद् के पास जाती है। इसके बावजूद भी राष्ट्रीय राज मार्ग प्राधिकरण भारत सरकार ने लिखकर बोर्ड को कहा कि वह लिखकर उनसे अनुमति लें। उनसे अनुमति लेने के बाद ही नक्शे स्वीकृत किए गए। अध्यक्ष महोदय, कृष्ण पाल जी जो यहां पर कह रहे थे कि अगर चार एकड़ जमीन को तैयार करते, सड़क बनवाते, सीवरेज डालते, पानी की लाइन डालते और बिजली की लाईन लगाते तो उस पर हमारा खर्चा 50 लाख आना था। मैं यह कहना चाहता हूँ कि अगर हम वहां पर प्लाट काटते और उनको बेचते तो हमें साढ़े तीन करोड़ रुपये मिलते और वह भी छः साल में सालाना किश्तों में मिलते। हमने लाइसेंस देने के बाद, ऊपर से परमिशन देने के बाद उससे विभाग को जो पैसा मिला है उस बारे में मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूँगा कि लाइसेंस फीस 1 करोड़ 10 लाख 94 हजार हमने ली। स्क्रूटनी फीस 2 लाख 69 हजार 4 सौ रुपये ली, सर्विस चार्जिज 2 लाख 69 हजार 4 सौ रुपये ली, कन्वर्शन चार्जिज 2 करोड़ 61 लाख के करीब मिली है। (विघ्न) यहां पर कृष्ण पाल जी ने कहा था कि 100 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, अगर हम प्लाट तैयार करके बेचते तो हमें उससे साढ़े 3 करोड़ रुपए ही मिलते और वह भी सालाना किश्तों में छः साल में मिलते। अध्यक्ष महोदय, हमें जो अब तुरन्त पैसा मिला है वह 5 करोड़ 92 लाख 69 हजार 300 रुपये मिला है। (विघ्न) चौधरी साहब, यह मेरी पार्टी का टाइम है आप मुझे बोलने दें। (विघ्न) कृष्ण पाल जी की जितनी चाबी भजन लाल जी ने भरी थी वह उतना बोलकर यहां से चले गए हैं। रात की दोस्ती इतनी ही हुआ करती है। चौधरी साहब, अब तो दिन है। अध्यक्ष महोदय, दूसरा उन्होंने आरोप लगाया कि खसरा नम्बर 532 (ii) खसरा नम्बर 533 (iii), खसरा नम्बर 534 (iii) है यह कुल मिलाकर 2.38 एकड़ बनता है। इस पर जो लाइसेंस दिए गए और जिस नीति के अन्तर्गत दिए गए तो 30-7-1998 को जो हरियाणा मंत्रिपरिषद् ने जिस मीटिंग में निर्णय लिया था उसमें श्रीमान् कृष्ण पाल गुर्जर भी थे। उसमें यही निर्णय लिया गया था कि अगर किसी के पास अपनी जमीन है और वह लाइसेंस के लिए अप्लाई करता है तो लाइसेंस के साथ उसकी जमीन को भी अधिग्रहण से मुक्त किया जाएगा। स्पीकर सर, इस पार्टी का 1993-94 से कब्जा था। इससे लाइसेंस के बाद जो हमें पैसा मिला वह 2 करोड़ दो लाख 75 हजार रुपये था। स्पीकर सर, अगर हुड्डा इसको तैयार करता और इस पर खर्च करता तो यह खर्चा एक करोड़ 85 लाख रुपया आता। स्पीकर सर, यह दूसरा प्वायंट है। इसके अलावा उन्होंने देवीनगर की बात भी कही। वे हमारे साथी चले गए। स्पीकर सर, वह जो जमीन एक्वायर हुई है वह 1.02 एकड़ है उसमें आरा लगा हुआ है वहां ए-क्लास का निर्माण होना है। चौधरी भजन लाल जी, आप चीफ मिनिस्टर के साथ-साथ हुड्डा के मिनिस्टर भी रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि यह हुड्डा की नीति है कि जहां पर ए-क्लास का निर्माण होगा वहां पर जमीन अधिग्रहण के बाद सैक्शन 6 के बाद उसको मुक्त किया जा सकता है। इस 1.02 एकड़ जमीन पर ए-क्लास का निर्माण होगा। स्पीकर सर, वहां पर कर्मचारी रह रहे थे उनके आवास बने हुए थे। इससे पहले भी उन्होंने वहां पर आरा लगाने के लिए निदेशक, उद्योग विभाग, हरियाणा से अनुमति ली थी। यह पंजीकृत इंस्टीच्यूशन है। उनके साथ यह शर्त रखी गयी थी कि 1.02 एकड़ जमीन में से वे तीस मीटर जमीन ग्रीन बैल्ट के लिए छोड़ेंगे। स्पीकर सर, इसी के साथ जो 2.47 एकड़ जमीन थी वह धार्मिक आश्रम की थी। एक ट्रस्ट बना हुआ है कोई सम्मानित पूर्वज थे उनकी वहां पर समाधि है। वहां पर उनकी परिवार की आपस में कोई अनबन होगी लेकिन इन्होंने उसको भी घसीट लिया। वहां पर रहने की, खाने-पीने की, पार्किंग की व्यवस्था है। जहां पर छोटे-छोटे बच्चों के लिए झूले लगे हुए हैं शाम को बच्चे वहां पर झूला झूलते हैं। 2.47 एकड़ जमीन जो थी इसका एक ट्रस्ट था यह धार्मिक संस्था थी। यह सोचकर इसको जमीन दी गयी थी कि यह संस्था बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए एवं बच्चों के लिए अनेक कार्य कर रही है। इसमें ए-क्लास का निर्माण भी है साथ वहां पर भावनाएं भी जुड़ी हुई हैं क्योंकि उसमें एक समाधि थी। स्पीकर सर, इसी मापदंड के आधार पर उनको यह 2.47 एकड़ जमीन छोड़ी गयी लेकिन इन्होंने उसका भी बवेला मचा दिया। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप इस

[श्री धीरपाल सिंह]

बारे में रिकार्ड मंगा कर देखें कि जो उन्होंने कहा है कि 19 करोड़ रुपये का इस पर हुड्डा ने खर्च किया होगा, हुड्डा ने जमीन डिवैल्प करी वहां पर फुव्वारे लगा दिए लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि एक पैसा भी इन दोनों जमीनों पर खर्च नहीं किया। अगर एक पैसा भी खर्च हुआ हो तो धीर पाल एक मिनट में ही इस्तीफा दे देगा, नहीं तो वह व्यक्ति इस्तीफा दे दे जिसने कदम-कदम पर इस बारे में झूठ बोला और हाउस को गुमराह किया। उन्होंने यहां पर एक ऐसा फिल्मी माहौल बनाया कि जो यहां पर दर्शक थे वे भी चिंतित हो रहे थे, प्रैस ने भी अपने-अपने अखबारों में लिखा कि सरकार को घेरने की कोशिश की गयी। स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से सदन से कहना चाहूँगा कि यह निंदनीय है। (विघ्न) भजनलाल जी, आपने भी तीस एकड़ जमीन का लाईसैंस दे दिया था। कल तो ये उनकी सुपोर्ट कर रहे थे और कह रहे थे कि उनको मेरे समय के भी 15 मिनट बोलने के लिए दे दो। वाह, कल तो इनको बड़ा बी.जे.पी. से प्रेम हो गया था कल आपने उनसे इतना मीठा प्रेम कर लिया। (विघ्न) स्पीकर सर, गलत बात कहने से काम नहीं चलेगा। यह हाउस न इनका है और न मेरा है बल्कि यह हाउस हरियाणा प्रदेश का है। जो लोग गुमराह करेंगे वह गुनाहगार होंगे। स्पीकर सर, हमारे राज में एक पैसा भी इस जमीन पर खर्च नहीं हुआ और न ही कोई घपला हुआ है। सारे काम कानून कायदे के अनुसार हुए हैं। दोष गलत बात कहने वालों का है और दोषी उनके उस्ताद हैं। स्पीकर साहब, यही बात मैं कहना चाहता था।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं पूरे सदन के सभी सम्मानित सदस्यों को विशेष रूप से विपक्ष के नेता को और उनकी पार्टी के वरिष्ठ सदस्यों को अर्ज करना चाहूँगा कि सदन का समय बहुत बहुमूल्य होता है। पूरे प्रदेश के दो करोड़ दस लाख लोगों की निगाह इस सदन पर इस वक्त टिकी हुई है। हम यहां बैठकर पूरे प्रदेश के लोगों का एक साल का लेखा-जोखा तय करते हैं। कल सदन में एक जिम्मेवार पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने बजट पर चर्चा की शुरूआत की। लगभग एक घंटे से अधिक समय तक गुप्ता जी बोले होंगे। (विघ्न)

चौधरी भजन लाल : उस समय में से 20 मिनट तक तो टोका टाकी लगी रही।

श्री अध्यक्ष : गुप्ता जी पूरे 63 मिनट बोले थे।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, गुप्ता जी ने एक लफ्ज भी बजट से संबंधित नहीं कहा और स्वयं उन्होंने तसलीम किया है कि मैंने किताब नहीं पढ़ी। (विघ्न) इसी प्रकार से इस समय मेरे सम्मानित दोस्त बठे नहीं हैं वे लगभग 36 मिनट तक अपने समय का बोले और 15 मिनट चौधरी भजन लाल जी के हिस्से के बोले, टोटल 51 मिनट बोले और बड़ी ही निराधार, अनर्गल बातें कहीं जिनका कोई सिर पैर नहीं था। निराधार और अनर्गल बातें कहकर सदन का समय खराब किया। हम इसको गहराई से देखेंगे और अगर यह ब्रीच ऑफ प्रिविलेज भी बनता होगा तो ऐक्शन लेंगे। मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग सदन की गरिमा का ध्यान रखें, सदन के समय का ख्याल रखकर बात करें। टू दि प्वायंट बात करें। भाषण देने की कोशिश न करें। भाषण देने की कोशिश में उलझ जाएंगे इसलिए बजट पर चर्चा करें। मैं ईमानदारी से कहता हूँ कि यदि कोई सदस्य रचनात्मक सुझाव देगा तो उन्हें सरकार मानेगी।

वैयक्तिक स्पष्टीकरण-

श्री मांगे राम गुप्ता एम.एल.ए. द्वारा

श्री मांगे राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं पर्सनल ऐक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : आप बैठ जाइए। रघुबीर सिंह कादयान को बजट पर बोलने के लिए अनुमति दी जा चुकी है।

श्री मांगे राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी सदन का समय खराब करने की बात कर रहे हैं। मुझे आपने समय दिया। मैंने आपसे बोलने की इजाजत लेकर बोलना शुरू किया। उस समय सब लोग मुझे बीच

में टोका-टाकी कर रहे थे और इस प्रकार मुझे आधे घण्टे तक डिस्टर्ब किया गया और आपने जब मुझे कहा कि बैठ जा तो मैं बैठ गया। अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने कह दिया कि मैं किताब पढ़कर नहीं आया। मैं आज कह रहा हूँ कि वित्तमंत्री जी ने हाउस में जो बजट पर स्पीच पढ़ी उसी के मुताबिक मैंने हाउस में आंकड़े रखे। वित्तमंत्री जी की स्पीच से बाहर मैंने एक शब्द भी गलत नहीं बोला। अगर एक शब्द भी गलत बोला हो तो आप जो सजा दें मैं वह सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। (विघ्न) मुख्य मंत्री जी तो हाउस में थे ही नहीं। मैंने एक भी बात विदाउट रिकार्ड नहीं कही है।

प्रो. सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी के कहने का मतलब यह है कि मांगे राम जी से हमें बहुत उम्मीद थी इन्होंने यह कहा था कि स्पीच को छोड़कर बाकी जो पेपर्स हमने दिए हैं। जैसे ऐक्सप्लेनेट्री नोट दिए हैं, रेवेन्यू के, इंकम के जो डिटेल्ड नोट सर्कुलेट किये हैं, एस.वाई.एल. के बारे में जो कागज दिए हैं इन्होंने खुद माना कि इन्होंने वे नहीं पढ़े हैं। इन्होंने यह कहा था कि एस.वाई.एल के बारे में बजट में कुछ नहीं दिया हुआ। तब इन्होंने कहा कि बजट स्पीच को छोड़कर मैंने कुछ और नहीं पढ़ा। मैंने यह कहा था कि इनको तो पढ़ना चाहिए था इसमें और कोई लम्बी चौड़ी बात नहीं है।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गुप्ता जी को बताना चाहूँगा कि गुप्ता जी जब आदमी खुद भाषण देता है तो यह बात ध्यान में नहीं रहती कि वह क्या बोला है। जब आपके पास आपकी स्पीच करैक्शन के लिए आये तब उसको पढ़कर देख लेना कि आपने क्या बोला है तब आपकी समझ में आ जायेगा।

वर्ष 2002-2003 के लिए बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

डॉ. रणबीर सिंह कादयान (बेरी) : स्पीकर सर, आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दिया इसके लिए आपका धन्यवाद! स्पीकर सर, सबसे पहले वित्त विभाग के बारे में कहना चाहूँगा कि वित्त विभाग ने जिस अच्छे ढंग से यह बजट बनाया है मेरे हिसाब से किसी माननीय सदस्य को बजट के बारे में इतनी माहरत हासिल नहीं है कि वह इस बजट को पढ़ सके और समझ सके। लेकिन मोटे तौर पर अगर नजर डाली जाये तो यह साफ नजर आता है कि पूरे का पूरा बजट तनख्वाहों में और नॉन प्लॉन एक्सपैंडीचर में और कर्मचारियों की सैलरी की अदायगियों में बंट जाता है। वित्तीय प्रबन्धन के नाम पर भी कोई नयी चीज नजर नहीं आती। पिछले दो सालों के बजट पर नजर डालें तो पी.सी.आई. की रेट ऑफ ग्रोथ साफ घटती दिखाई दे रही है। माननीय वित्त मंत्री महोदय ने 2000-2001 के बजट में वार्षिक योजना व्यय 2530 करोड़ रुपये रखा था जिसमें 39 फीसदी गिरावट आई और रिवाईज्ड बजट एस्टिमेटस में 1815 करोड़ रुपये का रह गया था और उस समय ट्रेजरी बैंचिज के सदस्यों ने बड़े जोर से मेजें थपथपाई थीं कि इतना बड़ा प्लान बनाया है। लेकिन उसमें रिवाईज्ड एस्टिमेटस में वह 1815 करोड़ रह गया। 2000-2001 की एनुअल प्लान में 39 फीसदी की गिरावट आई और इसी तरह 2001-2002 का बजट रखा गया उसमें वार्षिक योजना 2150 करोड़ रुपये की थी लेकिन उसमें भी डाऊन फाल कट हुआ कि वह वार्षिक योजना भी 1838 करोड़ रुपये की रह गई। उसमें भी सीधे तौर पर 20 फीसदी की गिरावट आ गई। उसी प्रकार अब माननीय वित्त मंत्री जी ने वर्ष 2002-2003 का बजट पेश किया है। इसमें भी वार्षिक योजना 1922 करोड़ रुपये की रखी गई है। मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि अगर पिछले साल की तरह ट्रेंड रहा तो यह प्लान भी 1600 करोड़ रुपये की रह जायेगी और 1600 करोड़ में भी अगर एक्चुअल वैल्यू देखी जाये तो कंट्री का इंफलेशन दर साढ़े चार से पांच प्रतिशत रहती है तो यह पांच फीसदी और कम हो जायेगी और उस हिसाब से यह 1500 करोड़ रुपये की प्लान ही रह जायेगी। इसमें नये एसैट्स के लिए बजट क्या रह जायेगा यह तो सरकार और वित्त मंत्री इस सदन को बतायें क्योंकि प्लानिंग कमीशन लगातार अपनी प्लॉन में कट करता रहता है और फायनैंस कमीशन के परसैंटेज ऑफ एनुअल रेट में भी कमी होती जा रही है। स्टेट के सोर्स नये असैटस बढ़ाने के लिए प्लॉन में फन्ड फैंड

[डॉ. रघबीर सिंह कादयान]

के नाम से आन लाइन लॉटरी का ही जिक्र किया है। ऑन लाइन लाटरी के नाम से प्रदेश के जो नौजवान हैं उनका भविष्य खतरे में पड़ जायेगा यह उसी तरह की बीमारी है जिस तरह की बीमारी लॉटरी फन की थी और उस लॉटरी के आज जो छोटे-छोटे धंधे जहां चल रहे हैं उससे मजदूर और गरीब किस्म के लोग फांसी और आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि दिल्ली के चारों ओर हरियाणा प्रदेश है, इन्फ्रास्ट्रक्चर यहां क्रिएट किया जा सकता है, अपने प्लॉन और असैटस को बढ़ाया जा सकता है, फाइनैंशियल मैनेजमैंट अच्छे ढंग से करके प्रदेश के नौजवानों का इस लाटरी जैसी बुराई से पीछा छुड़ाया जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, इस बजट में दिया हुआ है कि लोन रिपेमैंट और इंट्रस्ट पेमैंट पर 39 फीसदी खर्च होगा। जब टोटल बजट का 40 फीसदी बजट कर्ज और उसके ब्याज की अदायगी में चला जाएगा तो स्टेट के पास इतना क्या रह जाएगा यह वित्त मंत्री जी अच्छी तरह से जानते हैं। 3600 करोड़ रुपये डैबिट सर्विसेज में दर्शाया गया है। 3600 करोड़ रुपये का मतलब है जब हरियाणा में कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके ऊपर तकरीबन 1800 रुपये कर्ज होता है। नॉन प्लॉन एक्सपैंडीचर बुरी तरह से बढ़ता जा रहा है। वर्ष 2000-2001 का जब वित्त मंत्री जी ने बजट रखा था उस समय टोटल प्लॉन में से 3384 करोड़ रुपये नॉन प्लॉन एक्सपैंडीचर के लिए रखा गया था और प्लान एक्सपैंडीचर के लिए 3233 करोड़ रुपये रखा गया था। इसका मतलब 75 फीसदी हरियाणा प्रदेश का बजट जब नॉन प्लॉन यानी लोन की रिपेमैंट और कर्ज की अदायगी पर खर्च होगा तो 25 फीसदी में हरियाणा का क्या प्लॉन बनेगा। जब वर्ष 2001-2002 का बजट रखा गया तो उसमें तकरीबन 9375 करोड़ रुपये नॉन प्लॉन एक्सपैंडीचर के लिए रखा गया और 8116 करोड़ रुपये प्लॉन एक्सपैंडीचर के लिए रखा गया। इसका मतलब नॉन प्लॉन एक्सपैंडीचर के लिए योजना का 78 फीसदी रखा गया और आज जो बजट रखा गया है तो उसमें टोटल 10401 करोड़ रुपये रखा गया है इसमें 9055 करोड़ रुपये नॉन प्लान एक्सपैंडीचर के लिए रखा गया। इस प्रकार जब 87 फीसदी हरियाणा प्रदेश का बजट तनख्वाहों और गैर योजनाओं पर, कर्ज और उसके ब्याज की अदायगी पर खर्च हो जाएगा तो 13 फीसदी बजट में जो इन्होंने लम्बी-लम्बी योजनाएँ बिजली और सड़कों के बारे में बताई हैं उनका क्या होगा ? अगर 100 में से 13 रुपये हरियाणा प्रदेश के लिए बचेगा तो उससे कौन-कौन से प्लॉन एग्जीक्यूट होंगे और कौन-कौन से काम हो सकेंगे? इससे हरियाणा प्रदेश का जो पर कैपिटा इन्कम है या टोटल ग्रास डोमैस्टिक प्रोडैक्ट है वह कैसे बढ़ सकेगा और बिलो पावरटी लाइन के लोगों को कैसे ऊपर उठाया जाएगा यह हमारी समझ के बाहर की बात है? वित्त मंत्री जी बहुत काबिल मंत्री हैं यह ठीक है लेकिन साफ नजर आता है कि इन्होंने बड़े भारी मन से इस बजट को बनाया है। इनकी भी लिमिटेशन हो सकती हैं। इसलिए मेरा इसमें यह सुझाव है कि हरियाणा दिल्ली के चारों तरफ है और उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन ऐसी है कि अगर यहां इंडस्ट्रीज के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाये, फोर लेनिंग की जाए, बिजली और टेलीफोन की और दूसरी सुविधाएं दी जाएं तो आज जो इंडस्ट्रयलिस्टस दिल्ली में भटक रहे हैं वह हरियाणा की तरफ अट्रैक्ट हो सकेंगे। पूरे प्रदेश का एग्जोस्टिव प्लॉन इस तरह बनाया जाए और इस तरह का माहौल बनाया जाए ताकि इंडस्ट्रयलिस्टस हरियाणा की तरफ अट्रैक्ट हो सकें।

अध्यक्ष महोदय, जिस समय आपने मुझे पिछले बजट अधिवेशन में बोलने का समय दिया था उस समय भी मैंने जिक्र किया था कि हरियाणा और पंजाब के किसानों को W.T.O. के तहत बहुत बड़ी मार पड़ने वाली है। स्पीकर सर, इतनी बड़ी मार कि हरियाणा में यहां गेहूँ और चावल ये दो फसलें उगाई जाती हैं और आज तक गेहूँ के समर्थन मूल्य की भी घोषणा नहीं की गई है। दूसरी तरफ खाद्य और दूसरे इनपुट्स की कीमतों में वृद्धि हो रही है। आज ऐसा लगता है कि प्रोक्योरमैंट के बारे में मुख्य मंत्री जी ने जो आश्वासन किसानों को समर्थन मूल्य के बारे में दिया है वह समर्थन मूल्य किसानों को मिलने वाला नहीं है। पता नहीं जो समर्थन मूल्य किसानों को पहले दिया जा रहा है उस पर भी प्रोक्योरमैंट हो पायेगी या नहीं। स्पीकर सर, जैसा कि मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि लिबरेलाईजेशन का मामला कांग्रेस सरकार के समय में शुरू हुआ था इस बारे में मैं कहना चाहूँगा कि यदि किसी सरकार की

पॉलिसीज पूरी तरह से ठीक न हों तो उन्हें मोडीफाई किया जा सकता है, उन्हें इम्प्रूव किया जा सकता है। इसलिए मैं सदन के नेता से निवेदन करना चाहूँगा कि हरियाणा में गेहूँ और चावल की दो ही फसलें मुख्य तौर पर उगाई जाती हैं इसलिए अगर क्रोप डाईवर्सीफिकेशन नहीं होगी, क्रोप रोटेशन को बदला नहीं जायेगा तो हमारे किसानों को बहुत नुकसान होगा और गरीब किसान उजड़ जायेगा। इसलिए मेरा यह सुझाव है कि क्रोप डाईवर्सीफिकेशन के नाम से बजट में एलोकेशन होनी चाहिए और किसानों को दूसरी फसलों की तरफ प्रोत्साहित करना चाहिए। किसानों को दूसरी फसलों की तरफ प्रोत्साहित करने के लिए हिसार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी को जिम्मेवारी सौंपी जानी चाहिए। वे हरियाणा के किसानों को बतायें कि किस ढंग से नई फसलें उगाई जायें, नई फसल की हर चीज के बारे में किसान को जानकारी देनी चाहिए ताकि किसान को अच्छी आमदनी हो। स्पीकर सर, अब मैं मेरे हल्के की कुछ समस्याएं यहां रखना चाहूंगा कि मेरे हल्के बेरी में सड़कों की बहुत बुरी हालत है। स्पीकर सर, आप मेरे हल्के में आये थे आपने भी देखा था कि वहां सड़कों कि कितनी खराब हालत है। इस बारे में मैंने बजट अधिवेशन 2000-2001 और 2001-2002 में भी जिक्र किया था कि मेरे हल्के की 16 सड़कों की बहुत खराब हालत है। उस समय मुख्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि जून, 2001 तक सभी सड़कें बन जायेंगी, फिर 2002 में भी यह बात आई लेकिन खेद की बात है कि वहां पर सड़कों पर माईनर रिपेयर जरूर हुई लेकिन मेजर रिपेयर नहीं हुई है। वहां के लोग कहते हैं कि बेरी से अपोजीशन का विधायक होने के कारण वहां के लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। **(इस समय माननीय उपाध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।)** उपाध्यक्ष महोदय, वहां कुछ सड़कें ऐसी हैं जिनमें 1995 की बाढ़ में तीन-तीन फिट के गड्ढे पड़ गये थे और वे आज तक भी ठीक नहीं किए गये हैं। डीघल रोड़ पर बेरी और दुबलधन की सड़कों में तीन-तीन फिट के गढ्ढे पड़े हुए हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से आपके माध्यम से पूछना चाहूँगा कि इन सड़कों का निर्माण कब तक किया जायेगा और कब वहां के लोगों को राहत मिलेगी? उपाध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त खेद की बात यह है कि सी.ऐ.जी. की रिपोर्ट जो अभी-अभी आई है उसके मुताबिक फिसकल डैफीसिट सरकार के कंट्रोल से बाहर है और इसमें साफ लिखा है कि यह लैक ऑफ फाईनैंशियल मैनेजमैंट की वजह से है। हमारी पर-कैपिटा इन्कम डाउन न चली जाये इस बात का हमें ख्याल रखना चाहिए। हमारे प्रान्त की खुशहाली के नाम पर देश में और दूसरे प्रदेशों में गिनती होती है। यह मेरा सुझाव है कि हम गरीबी की तरफ न चले जाएं, हमारी पर-कैपिटा इन्कम डाउन न हो जाए तो इस तरफ हमें सोचना चाहिए। मेरा आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी को और मुख्य मंत्री जी को सुझाव है कि इसमें फाईनैंशियल मैनेजमैंट की तरफ ध्यान दिया जाये क्योंकि आज बजट में तो विकास के कार्यों की घोषणाएं होती नहीं और फील्ड में मुख्य मंत्री जी की घोषणाओं पर कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है इस बारे में मेरा सुझाव है कि वित्त मंत्री जी को स्वतंत्रता दी जाये कि बजट प्लान को ठीक ढंग से लागू कर सकें। अगर मौजूदा ढांचे के अनुसार इसी तरह से मामला चलता रहा तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। क्योंकि ये दो साल की जो एन्युअल योजना है इसमें हमारी 1000 करोड़ रुपये की गिरावट आ गई है। आप देखेंगे कि वर्ष 1999-2000 की जो प्लान थी वह 1815 करोड़ रुपये की थी और अब तीन सील के बाद भी इतनी ही आई है। इसमें इन्फलेशन लगाकर देखें कि एक्चुअल प्लान कितनी घट गई होगी। इन बातों के साथ मैं बजट के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। अत: उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो सुझाव दिए हैं उन बारे मुझे उम्मीद है कि सरकार उन पर गौर फरमायेगी। अंत में उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हुए मैं अपना स्थान लेता हूँ।

चौधरी बंसी लाल (भिवानी) : उपाध्यक्ष महोदय, बजट जो है वह खाली आंकड़े जोड़ने के लिए नहीं होता। यह सरकार का एक पॉलिसी डिसीजन होता है, पॉलिसी डिकलेरेशन होता है। पर हम प्रदेश को किस तरफ से और कहां लेकर जाएंगे, यह हमें देखना होगा। वित्त मंत्री जी ने कोशिश तो की है मगर इनको कामयाबी कम मिली है और बजट एट ए ग्लांस अगर हम एक पेज पर देखें तो मॉम प्लॉन एक्सपैन्डीचर पर इन्होंने 2001-02 में बजट ऐस्टिमेटस में 801643 लाख रुपये दिखाया है और रिवाइज्ड ऐस्टिमेटस 845599 लाख रुपये दिखाया है। आप

[चौधरी बंसी लाल]

देखेंगे कि यह 43956 लाख रुपये बढ़ गया। इसी प्रकार से प्लान साइड में बजट ऐस्टिमेटस 2001-02 में 252068 लाख रुपये दिखाया है और रिवाईज्ड एस्टिमेटस 222243 लाख रुपये दिखाया है। इसमें आप देखेंगे कि 298.25 लाख रुपये घट गया। मैं प्लान एक्सपैन्डीचर के बारे में वित्त मंत्री जी को कहना चाहूँगा कि जब तक यह नान प्लान एक्सपैन्डीचर कम नहीं करेंगे उस वक्त तक प्रदेश का गुजारा नहीं होगा। नॉन प्लॉन एक्सपैन्डीचर कम होना चाहिए और प्लॉन एक्सपैन्डीचर पूरा हो, इसको और ज्यादा करने की कोशिश करो तो और भी अच्छी बात है। लेकिन एक तरफ सरकार कहती है कि तरक्की कर रहे हैं और दूसरी तरफ तरक्की वाले काम के बजट घट रहे हैं, इनको मैं ठीक नहीं समझता और आपने जो 2002-03 का रिसीट एक्सपैन्डीचर बताया है उसमें 105623 लाख रुपये डैफिसिट है। डैफिसिट तो हो लेकिन डैफिसिट किसी परपज पर हो। उपाध्यक्ष महोदय, जो हमने लोन ले रखा है वह हम पेमैंट करते हैं, इन्ट्रस्ट पेमैंट 14 परसेन्ट, लोन रीपेमैंट 25 परसैंट यानि 39 परसैंट हम हर साल लोन की पेमैंट में देते हैं और पैण्डिग डैट से बजट में दिखाया गया है कि 37 पैसे आयेगा। 37 पैसे जो आयेगा और 39 पैसे आप देंगे, इसका मतलब 2 पैसे घर से मिलाकर देंगे तो फिर यह लोन कैसे उतरेगा ? क्योंकि सरकार तो लोन देने के लिए लोन ले रही है तो यह जो चीज है, मैं समझता हूँ कि यह कोई हैल्दी प्रैक्टिस नहीं है। जहां तक डैफिसिट का सवाल है, डैफिसिट होता है। 1997-98 में डैफिसिट था 1127 करोड़ रुपये और 1998-99 में यह डैफिसिट हो गयी 2240 करोड़ रुपये क्योंकि 1200-1300 रुपये का एकदम पे-कमीशन आ गया। हमने डैफिसिट के ट्रैण्ड को घटाने की कोशिश की। अगले साल 1999-2000 में यह 2132 करोड़ रुपये हो गया और उससे अगले साल 2000-2001 में बढ़ कर 2265 करोड़ और उससे अगले साल 2001-2002 में बढ़ कर 2687 करोड़ रुपये अब 2002-2003 में यह 2617 करोड़ रुपये तक का आने का अनुमान है। यह भी कोई बहुत हैल्दी बात नहीं है। डैट सर्विसिज में कर्जा तो आप लेते जाइये लेकिन कर्जा लेने के बाद यह भी देखना होगा कि देंगे कहां से ? जब तक आप इन्कम नहीं बढ़ाएंगे उस वक्त तक आप कर्जा कहां से चुकाएंगे। डैट सर्विसिज इन्ट्रस्ट पेमैंट्स से देंगे तो यह बजट एट ए ग्लांस पेज 9 पर लिखा है कि 2002-2003 में 1998 करोड़ का ब्याज देंगे और आगे यह बढ़ता जाएगा और अब आपने जो 14% दिखाया है डैट यह आगे जाकर 22-23% होने वाला है। आप इसे चुकाएंगे कहां से ? रिपेमैंट ऑफ लोन्ज से आपने इस साल चुकाया है 2795 करोड़ रुपये अगले साल यह हो जायेगा 3631 करोड़ रुपये। आपकी आउटस्टैंडिंग लायब्लिटीज हैं जिसमें लोन और गारन्टी दोनों हो गई। वर्ष 2000-2001 में कर्जा टोटल था 14264 करोड़ रुपये। 2001-2002 में 16,949 करोड़ रुपये, 2002-2003 में यह बढ़ कर 19,297 करोड़ रुपये हो जाने का अनुमान है। आप लोन ले रहे हैं सड़क बनाने के लिए, लोन ले रहे हैं दूसरे कामों के लिए भी लोन ले रहे हैं। हुडको से भी लोन ले रहे हैं। हुडको से जो लोन लेकर आप सड़कें बना रहे हैं उन सड़कों की क्वालिटी भी आप चैक करवा लें। पहले कई जगहों पर सड़क ठीक बन रही थी। लोहारू से दादरी तक और दादरी-झज्जर और बहादुरगढ़ की सड़क बन रही थी। उसको लोहारू की तरफ से चालू किया हुआ था तो काम ठीक हो रहा था और रोड़ी पड़ रही थी और जो मैटीरियल लगना चाहिए था अब वह नहीं लग रहा है। अब तो वे ऐसा करते हैं कि जो मिट्टी होती है उसकी जगह पहाड़ की जिस रेती को पहाड़ का पत्थर निकालने के लिए ठेकेदार मुफ्त में उठाता है और ट्रक भी मुफ्त भर देते हैं वही रेत सड़क पर डाल कर थोड़ी रोड़ी डाल कर तारकोल डाल देते हैं। वह सड़क चलने वाली नहीं है। क्वालिटी कंट्रोल किए बगैर आपका काम चलेगा नहीं और आप लोग जो लोन ले रहे हैं सड़कों के लिए अगर आप लोन के लिए नैगोशियेट करें वर्ल्ड बैंक से तो वर्ल्ड बैंक का लोन मेरे ख्याल से 9% से ज्यादा इन्ट्रस्ट पर नहीं पड़ेगा और अब तो शायद 8% ही पड़ेगा। इसका पूरा रुपया भी आपको देना पड़ेगा, 70 या 75% आपको देना है बाकी भारत सरकार देती है। बाकी जो देना है वह होता भी लोंग टर्म लोन है। आप 11%, 12% पर हुडको से लोन लेंगे तो वह आपको बहुत महंगा पड़ेगा और सड़कों की बात मुझे याद आ गई हमारे हरियाणा में सबसे डिफिकल्ट सड़क जो चलने में है वह सड़क कोटपुतली, नारनौल, महेन्द्रगढ़, चरखी दादरी, भिवानी, जीन्द है। आप यह सोचिएगा कि

इस सड़क के ऊपर नारनौल से दादरी के बीच में चलने के लिए जगह नहीं मिलती है। अगर रात को वहां पर चले जाएं तो वहां पर रोज 2-3 एक्सीडैंट हुए जरूर मिलेंगे। हमने इस सड़क को नैशनल हाई-वे बनाने के लिए लिख कर दरख्वास्त दी हुई है क्योंकि यह सड़क कोटपुतली से पटियाला तक जा सकती है। हमारी और सड़कें नैशनल हाई-वे बन चुकी हैं, पता नहीं उस दरख्वास्त का क्या कर रहे हैं। इसके अलावा कैप्टन अजय सिंह ने यहां पर एक सवाल किया था और उसके जवाब में मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि रिवाड़ी में नारनौल वाली सड़क पर पुल बनाने का प्रावधान तो है लेकिन झज्जर तक की सड़क के ऊपर पुल बनाने का कोई प्रावधान नहीं है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ और वित्त मंत्री जी, आपको पता भी होगा बावल, रिवाड़ी, झज्जर, रोहतक, जींद, नरवाना और संगरूर वाला रोड़ नैशनल हाई-वे बन चुका है। जिस सड़क के बारे में मैंने नैशनल हाई-वे बनाने के लिए कहा है आप उस बारे में भारत सरकार से कहें। आप चाहे रिवाड़ी के लिए नारनौल वाले पुल से चले जाएं या झज्जर के पुल से चले जाएं दोनों तरफ से आपको फाटक बंद मिलेगा। वहां पर ट्रैफिक बहुत ही ज्यादा है और उस ट्रैफिक को निकालने के लिए वहां पर पुल दोनों तरफ बहुत जरूरी है।

वित्त मंत्री जी ने कहा कि सैलरीज एंड पेंशनर्ज की तनख्वाह के ऊपर 46.28 प्रतिशत खर्च होंगे। मेरे ख्याल से आपको दोबारा से इसको चैक करना होगा इसमें 55 प्रतिशत के करीब होगा (विघ्न) आपने 46.28 प्रतिशत लिखा हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, जो बजट है उसमें पिछले साल के आंकड़े दिखाए गए हैं उसमें वित्त मंत्री जी ने कहा था कि 233.86 करोड़ रुपए का घाटा रहेगा इसमें भी माईनस बैलेंस रहेगा, वह 288.19 करोड़ रुपए हो गया था। इन्होंने 2001-02 में डैफिसिट लगाया था कि यह 55 करोड़ रुपए का रहेगा हकीकत में यह 171.70 करोड़ रुपए हो गए हैं। सबसे खराब बात जो हो गई है वह यह कि इस साल का 200 करोड़ रुपए का घाटा होगा यह बताया गया है। मैं समझता हूँ कि 200 करोड़ के घाटे में सार नहीं सकेंगे अगर 55 करोड़ का जब 190 करोड़ हो गया तो 200 करोड़ 700 या 800 करोड़ होगा। (शोर एवं व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, डैफिसिट ट्रैंड जो हमारा है वह कोई उत्साहजनक बात नहीं है। डैफिसिट के बारे में मैंने बताया कि इसमें 21-3-99--2000 से लेकर 2617 करोड़ रुपए हो गया तो इससे आपका गुजारा कैसे होगा ? यही आंकड़े आपने बजट स्पीच में लिखे हैं। डैड लाईब्लिटीज जो हैं वह आउटस्टैंडिंग बढ़ता ही बढ़ता जा रहा है। डैड सर्विसिज का भी मैंने आपको बताया लेकिन जो सबसे गम्भीर मामला है वह नॉन प्लान एक्सपैंडिचर बढ़ने का और घटने का है। इसमें आपने जो 2001-2002 में बजट एस्टीमेट दिया था उसका 7 प्रतिशत घाटा रहा है और प्लान एक्सपैंडिचर साढ़े चार प्रतिशत ही रह गया।

अब एक्साईज के बारे में वित्त मंत्री जी ने पिछले साल कहा था कि हमको 924 करोड़ रुपए की आमदनी होगी लेकिन इनकी आमदनी 870 करोड़ रुपए की ही हुई। अगर 924 करोड़ रुपए की आमदनी होती तो इनकी पिछले साल की इन्क्रीज 9.27 करोड़ की होती। मैंने पिछले साल भी वित्त मंत्री सम्पत सिंह जी से पूछा था कि क्या आपको पूरी उम्मीद है कि यह आपका 9.27 करोड़ हो जाएगा ? तो इन्होंने कहा था कि मुझे पूरी उम्मीद है कि यह पूरा हो जाएगा लेकिन यह हो गया साढ़े तीन प्रतिशत। अब इन्होंने 2002-2003 के बजट एस्टीमेटस में एक्साईज के लिए 940 करोड़ रुपए दिखा" है that is 8% increase Ch. Sampat Singh Ji, I think it is not possible और अगर पोसिबल है तो वित्त मंत्री जी अपनी स्पीच के वक्त जरा सदन को भी बता दें। उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से जहां तक पावर का मामला है। 31-12-2001 को सरकार कहती है कि 1460.90 करोड़ की पावर लाईब्लिटीज होंगी। फिर रामकिशन फोजी ने जब इस बारे में एक प्रश्न पूछा तो एक नोट देकर कह दिया कि 994 करोड़ के जो बांड जारी किये गये हैं वह इसमें शामिल नहीं है इसका मतलब यह बन गया 2454 करोड़ 90 लाख रुपए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि पावर में सरकार क्या कर रही है? पावर में मिस-मैनेजमैंट है। भारत सरकार की पोलिसी है कि अलग-अलग कम्पनियां बनाकर इंडीपैंडैन्ट बनाओ और उनको इंडीपैंडैन्टली काम करने दो। पावर लोसिज बड़े हैवी है। पावर लोसिज को घटाने की कोशिश की जाए। जब तक किसी प्राईवेट आदमी के पास इसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा with the full backing of the Government उस वक्त तक लाइन लौसिज नहीं

[चौ. बंसी लाल]

घटेगा इसलिए पावर सैक्टर में मुझे खास चिंता है कि क्या होने जा रहा है ? पांच साल के बांड तो पावर सैक्टर के इस सरकार ने जारी कर दिए, कब देने पड़ेंगे, जो कोई मुख्य मंत्री होगा वह भुगतेगा इस सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। खर्च किया खत्म किया।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : उपाध्यक्ष महोदय, ए.बी.बी. कम्पनी का भी तो हम भुगत रहे हैं। काम इन्होंने करे और भुगत हम रहे हैं।

चौ. बंसी लाल : ए.बी.बी. को भुगतने वाले ही भुगतेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, आप इनसे कहिये कि ये थोड़ी देर चुप रहेंगे तो फायदा रहेगा।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : उपाध्यक्ष महोदय, ये ए.बी.बी. के बारे में भी थोड़ा सा स्पष्ट करें ताकि पूरे सदन को पता लग जाए। बावजूद विरोध के इन्होंने ए.बी.बी. को दिया और वह यूनिट खोलकर छोड़ दी जिससे तीन सौ करोड़ रुपए का घाटा हो गया। 110 मेगावाट बिजली तीन वर्ष से नहीं मिल रही है। उपाध्यक्ष महोदय, ये थोड़ा सा इस बारे में भी स्पष्ट कर दें।

चौ. बंसी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, हमने ए.बी.बी. को भी ठीक सोच समझकर दिया था। सब एक्सपर्टस ने बैठकर फैसला किया था लेकिन इन साथियों ने क्या झगड़ा किया मुझे पता नहीं। दिया हमने था और हमारे टाइम में चलता भी रहा लेकिन इन्होंने आकर उसको बंद कर दिया। (विघ्न)

प्रो. सम्पत सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, वह इनके टाइम में बंद हो गया था।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : उपाध्यक्ष महोदय, ये हाउस को क्यों गुमराह कर रहे हैं ?

चौ. बंसी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक सच्ची बात को एक बार कहूँ और ये एक गलत बात को सौ बार कहें जिस पर इनको विश्वास है तो मेरे पास उसका कोई जबाब नहीं है।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : उपाध्यक्ष महोदय, ये तो हाउस के बड़े सीनियर मैम्बर हैं लेकिन ये हाउस को गुमराह कर रहे हैं। वह इनके समय में बंद हुआ और इनके वक्त का ही पचास-साठ करोड़ रुपए के वर्क का सामान पड़ा है। तीन सौ करोड़ रुपए का नुक्सान प्रदेश ने भुगत लिया है। हम तो आर्बीट्रेटर में गए हैं हमने तो आपको यह कहा कि चौधरी साहब इसको मत दो लेकिन आपको केवल कमीशन खाने की जो आदत थी वह नहीं गयी। आपने नहर में भी कमीशन खाया। आपने कमीशन खा-खाकर प्रदेश का बेड़ा गर्क कर दिया है।

वैयक्तिक स्पष्टीकरण--

चौ. बंसी लाल एम.एम.ए. द्वारा

चौ. बंसी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पर्सनल एक्सप्लेनेशन है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरी न कमीशन खाने की आदत है और न मुझे कमीशन खाना आता है। कमीशन खाने का तरीका तो यह होता है कि कोई भी चीफ मिनिस्टर कभी बिजली बोर्ड की परचेज कमेटी का चेयरमैन नहीं बना लेकिन मुख्य मंत्री जी इस परचेज कमेटी के चेयरमैन हैं। यह कमीशन के लिए ही होता है यह ऐसे नहीं होता है।

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : उपाध्यक्ष महोदय, हाई पावर परचेज कमेटी का चेयरमैन बनने के बाद उसमें कितना सुधार आया है जरा इसकी चर्चा भी थोड़ी सी कर दें। पहले जिनको चेयरमैन बनाया जाता था उससे पैसा खाया जाता था लेकिन हम बाकायदगी चैकिंग करते हैं। न एक पैसा हमारी सरकार में कोई खाएगा और जिन्होंने खा रखा है हम उससे वसूल भी करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : बंसी लाल जी, आप यह बता दें कि किस डेट से पानीपत थर्मल प्लांट की दूसरी यूनिट बंद है ?

चौ. बंसी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, इस बारे में ये ही बताएंगे क्योंकि वह इनके वक्त में ही बंद हुआ है। (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय, अगर इस तरह से ये बोलते जाएंगे तो मेरे बोलने का टाईम कहां रह जाएगा।

श्री कृष्ण लाल : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। सर, अभी जैसा मुख्य मंत्री ने सदन में पानीपत थर्मल प्लांट की दूसरी यूनिट के बारे में ए.बी.बी. कम्पनी का जिक्र किया। वह जनवरी 1999 के अंदर जब चौधरी बंसीलाल जी की सरकार थी, पानीपत थर्मल प्लांट की नम्बर एक और दो यूनिट जो 110-110 मेगावाट की हैं, उनमें केवल आठ मेगावाट बढ़ाने के लिए तीन सौ करोड़ का ठेका दिया था और वह प्लांट 1999 में बंद हुआ था इसके साथ में जब एक नंबर प्लांट चलता रहा, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने आदेश देकर और 4-5 करोड़ रुपया लगाकर के एक नम्बर को बी.एच.ई.एल. से ओवरहाल करवाया आज यह 110 मेगावाट प्लांट लोड दे रहा है अब इसका प्लांट लोड फैक्टर 114 मेगावाट तक बढ़ा है।

वर्ष 2002-2003 के लिए बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

चौ. बंसी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, हमने एक या दो नहीं चारों प्लांटों का एग्रीमैंट किया था। 30-32 परसैंट प्लांट लोड फैक्टर पर वे चलते थे उस कम्पनी ने वादा किया था कि 110 मेगावाट का 118 मेगावाट का हर प्लांट कर देंगे और 118 मेगावाट करके 80 परसैंट प्लांट लोड फैक्टर 6-6 महीने सब के सब चलाकर देंगे। ये फैसला हुआ था। उपाध्यक्ष महोदय, एक साइबर सिटी गुड़गांव में बन रही है मुझे ताज्जुब यह है कि वह प्राइवेट सेक्टर को दी जा रही है जबकि प्राइवेट सेक्टर को देने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी उसको हुड्डा भी कर सकता है और एच.एस.आई.डी.सी. भी बखूबी कर सकती है। जो प्राइवेट पार्टी को दिया गया है इसमें हरियाणा सरकार को कम से कम 200-300 करोड़ रुपए का लौस हुआ है। उनको यह कैसे दिया गया, क्यों दिया गया ? न तो उनसे कोई लाइसैंस फीस के पैसे लिए गए, न सी.एल. यू. के पैसे लिए, कुछ भी नहीं लिया। एक खैरात बांट दी गई। एक तरफ कहते हैं कि पैसे की कमी है मैं मानता हूँ कि पैसे की कमी है लेकिन एक तरफ कमी है दूसरी तरफ खैरात बांटते हैं। कैसे काम चलेगा। अभी तो ये एक प्राइवेट पार्टी को दिया है, अभी तो पता नहीं कहां तक पहुँचेंगे ? मैं समझता हूँ कि इससे स्टेट ऐक्सचैकर पर 200-300 करोड़ रुपए की चोट है। एक चौधरी सम्पत सिंह ने बजट में पैरा नं. 96 लिख दिया। इसमें लिखा है कि 'हमारी सरकार इस सिद्धान्त में पूर्ण विश्वास रखती है कि प्रजातंत्र में शासन लोगों का है, लोगों के लिए हैं और लोगों के द्वारा चलाया जाता है इसलिए शासन को लोगों की भावनाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप बनाना हमारा मुख्य लक्ष्य है। मैं समझता हूँ कि इसे इनको स्पीच में से निकाल देना चाहिए ये बिल्कुल ही गलत है, इस पैरा में कोई सच्चाई नहीं है यहां इससे उलट काम है।

श्री उपाध्यक्ष : बंसी लाल जी, आप वाइंड अप करें। आपको बोलने के लिए 12 मिनट का समय तय था। आपको बोलते हुए 25 मिनट हो गए हैं।

चौ. बंसी लाल : मैं थोड़ी देर में वाइंड अप कर देता हूँ। सरकार ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई स्कीम का जो कर रही है, ट्यूबवैल लगा रही है मैं बताना चाहूँगा कि सैलो ट्यूबवैल कभी भी पोटेबल नहीं होता जब तक कि दरिया के किनारे न हो। जो देहात हैं उनमें सैलो ट्यूबवैल लगाकर वाटर सप्लाई कर रहे हैं मैं बता देना चाहता हूँ कि इससे वाटर बोर्न डिजिजिज पैदा होंगी और लोगों को तकलीफ होगी। मैं सरकार को सुझाव देना चाहूँगा कि डीप ट्यूबवैल बोर करा कर लोगों को पीने के लिए पानी दिया जाए ताकि लोगों की सेहत ठीक रहे। उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री

[चौ. बंसी लाल]

जी ने मेरे भाई के ऊपर इल्जाम लगाया है कि वह बेनामी गिगाना पहाड़ को चलाते रहे हैं। मेरे भाई ने कोई बेनामी पहाड़ नहीं चलाया, कोई ब्लैकमार्किट का धंधा नहीं किया वह बिल्कुल साफ है। यह तो जब तिलक उधड़ेगा तब पता चलेगा कि बेनामी कहां की है, किस की है और कैसी है ? जहां थोड़ा-सा झगड़ा होने पर पुलिस छावनी बना दी जाती है हजारों रुपए की पर्ची टोल टैक्स की तरह कटती है। सेल टैक्स क्रशर वाले ने ले लिया, मैटीरियल की कीमत ले ली, रॉ मैटीरियल भी लिख दिया, उसके आगे सेल टैक्स भी लिख दिया। एक माल का एक ट्रक, एक ड्राइवर का नाम और एक ही टाइम और उस पर दो दफा सेल टैक्स लिया जा रहा है, दो दफा मैटीरियल की कीमत ली जा रही है। उपाध्यक्ष महोदय, यह जो चीजें हैं कि कब तो नीलामी हुई, कब ऐग्रीमेंट हुआ और कब ये ठेके बैठे क्योंकि असल में बेनामी का जो सौदा है (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष : बंसी लाल जी, आप बैठ जाएं। मुख्य मंत्री जी बोलेंगे।

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : उपाध्यक्ष महोदय, चौधरी बंसीलाल जी कह रहे हैं कि वहां पर कैम्प बैठा दिये हैं पुलिस लगा दी। आपके वक्त में तो जो नीलामी की थी तीन महीने प्रयास किये, ट्रैक्टर जलाये गये पुलिस बैठाई गई तब जाकर आपने उनसे साजबाज सटपट करके उनको 54 लाख रुपए में दिया। हमने उस पर कंट्रोल किया और जो आप 54 लाख रुपये में नीलाम किया करते थे अब वे खानें सात करोड़ की बिकी हैं और दनादन चल रही हैं। पहले जिन लोगों ने लिया था आपके भाई की भी चर्चा बतायी जायेगी लेकिन वे साल के 40 हजार रुपये दिया करते थे जो कि अब हमें उनके एक करोड़ 72 लाख रुपये मिल रहे हैं। अब यह बजट स्पीच चल रही है। यह रिप्लाई गवर्नर एड्रेस के रिप्लाई में दिया गया था आप तो उस समय भाग गये थे ये सरकारी आंकड़े हैं इनको कोई झुठला नहीं सकता। मैं आपको पढ़कर बता दूं आपके भाई का नाम तो इसमें नहीं है आप मुझे बतायें कि क्या चौधरी रघबीर सिंह सुपुत्र चौधरी मोहर सिंह आपका भाई नहीं है वही ईश्वर गुप्ता के जामन हैं वह उनका पार्टनर है। (शोर)

चौ. बंसी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, पार्टनर है लेकिन गड़बड़ी घोटाला या कोई घपला कभी नहीं हुआ आप इस बारे में इंक्वायरी करवायें और जो दोषी हो उसको सजा दें।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : उपाध्यक्ष महोदय, हम तो जो दस साल पहले घोटाले हुए हैं उनके बारे में भी इंक्वायरी करवायेंगे और उनसे वसूल भी करवायेंगे।

चौ. बंसी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, जो हजारों रुपये के सेल टैक्स ले रहे हैं उनके खिलाफ भी एक्शन लें और उनके खिलाफ केस दर्ज करायें और केन्द्र की सी.बी.आई. से इस मामले की इंक्वायरी करवायें।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : उपाध्यक्ष महोदय, 12 दिसम्बर से 18 जनवरी के बीच में उनसे 80 लाख रुपये वहाँ से वसूल किये हैं जबकि दस साल पहले रघबीर सिंह जी साल के 40 हजार रुपये दिया करते थे उसकी एवज में अब हम साल के एक करोड़ 72 लाख रुपये ले रहे हैं। पिछले दस साल का भी वसूल लूंगा, बड़ी पीड़ा होगी आपको (शोर)

चौ. बंसी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, यह इल्जाम गलत लगा रहे हैं। हकीकत यह है कि आज एक हजार रुपए प्रति ट्रक लिया जाता है।

श्री उपाध्यक्ष : चौधरी बंसी लाल जी आप मेरी बात सुनिये आपको इस बारे में शायद मालूम नहीं है। इस बारे में गवर्नर एड्रेस पर बोलते हुए माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस बात का रिप्लाई डिटेल में दे दिया है। मैं आपको याद दिला रहा हूँ आप उस समय हाउस में नहीं थे आपने यह इश्यू गवर्नर एड्रेस पर भी उठाया था।

चौ. बंसी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, 30 टन का ट्रेलर रॉ मैटीरियल का ये क्रेशर के रैम्प पर चढ़ाकर दिखा

दें। 15 टन का ट्रक जिसकी रसीद 15 टन के ट्रक की काटते हैं उस ट्रक को रैम्प पर चढ़ाकर दिखा दें अगर रॉ मैटीरियल के पैसे ले रहे हैं। मैं तो यह कहता हूँ कि हरियाणा बना तब से अब तक के इन सारे केसों के बारे सी.बी.आई. की इंक्वायरी करवाई जाये।

श्री उपाध्यक्ष : बंसी लाल जी वाइंड अप कीजिये।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इन पर बहुत तर्स भी आता है। अफसोस भी होता है। बुजुर्ग आदमी हैं। (विघ्न) चौधरी साहब आता तो नहीं रहेगा आवेगा तो तब जब चीपड़ी में हाथ लगेगा तब पता लगेगा कि खोसूड़े आ रहे हैं। चौधरी साहब जिसके आप चालीस हजार रुपये साल के दिया करते थे आपको पता होना चाहिये उसी पहाड़ की 24 रुपये प्रति टन रायल्टी सरकार देती है और क्रेशर वाला 12 रुपये टन के हिसाब से सेल्स टैक्स देता है और यह बीच में रॉ मैटीरियल का 20 प्रतिशत सेल्ज टैक्स था आपके शासन काल में एक नया पैसा वसूल नहीं हुआ वह पैसा कहाँ गया ? आप तो चले गये थे सदन छोड़कर के। सुनने की हिम्मत नहीं है भाग जाते हो लेकिन कितने दिन टलोगे। हम तो मौका देखकर बता देंगे आपको। आपने तो समझा कि पैंडा छूट गया।

चौ. बंसी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, जो मुख्य मंत्री जी कह रहे हैं उस बारे में मैं इन्हें बता दूं। मेरे ऊपर जो इल्जाम लगाया है वह बेबुनियाद है। मैंने न कभी पत्थर का काम किया न कोई धंधा किया। लेकिन आज यह बगैर ठेका हुए यानी 15 लाख रुपये रोज का जाता है यानी साढ़े चार करोड़ रुपये महीने के वे कहां जाते हैं ? इस साढ़े चार करोड़ रुपये महीने के बारे में केस रजिस्टर करके सी.बी.आई. को दिया जाये। मैं कहता हूँ जब से स्टेट बनी तब से आज तक के केस ऐसे के ऐसे सी.बी.आई. को दे दो मुझे कोई एतराज नहीं है।

12-00 बजे **कैप्टन अजय सिंह यादव (रिवाड़ी) :** उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का समय दिया इसके लिए आपका धन्यवाद। आज मुझे इस बात का अफसोस है कि बजाय रोजगार देने के जो कि सरकार की एक अहम् भूमिका होती है, 5400 पोस्टें अबोलिश की जा रही हैं। सरकार आज के दिन पूर्ण रूप से कर्ज में डूब चुकी है। वर्ष 1998-99 में टोटल डैबिट 29.16 परसैंट था, 2000-2001 में यह बढ़कर 34.37 परसैंट, 2001-2002 में 35.28 परसैंट और आज बढ़कर 37 परसैंट हो गया है। इस प्रकार से 1998-99 में लोन रिपेमैंट 11.14 परसैंट था जो बढ़कर 25 परसैंट हो गया है, इन्ट्रस्ट पेमैंट 1998-99 में 11.14 परसैंट था जो बढ़कर 14 परसैंट हो गया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि जो सरकार तकरीबन 50 परसैंट सैलरीज पर और 39 परसैंट इन्ट्रस्ट में देगी तो आप सोच सकते हैं कि यह सरकार विकास के लिए क्या कार्य कर सकती है। उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक एक्सपैंडीचर की बात है तो आज जो सी.ए.जी. की रिपोर्ट पेश हुई है इसमें बाकायदा लिखा हुआ है --

"The Government achieved a decrease in Revenue Deficit by curtailing budgeted expenditure of Rs. 273 crore of subsidy on rural electricification." यानी रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन की सबसिडी को 273 करोड़ रुपए करटेल कर दिया गया उसके बाद रिवैन्यू में डैफिसिट दर्शाया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, एक बात मैं साफ शब्दों में और कहना चाहता हूँ कि जहां यमुनानगर के चुनावों की ये बात करते हैं, यू.पी. के चुनावों में इन्होंने क्या काम किया। इस बजट की किताब में लिखा है — "The capital expenditure increased significantly due to unnecessary procurement of foodgrains for Central pool by nearly Rs. 600 crore ....." फिर ये फूड ग्रेन की बात करते हैं कि फूड ग्रेन हमने हरियाणा से प्रोक्योर की, मेरा सरकार से यह कहना है कि जिस प्रकार यू.पी. से फूड ग्रेन आई, हमारे किसान दर-दर भटकते रहे, तकरीबन 600 करोड़ रुपए सरकार ने प्रोक्योरमैंट के लिए खर्च किया। उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक घपलों की बात है तो अम्बाला में एक्साइज डिपार्टमैंट में किस तरह से सैक्रेटरी के साइन से स्टेट बाउचर से पैसा निकलता रहा, सरकार की तरफ से वहां कार्यवाही भी हुई है। फिर ये आज घाटे की बात करते हैं। इनका जो नाइन्थ फाइव इयर प्लॉन का आउट-ले था वह 11600 करोड़ रुपए का था और यह इस वर्ष में साफ होने वाला है। मंहगाई बढ़ने के बावजूद भी टैन्थ फाइव

[कैप्टन अजय सिंह यादव]

इयर प्लॉन में 11250 करोड़ रुपया रखा गया है जबकि नाइन्थ फाइव इयर प्लॉन में 11600 करोड़ रुपया रखा गया था और फिर ये कहते हैं कि इसमें हमने 40 परसैंट इन्क्रीज किया है। एक्चुयल एक्सपैंडीचर 8019.25 करोड़ रुपया रखा गया है। इस प्रकार वर्ष 2001-2002 का एनुयल प्लॉन 1838.68 दर्शाया गया था जबकि उसका आउट-ले 2150 करोड़ था। इस साल इन्होंने 1922 करोड़ का रखा है, अब मंहगाई बढ़ चुकी है जहां 2001-2002 में 2150 करोड़ का आउट-ले रखा गया था वहीं अब वर्ष 2002-2003 में 1922 करोड़ रुपये रखा गया है। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, जो यह 4.5 परसैंट प्रोजैक्शन दिखाया गया है यह गलत है, यह हाइपोथैटिकल है। प्राइस इंडेक्स पूर्ण रूप से बढ़े हैं और बजट में डैफिसिट 202 करोड़ रुपए का दिखाया गया है। मैं कहना चाहता हूँ कि ये कम से कम 400-500 करोड़ रुपये का डैफिसिट है और सरकार ने ऐसा कोई तरीका नहीं दिखाया कि किस तरह से इसको वसूल करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने एक काम और किया है, वोकेशनल ट्रेनिंग जिसको ये इतना स्ट्रैस करते हैं उसमें 2001-2002 में 46.10 करोड़ रुपये रखा गया था, उसको घटाकर 45.21 कर दिया है। उपाध्यक्ष महोदय, आपका इलाका और मेरा इलाका दिल्ली के साथ लगता है, इंडस्ट्रीज में इन्होंने 1.10 परसैंट कम किया है तो इससे जो टैक्नीकल हैडिड पर्सनज हैं वे कहां जाएंगें। उपाध्यक्ष महोदय, 2001-2002 में इनरोलमैंट ऑफ स्टूडैंटस 23.91 लाख था, वर्ष 2002-2003 में ये घटकर 20.17 लाख हो गया है यानि पौने चार लाख स्टूडैंटस की कमी सरकारी स्कूलों में हो गई है। उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं रिवैन्यू डिपार्टमैंट के बारे में कुछ कहना चाहूँगा, यह मामला मैंने पहले भी उठाया था कि को-आपरेटिव सोसायटीज के जो मैम्बर्ज हैं। वे यदि 50 हजार रुपए से अधिक लोन लेते हैं तो उन पर रैवेन्यू विभाग ने डेढ़ प्रतिशत स्टैंप डयूटी लगा दी है, यह कोआपरेटिव एक्ट के खिलाफ है। इस बारे में मैं मुख्य मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि यह जो डेढ़ प्रतिशत स्टैंप डयूटी लगाई है यह गलत है, यह नहीं लेनी चाहिए और इससे किसानों के साथ ज्यादती होगी। उपाध्यक्ष महोदय, एग्रीकल्चर प्रोडैक्शन 1999-2000 में 17.48% था जो घटकर 2001-2002 में 15.45 % हो गया है। इसी तरह से ऑयल सीडस में भी गिरावट आ रही है। उपाध्यक्ष महोदय, जो इलैक्ट्रीकल कन्ज्यूमर्ज हैं चाहे इण्डिस्ट्रीयल हैं, चाहे ट्यूबवैल के हैं इनकी तादाद में भी कमी हुई है। लिट्रेसी के मामले में ये कह रहे हैं कि हमारा प्रदेश आगे है लेकिन इस बारे में मैं बताना चाहूँगा कि लिट्रेसी में हमारे प्रदेश का देश में 20वां नम्बर है। जहां तक रोजगार की बात है, पब्लिक सैक्टर में रोजगार भी कम हो रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, सिंगल फाईल सिस्टम होने से कर्मचारियों की रिट्रैंचमैंट अधिक होगी। रिट्रैंचमैंट के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि इन्होंने दर्शाया है कि 5400 कर्मचारी रिट्रैंच किए हैं लेकिन वास्तविकता यह है कि 20,000 से अधिक कर्मचारी रिट्रैंच हुये हैं। म्गरपालिकाओं के अंदर, हरको फैड के अंदर, होस्पिटीलिटी के अंदर, हांसी स्पिनिंग मिल के अंदर, टूरिज्म के अन्दर और हरियाणा मिनरल्ज के अंदर कर्मचारियों की बहुत अधिक रिट्रैंचमैंट हुई है। एम.आई.टी.सी. के अंदर 682, कॉनफैड के अंदर 623 कर्मचारियों को रिट्रैंच किया गया है। इसी तरह से डी.पी.आई. के अंदर भी 3200 टीचर्ज सरप्लस करने की बात चल रही है तथा इरीगेशन विभाग के अंदर भी लगभग 4000 पोस्टें अबोलिश की गई हैं। उपाध्यक्ष महोदय, सिंगल फाईल सिस्टम करने से एक्साईज एण्ड टैक्सेशन विभाग और सैक्रेटेरियट के अंदर बहुत ज्यादा रिट्रैंचमैंट होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, जिन कर्मचारियों को इस सरकार ने निकाला था या सस्पैंड किया था उनको वापिस नहीं लिया। वे बेचारे दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। जहां तक 'सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम का सवाल है इस बारे में मैं कहना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम के तहत रिवाड़ी में एक पैसा भी नहीं दिया गया। विधायक डवैल्पमैंट फंड के तहत एच.आर.डी.एफ. का जो पैसा पहले विधायक बांटते थे और बी.डी.ओ. बांटता था उसी पैसे को ये लोग 'सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम के तहत बांट रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक इलैक्ट्रोनिक मीटरों का सवाल है इस बारे में मैं कहना चाहूँगा कि इन मीटरों को गांव रामा के लोगों ने उखाड़ फैंक दिया है, अखबार में भी इस बारे में आया है, यह अखबार मैं सदन में दिखा सकता हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, ट्यूबवैल्ज के बिजली के बिल हमारे यहां स्लैब प्रणाली

के तहत दिए जाते हैं वहां भी स्लैब रेट 65 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपये कर दिये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार 435 करोड़ रुपये इलैक्ट्रोनिक मीटरों पर खर्च करेगी। इस बारे में मैं यह कहना चाहता हूँ कि जहां पर स्लैब प्रणाली के तहत बिजली के बिल ट्यूबवैलों के लिए जाते हैं वहां पर इलैक्ट्रोनिक मीटर क्यों लगाये जा रहे हैं। इसके विरोध में किसानों ने धरने दिये हैं, प्रदर्शन किए हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त किसानों से जबरदस्ती बिजली के बिल वसूल किए जा रहे हैं। कण्डेला काण्ड इसका जीता-जागता उदाहरण है। 25 जनवरी, 1997 को जींद में चौधरी देवी लाल जी के जन्म दिन पर चौटाला साहब ने किसानों को कहा था कि ये किसानों को मुफ्त बिजली, पानी देंगे और लोगों को कहा कि वे बिजली का बिल न भरें। जिसके नतीजन मण्डिआली काण्ड हुआ। मण्डियाली में किसानों पर फायरिंग हुई और काफी किसान मारे गये। उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं हाउस टैक्स के बारे में कहना चाहूँगा कि रिवाड़ी के अंदर पुलिस पहरा लगवाकर, लोगों को और म्यूनिसिपल कमिश्नर को डराकर हाउस टैक्स का बिल पास करवाया। वहां पुलिस की छावनी बैठा दी तथा जिस समय ये यह आर्डिनैंस लेकर आये थे उसमें इन्होंने कहा था कि ये और टैक्स नहीं लगायेंगे लेकिन इन्होंने 2500 रुपए प्रोफैशनल टैक्स रैस्टोरैंटस पर लगा दिया और 1000 रुपये आटा चक्की पर लगा दिया और हर प्रकार से टैक्स लग रहे हैं। ये कहते हैं कि हमारा यह बजट टैक्स फ्री बजट है। (विघ्न) डिप्टी स्पीकर साहब, अब मैं कानून व्यवस्था की बात कहना चाहता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : कैप्टन साहब, वाइंड अप प्लीज, आपको बोलते हुए 10 मिनट हो गये हैं।

कैप्टन अजय सिंह यादव : डिप्टी स्पीकर साहब, मेरे एरिया में जो साबन गांव है, दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर वहां पर राव राम कुंवार सिंह का पेट्रोल पम्प दिन-दहाड़े लूट ले गये। वहां से 14 लाख रुपए लूट ले गए। उस वारदात के बारे में आज तक पता नहीं लगा कि कौन व्यक्ति थे और दिन दहाड़े न नाके बन्दी हो सकी और न कोई और बात हो सकी। इसी प्रकार से उपाध्यक्ष महोदय, कुछ हथियारबंद लोगों ने रिवाड़ी के अन्दर विजय नगर कालोनी में बाकायदा लूटपाट की, उनका भी आज तक कुछ पता नहीं लगा कि वे कौन लोग थे। वे लोग मदन लाल की नकदी ले गए। गांव रोजूवास में पुलिस हिरासत के अन्दर एक नौजवान मारा गया, वह भी आपने अखबार में काफी पढ़ा होगा। इसी प्रकार से मेरे हल्के के अन्दर देवलाबास गांव के 25 वर्षीय जिले सिंह पुत्र भुथर सिंह की मारूति कार ले गए और डहिना के पास उसकी लाश मिली। इस बारे में भी आज तक कुछ पता नहीं लगा। (विघ्न) जो नौजवान लड़के थे वे बाकायदा सचिन होटल में रहे थे लेकिन आज तक पता नहीं लगा कि वे कौन लोग थे जिन्होंने उसको मारा। इसी प्रकार से अल्लबगढ़ के अन्दर हमारी दो बहनों की इज्जत के ऊपर बाकायदा प्रहार किया गया। इस बारे में भी आज तक यह पता नहीं लगा कि किस प्रकार की यह बात हुई है। इसी प्रकार से करनाल के अन्दर माडल टाउन पोस्ट कालोनी में ..... (विघ्न)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : कैप्टन साहब, आप तो सीजन्ड पोलिटिशियन हैं। आप तो बहुत पुराने रहे हैं। क्या इस बारे में बजट में कोई प्रावधान है। आपकी यह बात तो मान सकते हैं कि इलीट्रेसी है, जो पढ़े लिखे हैं, उनको कैसे समझायेंगे। आप तो थोड़ा-सा समझो। आप बजट पर बोलो, समय क्यों खराब कर रहे हो। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष : कैप्टन साहब, आप वाइंड अप करें। (विघ्न)

कैप्टन अजय सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने शुरूआत किस बात पर की थी ..... (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष : कैप्टन साहब, आप वाइंड अप करें। (विघ्न)

कैप्टन अजय सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात अपने होने वाले शहीदों के बारे में कहना चाहता हूँ। हमारे यहां पर बहुत से ऐसे नौजवान हैं, जो शहीद हुए हैं..... (विघ्न) जब चुनाव हुए थे तब आपने कारगिल के अन्दर मरने वाले नौजवानों के लिए सरकार द्वारा बाकायदा घोषणा की थी कि कारगिल के अन्दर शहीद होने वाले नौजवान को 10 लाख रुपये देंगे। आज आपने उस राशि को घटा कर 2.5 लाख रुपए कर दिया है। हमारी जो पैरामिल्ट्री फोर्स है, उनके शहीद होने पर यानि उनको मिलने वाले पैसे को बिल्कुल खत्म कर दिया। इस बारे में मैं मुख्य मंत्री जी को कहना चाहूँगा कि वे इस बारे में जरा ध्यान दे दें और युद्ध वीर कोष में शहीद होने वाले जवानों के लिए पैसा रख लें।

श्री उपाध्यक्ष : कैप्टन साहब, आप समापन करें।

कैप्टन अजय सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं एग्रीकल्चर के बारे में कुछ बातें कहना चाहूँगा। हमारे एरिया में सरसों और बाजरे की मुख्य फसल होती है। मैं बाजरे और सरसों की फसल की मिनिमम सपोर्ट प्राईस के बारे में कहना चाहता हूँ कि किसानों को उनकी उपज का जो उचित मूल्य मिलना चाहिए था वह नहीं मिल पाया। मण्डियों में किसानों की फसल खराब हो गई। मेरे कहने का भाव है कि यदि किसानों को सरसों और बाजरे की मिनिमम सपोर्ट प्राईस न मिले तो फिर किसान कहां जाएंगे। उनको उचित प्राईस न मिलने के कारण बड़ा नुकसान हुआ है। आज फर्टीलाईजर और सीड पर सबसिडी जिस प्रकार से करटेल की जा रही है वह भी ठीक नहीं है। आपको पता है कि कितना डी.ए.पी. और यूरिया का रेट बढ़ा है। जो आऊट पुट है उसके हिसाब से जितनी किसानों को मिलनी चाहिए, वह नहीं मिल पा रही। ऐसा न होने पर किसानों का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। जो एग्रीकल्चर प्रौडक्ट इम्पोर्ट कर रहे हैं, इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है।

श्री उपाध्यक्ष : कैप्टन साहब, क्या इम्पोर्ट करने का अधिकार स्टेट गवर्नमैंट का है। प्लीज कन्फ्लयूड। (विघ्न) आप यहां पर वही बातें करें जो स्टेट से संबंधित हों। कैप्टन साहब, आपको बोलते हुए 15 मिनट हो गए हैं, आप जल्दी अपनी बात खत्म करें।

कैप्टन अजय सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एग्रीकल्चरल मार्किटिंग बोर्ड के बारे में एक बात कहना चाहता हूँ। बोर्ड द्वारा जो सड़कें बनाई जा रही हैं, मेरे हल्के में एक भी सड़क नहीं बन रही। हम पहले चौधरी बंसी लाल जी का प्रकोप सहते रहे। अब वे मुख्य मंत्री जी जो आये हैं, ये यहां पर बैठ कर कहा करते थे कि मैं आपके साथ सहानुभूति रखता हूँ। लेकिन मैं आपके माध्यम से इनको कहना चाहता हूँ कि मेरे हल्के में एक किलोमीटर भी सड़क नहीं बनी। मेरे हल्के में एक सांपली से पिथनवास गांव है वह सड़क भी आज तक नहीं बनी है। (विघ्न)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : आपके समय में कितने किलोमीटर सड़कें बनी थीं। (विघ्न)

कैप्टन अजय सिंह यादव : हमारे समय में 50 लाख रुपये एम.एल.ए. को लोगों की भलाई करने और उनके विकास के कार्य करने के लिए मिला करते थे। (विघ्न)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : जब आप इधर बैठा करते थे तो कितनी सड़क बना करती थी। (विघ्न)

कैप्टन अजय सिंह यादव : हमने तो खूब सड़कें बनायी हैं। (विघ्न) रिकार्ड तो सरकार के पास है, मेरे पास है नहीं। (विघ्न)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : मैं तो आपकी कांस्टीच्युंसी के बारे में पूछना चाहता हूँ कि उस वक्त आपकी कितनी सड़कें बनी थीं।

कैप्टन अजय सिंह यादव : रिकार्ड तो जिसकी सरकार होती है, उसके पास होता है। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष : कैप्टन साहब, आप अपनी बात जल्दी खत्म करें।

कैप्टन अजय सिंह यादव : डिप्टी स्पीकर साहब, हमारा जो पोस्ट ग्रेजुएट रिजनल सैन्टर था, वह बनना शुरू हुआ था और उस पर चौधरी बंसी लाल जी जब मुख्य मंत्री थे तो उस वक्त उस पर 1 करोड़ रुपये भी खर्च हुए थे। उस वक्त उसकी चार दीवारी बन गई थी। इस वक्त दक्षिणी हरियाणा के अन्दर एक भी रिजनल सैन्टर नहीं है। (विघ्न) आपने एक रिजनल सैन्टर गुड़गांव में खुलवा दिया है। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष : हमारे यहां पर यूनिवर्सिटी नहीं खुली है। हम यूनिवर्सिटी के लिए प्रयास कर रहे हैं। (विघ्न)

कैप्टन अजय सिंह यादव : डिप्टी स्पीकर साहब, आप मेरी बात सुनिये, 100 एकड़ भूमि लोगों ने फ्री

ऑफ कॉस्ट दी है और उस पर एक करोड़ रुपया लग चुका है, उसकी चारदीवारी बन गई है और सड़कें भी बन गई हैं। मुख्य मंत्री जी जब विपक्ष में हुआ करते थे तो कहा करते थे कि वहां पर मैं काम चालू कर दूंगा आज दो तीन साल हो गये हैं लेकिन लोग वहां पर अभी तक इसके चालू होने की बाट जोह रहे हैं। कम से कम वहां पर एक रीजनल सैंटर जरूर खोलें। उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से बावल में एग्रीकल्चरल कॉलेज था उसको भी वहां से उठा कर ले गए। तो मेरे कहने का मकसद यह है कि बजाय कोई संस्थान खोलने के वहां से कॉलेज कहीं और ले गए। चौधरी भजन लाल जी ने मोरपुर के अन्दर रीजनल सैंटर की आधारशिला रखी थी। हमारे क्षेत्र के नौजवान रोहतक और कुरुक्षेत्र में पढ़ने के लिए आते हैं अगर उनको आज यह सुविधा मिल जाए तो उसके लिए मैं मुख्य मंत्री जी का आभारी हूंगा तथा मुख्य मंत्री जी से यह आश्वासन चाहूंगा कि उसे चालू करवाएं। इस रीजनल सैंटर पर हमारी सरकार के समय एक करोड़ रुपया खर्च किया गया था उसको अभी तक अधूरा क्यों छोड़ा हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, जो झज्जर से रिवाड़ी की रोड है उस पर बाई पास बनाने की बात है। इतना भारी ट्रैफिक रोहतक से आता है आई.ओ.सी. की गाड़ियां वहां से निकलती हैं जिसकी वजह से बड़ी भारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। वहां पर कण्टेनर पोर्ट बनने वाला है और फ्लाई ओवर बनने वाला है। उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर बाईपास बनाने की बहुत जरूरत है क्योंकि वहां पर हर रोज एक्सीडैंट्स होते हैं। मुख्य मंत्री महोदय से मेरा यह कहना है कि वहां पर बाईपास तथा फ्लाई ओवर की बहुत जरूरत है।

श्री उपाध्यक्ष : कैप्टन साहब, इस बारे में चौधरी बंसी लाल जी ने कह दिया है, आप इसको किस लिए दोहरा रहे हैं। अब आप अपना स्थान लें। आप इस बात को देखें कि और सदस्यों ने भी बोलना है यदि आप बोलते रहे तो आपके दूसरे मैम्बरों को बोलने का टाइम नहीं मिलेगा।

कैप्टन अजय सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद करते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री धर्मवीर सिंह (तोशाम) : उपाध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। 13 तारीख को वित्त मन्त्री जी ने इस साल का जो बजट रखा है मैं उसका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय, बजट के पेज नम्बर 6 पर जो दर्शाया गया है यह पैसा कहां से आता है कहां जाता है कुछ क्लीयर नहीं है यह कैंसर की तरह स्टेट के बजट को खा रहा है। इस बजट की जो प्लान है उससे ज्यादा पैसा तो आपने पहले ही खर्च कर लिया है। 4-5 साल अगर यही हाल रहा तो प्रदेश में एक भी पैसा विकास के नाम पर नहीं बचेगा इसलिए इस को रोकने के लिए मैं तो केवल कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। इसके लिए सबसे पहले करप्शन को रोकिए। जब तक करप्शन, टैक्सिज की चोरी और दूसरी करप्शन्ज बंद नहीं होती तब तक आपका काम नहीं चलेगा। उपाध्यक्ष महोदय, क्योंकि हरियाणा प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश है, यह किसानों का प्रदेश है और किसानों को बिजली, पानी और फसल का भाव चाहिए। लेकिन वित्त मन्त्री महोदय ने तीनों महकमों में जिस प्रकार असीमित बजट देना है वह प्रदेश के किसान के लिए अच्छी बात नहीं है। अगर हम नहरों की बात लें उपाध्यक्ष महोदय, 4 तारीख को गवर्नर महोदय ने जो हाउस को एड्रैस किया तो पहली लाइन यह कही कि कई साल से भाखड़ा में पानी कम है, यमुना में पानी कम है लेकिन बड़े दु:ख की बात है कि इस बारे सरकारी आंकड़े बताते हैं कि गोबिन्द सागर खतरे के निशान पर है और यमुना में 90 हजार क्यूसिक पानी आया आज से 15 दिन पहले और दूसरी तरफ यह दिखाया जाता है कि पानी की कमी है। उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार से एक बात कहना चाहता हूँ कि मुख्य मंत्री जी बार-बार कहते हैं कि टेल से एस.वाई.एल. का काम चालू नहीं करवाना चाहिए था लेकिन हम इस बात के हक में नहीं हैं। जब तक पीछे का पोर्शन पूरा नहीं होगा तो बाद में हमें उससे बहुत भारी खतरा है। उपाध्यक्ष महोदय, आज हरियाणा को बने हुए 35 साल हो गए हैं।

श्री उपाध्यक्ष : धर्मवीर जी, आप भी कैप्टन साहब की तरह सिर्फ बजट पर बोलें। मैं आपको यह बात बता

[श्री उपाध्यक्ष]

रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी का केवल 13 मिनट का समय बचा है। आप इस चीज का विशेष ध्यान रखें। अगर 13 मिनट आप अकेले लेंगे तो दूसरे लोगों को टाइम नहीं मिलेगा इसलिए जैसे कैप्टन साहब ने बजट पर बात की है आप भी बजट पर ही बोलें।

श्री धर्मवीर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, एस.वाई.एल. के पूरा होने पर भी हमारे ऊपर खतरा मंडरा रहा है। हमारे दक्षिणी हरियाणा के जब तक लिफ्ट कैनाल सिस्टम है उनके पम्पस को ठीक नहीं करवाया जाएगा तब तक वहां पर पानी नहीं आएगा और हो सकता है कि एस.वाई.एल. का पानी मिलने के बाद वह पानी दोबारा सिरसा, जींद, कैथल और नरवाना की तरफ न भेज दिया जाए, यह कहकर कि आपकी लिफ्टिंग कपैस्टी नहीं है। इसलिए मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि एक साल के अन्दर जितने भी हमारे लिफ्ट कैनाल सिस्टम हैं उनका सुधार किया जाए। (विघ्न)

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं बिजली के बारे में कहना चाहता हूँ कि आज बिजली की क्या हालत है वह किसी से छुपी नहीं हुई है। ज्यादा से ज्यादा 3000 मैगावाट बिजली ये प्रदेश को देते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, सबसे दुःख की बात है कि आज प्रदेश के अन्दर बी.जे.पी. के कम्बीनेशन की सरकार है, केन्द्र में भी बी.जे.पी. की सरकार है और हिमाचल में भी बी.जे.पी. की सरकार है। आज हिमाचल प्रदेश की सरकार 18 हजार मैगावाट के संयंत्र लगाने जा रही है लेकिन वहां पर हमें एक प्रतिशत का हिस्सा नहीं मिल रहा है। यह हमारे प्रदेश की सरकार की कमजोरी है। उपाध्यक्ष महोदय, यह हमारा हक बनता है और इसके लिए प्रदेश की सरकार को केन्द्र सरकार पर दबाव डालकर अपना हिस्सा लेना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, आज यह सरकार हरियाणा में प्रदूषण ठीक रखने जा रही है। अगर प्रदूषण फैलेगा तो वह हरियाणा स्टेट के लिए ठीक नहीं होगा। उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर बार-बार थर्मल प्लांट की बात कही जाती है तो मैं आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहूँगा कि जब तक आप हाईडल प्रोजैक्ट को बढ़ावा नहीं देंगे तब तक इस प्रदेश का और देश का भला नहीं होने वाला है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी के साथ मैं यहां पर टैक्स के बारे में कहना चाहूँगा। वित्त मंत्री जी का जवाब आया था कि इस साल 65 करोड़ रुपए रोड़ी, बजरी और रेत से टैक्स के मिलेंगे। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, यमुनानगर से सोनीपत तक जो यमुना नहर जाती है उसमें खानक और बागनवाला, डिगाना में जाकर देखें, गुड़गांव और फरीदाबाद में जाकर देखें वह तो उपाध्यक्ष महोदय, आपके नजदीक पड़ता है वहां पर हर रोज एक प्रकार से खुली लूट होती है। हजार-हजार रुपए के हिसाब से वहां पर कूपन काटे जाते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, 12 दिसम्बर से लेकर 18 जनवरी तक का मुख्य मंत्री जी वहां पर रिकार्ड दिखाएं कि वहां पर कोई एग्रीमैंट हुआ है। वहां पर एक भी एग्रीमैंट नहीं हुआ है। सारा पैसा फर्जी पर्चीं काटने वालों के हाथों में गया है। उपाध्यक्ष महोदय, पूरी स्टेट में हर रोज 10 हजार ट्रकों से वे पैसा लूटते हैं। अगर वही पैसा सरकारी खजाने में आया होता तो जो टैक्स है वह 5 गुणा बढ़ गया होता।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे ख्याल से धर्मवीर सिंह ने मेरी बात पहले सुनी की नहीं। या सुनी भी तो अनसुनी कर रहा है। इनको मैं यह बता दूं कि मैंने यह क्लीयरकट कहा था कि 12 दिसम्बर को ज्यों ही हमें शिकायत मिली हमने इस पर कार्यवाही करके उनसे 20 या 40 लाख रुपये वसूल किए हैं और यह टोटल 80 लाख वसूल किए जाएंगे। उस समय मैंने यह भी कहा था कि पहले 10 सालों में भी जो चोरी करते रहे हैं उनसे भी यह सरकार वसूली करेगी फिर आपको पीड़ा होगी।

श्री धर्मवीर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इनको आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि हमें पीड़ा कभी नहीं होती और न ही हम इस बात से डरते हैं। सच्चाई यह है कि 12 दिसम्बर से 18 जनवरी तक कोई भी एग्रीमैंट नहीं हुआ

है। इस प्रकार से हर रोज 1 हजार 15 सौ ट्रक बिना टैक्स दिए वहां से गए हैं। जहां तक एग्रीमैंट का सवाल है आप सरकार से पता करवा लें या सरकार खुद पता करवा ले कि निगाना के अन्दर अब तक एग्रीमैंट का कोई नामोनिशान नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, रिवासा ढाणी, माओ और दूलेहड़ी के ऊपर तीन नाके लगाए हुए थे। बाकेवाला में जिस प्रकार से हजारों पुलिस कर्मचारियों ने कार्यवाही की है, वहां पर भय दिखाने के लिए पशुओं को भी नहीं छोड़ा गया है ताकि वहां पर कोई आदमी आवाज न उठा सके। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कोई लम्बी चौड़ी बात नहीं कहना चाहता हूँ, इस बारे में सी.बी.आई. से इन्क्वायरी करवा ली जाए और जिन-जिन लोगों ने वह पैसा लूटा है उनका पता करवाएं, यही हमारी मांग है। उपाध्यक्ष महोदय, जिस आदमी के नाम पर यह पहाड़ है उसके बारे में जानते तो मुख्य मंत्री जी भी हैं। चौधरी बंसी लाल जी के बारे में मुख्य मंत्री जी कह रहे थे कि वे दारू बिकवाते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, हमें यहां पर कहते हुए शर्म आती है कि जिनके ऊपर शराब बेचने के अनेकों केस बने हुए थे वही आज इनके नेता बने बैठे हैं। इसके अलावा धानक में पब्लिक हैल्थ का एक सरकारी कर्मचारी ट्रक यूनियन के नाम से 300 रुपए प्रति ट्रक के वसूल करता है। हर रोज साढ़े चार लाख रुपए कमासा है लेकिन उस पैसे का कोई रिकार्ड नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, पब्लिक हैल्थ के उस आदमी को उसका अध्यक्ष बना रखा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूँगा कि इस प्रकार से सरकारी खजाने को बढ़ाया नहीं जा सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, हम तो आपके माध्यम से सरकार से यह प्रार्थना करते हैं कि सरकार के इस खजाने को बचाएं ताकि प्रदेश का विकास हो सके।

श्री उपाध्यक्ष : धर्मवीर जी, आप वाईंड अप करें। (शोर एवं व्यवधान) चौधरी भजन लाल जी खानक पर कितनी बार बोलेंगे। फिर बाद में मुझे मत कहना कि समय नहीं दिया गया। (शोर एवं व्यवधान) आप उनको वाईंड अप करने दो।

श्री धर्मवीर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पर ओलावृष्टि से बड़ा भारी नुकसान हुआ है। कम से कम 50 गांव खरकड़ी, उलेड़ी, रिवासा, वीर ढाणी, मिराल से लेकर के छपार, सलह आदि ऐसे गांव हैं जहां पर 100 प्रतिशत नुकसान हुआ है। इसी के साथ उपाध्यक्ष महोदय, खासकर दक्षिणी हरियाणा में सर्दी ज्यादा होने की वजह से, जीरो डिग्री टैम्परेचर होने की वजह से सरसों की फसल खराब हो गई है। इस वजह से फसल का बड़ा भारी नुकसान हुआ है। हम मुख्य मंत्री महोदय से आपके द्वारा प्रार्थना करते हैं कि जिनकी फसल तबाह हुई है उनको मुआवजा देने की जरूर कोशिश करें।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : उपाध्यक्ष महोदय, इनको याद नहीं रहती है। मैं इनको बता दूं कि पिछले सेशन में इसी सीट पर बैठकर ये कह रहे थे कि हमारा इलाका सूखा रह गया बोया नहीं गया और अब यह कह रहे हैं कि ओले पड़ गए। (विघ्न) उस वक्त इन्होंने कहा था कि सूखा पड़ गया और कहीं पर भी फसल बोयी नहीं गयी और अब ये कह रहे हैं कि ओलावृष्टि से नुकसान हो गया।

श्री धर्मवीर सिंह : सरकार द्वारा गिरदावरी की गयी है। ये पता करवा लें। वहां पर 80 परसैंट से ज्यादा नुकसान ओलावृष्टि से हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : धर्मवीर जी, आप शायद उस समय हाउस में नहीं थे ओलावृष्टि की सारी डिटेल धीरपाल जी ने सदन को दी थी।

श्री धर्मवीर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से मैं कानून एवं व्यवस्था के बारे में कहना चाहता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : कानून व्यवस्था के बारे में नहीं बल्कि आप बजट पर अपनी बात रखें।

चौधरी भजन लाल : उपाध्यक्ष महोदय, कानून एवं व्यवस्था का मामला भी बजट में ही आता है।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : उपाध्यक्ष महोदय, अब इनको बजट के बारे में बोलना चाहिए।

श्री धर्मबीर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कोई लम्बी चौड़ी बात नहीं कहना चाहता। चौधरी बंसी लाल जी ने जब सरकार से सिक्योरिटी मांगी थी उस वक्त इन्होंने कहा था कि इस आदमी पर 70 रुपये की गोली कौन खराब करेगा। उपाध्यक्ष महोदय, शरीर तो सबका एक जैसा ही होता है। मुख्य मंत्री जी के परिवार पर सिक्योरिटी पर हर साल सात करोड़ रुपये से भी ज्यादा का खर्चा होता है। जब इनके परिवार का कोई सदस्य कहीं जाता है तो पुलिस की लाईन लग जाती है इसलिए अगर बंसीलाल जी ने सरकार से सिक्योरिटी मांग ली तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं थी, सरकार को उन्हें सिक्योरिटी देनी चाहिए थी। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : अच्छी बात है कि आज आप भी बंसीलाल जी के बारे में ध्यान रख रहे हैं। अब श्री अनिल विज बोलेंगे।

श्री अनिल विज (अम्बाला कैंट) : डिप्टी स्पीकर सर, आपका समय देने के लिए धन्यवाद। डिप्टी स्पीकर सर, जो हमारे वित्त मंत्री जी ने इस सदन में एक बहुत ही संतुलित बजट प्रस्तुत किया है मैं उस पर चर्चा करने के लिए खड़ा हुआ हूं। डिप्टी स्पीकर साहब, प्रजातंत्र मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्था का एक बहुत ही बेहतरीन तोहफा है। इस प्रजातंत्र में तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं, बहुत आवश्यक हैं। ये तीन चीजें हैं--नेता, नीति और नीयत। इन तीनों ही चीजों का होना बहुत आवश्यक है। अगर इन तीनों चीजों में से एक भी कम्पोनैंट मिसिंग हो गया तो काम खराब हो जाता है। मान लो नेता है नीतियां नहीं हैं तो उसका नतीजा नहीं निकल सकता, अगर नेता है, नीतियां भी हैं और अगर नीयत नहीं है तो भी प्रजातंत्र में लाभ नहीं मिल सकता और अगर नेता नहीं है नीतियां हैं एवं उनको लागू करने वाला कोई नहीं है तो भी नतीजा नहीं निकल सकता। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे फख्र है कि आज प्रदेश की बागडोर एक ऐसे व्यक्ति के हाथों में है जो हमें नेता भी उपलब्ध करवा रहा है, उसकी नीतियां भी हैं और जो वित्त मंत्री महोदय ने अपना बजट प्रस्तुत किया है उससे उनकी नीयत भी साफ झलक रही है। उनकी नीयत ठीक लग रही है। जो सम्पत सिंह जी ने बजट प्रस्तुत किया है उसमें उन्होंने 1922 करोड़ रुपये की योजना हमारे सामने प्रस्तुत की है। उपाध्यक्ष महोदय, आज हम जिस वित्तीय दौर से गुजर रहे हैं और जो प्रावधान आज की व्यवस्था में केन्द्रीय सरकार एवं प्लानिंग कमीशन के द्वारा किए जा रहे हैं वह भी देखने की बात है। आज इस बात पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है कि हम अपने रिसोर्सिज को अधिक से अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसेलिटीज को प्रोवाइड करने के लिए लगाएं। एक समय था कि जब हम अपने सारे संसाधन लोगों को सबसिडियां बांटने में लगा देते थे जिसकी वजह से जो तरक्की होनी चाहिए थी वह नहीं हो पायी। लेकिन आज युग बदला है, आज सोच बदली है, आज विचार बदले हैं इसलिए अधिक से अधिक तवज्जोह, अधिक से अधिक ध्यान आज इंफ्रास्ट्रकचर फैसेलिटीज देने की तरफ दिया जा रहा है। मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हमारे वित्त मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसमें उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पर 42 परसैंट खर्च करने की बात कही है। यह बहुत ही सराहनीय है। इन्फ्रास्ट्रक्चर अगर मजबूत होगा तो देश की इकोनोमी मजबूत होगी, अगर इन्फ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा तो ही प्रदेश की तरक्की होगी और प्रदेश का देश में एक नम्बर का राज्य बनने का सपना साकार हो सकेगा। 42 परसैंट यानी 1900 करोड़ में से 800 करोड़ रुपया खाली इन्फ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए होगा। पावर पर 165 करोड़ रुपया, रोड्स पर 285 करोड़ रुपया और इरीगेशन पर 300 करोड़ रुपया रखा गया है जो कि बहुत ही सराहनीय काम है।

श्री मांगे राम गुप्ता : पिछले साल कितना था। (विघ्न)

श्री अनिल विज : पिछले साल का भी बता देता हूं। पिछले साल रिवाइज्ड ऐस्टीमेट रोड्स के लिए 190 करोड़ का था इस बार 285 करोड़ का प्रावधान रखा है। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष : विज साहब, आप उनसे बात न करें। मांगे राम जी 63 मिनट बोल चुके हैं और ये सब सुनते हैं, सुनकर अनसुना करते हैं।

श्री अनिल विज : उपाध्यक्ष महोदय, सोशल सर्विसेज पर बजट का 37 परसैंट का प्रावधान रखा गया है और हम जो नीति बनाते हैं। दो चीजें होती हैं Work your plan and the second is Plan your work. These two things are very important और जो नीतियां हैं जैसा मैंने कहा, हमारे पास नीति भी है, नेता भी है और नीयत भी है। अभी जो यमुनानगर का इलैक्शन हुआ, उसने यह सिद्ध कर दिया कि हमारे पास तीनों चीजें हैं। यमुनानगर में जो पार्टी की जीत हुई उसमें लोगों ने, हरियाणा की जनता ने इन तीनों चीजों पर अपनी स्वीकृति की मोहर लगाई। (विघ्न) मांगे राम जी, आपकी पार्टी थर्ड आई है। आज कल रेलगाड़ी में भी थर्ड क्लास का डिब्बा नहीं लगाया जाता (शोर एवं व्यवधान) थर्ड की आजकल कोई जगह नहीं है (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : जो माननीय विधायक बोल चुके हैं वे कृपया बैठ जाएं। कैप्टन साहब, आप बैठ जाएं, दूसरों को बोलने दें। विज साहब, आप कंटीन्यू करें। (शोर एवं व्यवधान)

एक आवाज : बी.जे.पी. के बारे में बता दें।

श्री अनिल विज : बी.जे.पी. मेरी पुरानी पार्टी रही है इसलिए मैं उनके बारे में कुछ अधिक नहीं कहना चाहता हूं। मैंने इस पार्टी में 20-25 साल काम किया है। कल मेरी पुरानी पार्टी के नेता बहुत बौखलाहट में बातें कर रहे थे, बहुत कुछ कह रहे थे। वे यमुनानगर में आउट क्लास हो गए, कारण क्या है ? कारण ये है कि एक अच्छी पार्टी गलत मैनेजर के हाथ में है लेकिन जो हमारे मित्र की बौखलाहट है, उससे ऐसा लगता है कि वे बेचारे इस दुविधा में है कि मैं उधर का हूँ या इधर का हूँ बड़ी मुश्किल में हूँ कि मैं किधर का हूँ। (शोर एवं व्यवधान) इनकी दुविधा लोगों पर क्या असर कर रही है वह भी कहना जरूरी है। यह ठीक है कि इस हाउस की परम्परा बन गई है कि जब कोई चीज प्रस्तुत की जाएगी तो एक उसके पक्ष में बोलेगा और दूसरा उसके विपक्ष में बोलेगा। अगर मैं सच कहूँ तो आज हिन्दुस्तान में कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं है ये जितने अलग-अलग नाम हैं ये बिल्कुल गलत हैं। खाली दो पार्टियां है हिन्दुस्तान में, एक सत्ता पक्ष और एक विपक्ष। इनमें जब वे इधर बैठती हैं तो उधर की बात करती हैं और उधर बैठती हैं तो इधर की बात करती हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अनिल विज जी आपको 6 मिनट और दिए जाते हैं आप अपनी बात को कंक्लयूड करें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : उपाध्यक्ष महोदय, हम यहां बैठकर काम ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं इसका सर्टिफिकेट न इधर से दिया जाता और न उधर से, इसका सर्टिफिकेट तो जनता देती है जनता की अदालत देती है। जनता का जो नतीजा होता है उसको हमें मानना चाहिये और उसकी चर्चा यहां पर की जा सकती है। चाहे वह बजट की स्पीच हो चाहे गवर्नर एड्रेस की स्पीच हो। (शोर एवं व्यवधान) पिछली परफोर्मेंस ठीक थी। आगे के लिए हालांकि आजकल आर्थिक मंदी का दौर है उसका अगर हम अवलोकन करें तो यह बहुत ही चिन्ताजनक है।

श्री उपाध्यक्ष : विज साहब कंक्लयूड कीजिये।

श्री अनिल विज : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे साथ आप अन्याय मत कीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : आप मेरे से अन्याय की उम्मीद रखते हैं आप जल्दी कंक्लयूड कीजिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रार्थना करूंगा कि जिस तरह कल कांग्रेस पार्टी ने बी.जे.पी. पार्टी को टाइम दिया था हम और आप तो एक ही हैं आप अपनी डिस्क्रीशन से अपना समय मुझे दें।

श्री उपाध्यक्ष : बिज साहब कंक्लयूड कीजिये। आपको मैंने अपना 6 मिनट का समय दे दिया है।

श्री अनिल विज : उपाध्यक्ष महोदय, किन परिस्थितियों में माननीय सम्पत सिंह जी ने बजट प्रस्तुत किया है अगर हम प्रदेश की सी.ए.जी. की स्टेटमैंट देखें तो पता लगेगा कि What are the assets and liabilities of our State, अगर उसको देखें तो कैसी भयावह स्थिति काफी लगातार बनती जा रही है। सी.ए.जी. ने जो 31-3-2001 को अपनी रिपोर्ट दी है उसके हिसाब से हमारी लायब्लिटीज 14263 करोड़ रुपये थी और हमारी असैट्स 10495 करोड़ रुपये की थी यानी 3768 करोड़ रुपये की जो हमारी असैट्स थी वे लायब्लिटीज से कम थी। यह हमारी पिछले साल की वित्तीय स्थिति थी। इसी प्रकार से 2002-2003 में मैं समझता हूँ कि ऐसी परिस्थिति में इससे बेहतर बजट प्रस्तुत करने की कल्पना की नहीं जा सकती। इन्होंने किस प्रकार से अपने संसाधनों का बंटवारा किया है। मैंने बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 42 प्रतिशत का प्रावधान रखा गया है। इसी प्रकार से सोशल सर्विसिज के लिए 37 प्रतिशत का और इसी प्रकार से ओल्ड ऐज पैंशन और विडो पैंशन जोकि आज के समाज की आवश्यकता है उसके लिए 305 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार से वूमैन एण्ड चाइल्ड डिवैल्पमैंट के लिए 12.12 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। टैक्नीकल और वोकेशनल एजूकेशन के लिए 146 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है, हैल्थ सर्विसिज के लिए 47 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है, पब्लिक हैल्थ के लिए 77 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है, हाउसिंग के लिए 54 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है, एस.सी.एस.टी. के लिए 21 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। इसी प्रकार से 37 प्रतिशत का जो पैसा है वह सोशल सैक्टर के लिए रखा गया है। सोशल सैक्टर के लिए जो पैसा रखा गया है उसके एक हैड के बारे में मैं माननीय सम्पत सिंह जी से जरूर कहना चाहूँगा कि स्पोर्ट्स के लिए जो पैसा रखा गया है उसको अधिक बढ़ाया जाये क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ और मेरी ऐसी सोच है कि पिछले बजट में जो रिवाइज्ड एस्टिमेट्स थे उस में 11.91 लाख रुपये रखा गया था जो इस साल 3.40 लाख रुपये रखा गया है जो कि कम है। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे माफ करें क्योंकि मैं अभी थोड़ा समय और लूंगा क्योंकि मैं गवर्नर एड्रैस पर भी नहीं बोला।

श्री उपाध्यक्ष : आप स्पोर्ट्स पर बोलना चाहते हैं इसलिए मैं आपको एक मिनट का समय स्पोर्ट्स पर बोलने के लिए देता हूँ।

श्री अनिल विज : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने स्पोर्टस की, आई.टी. की और एजुकेशन की एक नीति बनाई है, इंडस्ट्रियल नीति बनाई है, राइट ऑफ वे की नीति बनाई है, इन सब नीतियों में से मैं सबसे अधिक स्पोर्ट्स नीति को महत्व देता हूँ और वह इसलिए क्योंकि मैं स्पोर्ट्स को रिफोर्मिस्ट मानता हूँ। यदि आप समाज को रिफोर्म करना चाहते हैं और समाज में परिवर्तन लाना चाहते हैं, नौजवानों की शक्ति सकारात्मक कार्यों की ओर लगाना चाहते हैं तो आपको नौजवानों के हाथों में कोई न कोई खेल की चीज पकड़ानी पड़ेगी। आज अगर सारे संसार में सर्वेक्षण करें और पदक तालिका पर नजर डालें तो आप देखेंगे कि जिन-जिन देशों में ओलम्पिक के पदक ज्यादा आए है उनमें कहीं उग्रवाद नहीं है, कहीं गुंडागर्दी नहीं है। युवकों में अत्याधिक शक्ति होती है और उस शक्ति को कहीं न कहीं तो लगना होता है। अगर उसके हाथ में बैट या हाकी नहीं पकड़ाएंगे तो वह डिस्को क्लब में जा सकता है या उसके हाथ गन भी उठा सकते हैं। हमारे प्रदेश में काफी लम्बे समय तक खेलों के प्रति खामोशी रहने के बाद इस सरकार के आते ही नई खेल नीति बनाई गई है। खेलों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, आज आलोचना तो सभी करते हैं, कहीं दुकान पर कहीं दफ्तर में और कहीं बाजार में कि 100 करोड़ की आबादी वाला देश है और पदक तालिका में नाम नहीं है। खेलों के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम कितना बजट खेलों के लिए मुहैया करा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : अनिल विज जी आप जल्दी वाइंड अप करें।

श्री अनिल विज : उपाध्यक्ष महोदय, अगर हम खेलों को प्रोत्साहन दें तो उसके नतीजे अच्छे निकल

सकते हैं और ऐसा हुआ भी है। इसका मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा कि इस सरकार के आते ही मुख्य मंत्री महोदय ने घोषणा की है कि ओलम्पिक में जो स्वर्ण पदक लाएगा उसे 1 करोड़ रुपये और रजत पदक लाने वाले को 50 लाख रुपये और ब्रोंज पदक लाने वाले को 25 लाख रुपये इनाम दिया जाएगा और इस घोषणा का असर भी हुआ है कि पीछे जो ओलम्पिक हुए उसमें पदक तालिका में कर्णम मल्लेश्वरी पदक हासिल करने में कामयाब हुई। उपाध्यक्ष महोदय, आज इस सदन में आपके सामने मैं यह दावा करता हूँ कि अगर हरियाणा प्रदेश का अनुसरण करते हुये बाकी सारे प्रदेश भी इस प्रकार की नीतियों पर अमल करें और इसी प्रकार खेलों को बढ़ावा दें तो अगले जो भी ओलम्पिक होंगे उसमें पदक तालिका में हिन्दुस्तान के खिलाड़ियों के नामों की संख्या सबसे अधिक होगी।

श्री उपाध्यक्ष : अनिल विज जी, आप दो मिनट में कंकलयूड करें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी बात दो मिनट में खत्म नहीं होगी, अभी मैंने अपने हल्के की एक भी बात नहीं की। उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से और भी अच्छी नीतियां बनाई जा रही हैं। 'सरकार आपके द्वार' पर काफी चर्चा हो चुकी है लेकिन मैं एक और अच्छी बात का जिक्र करना चाहूँगा। मेरे साथी अशोक अरोड़ा जी यहां बैठे हैं उनके दिमाग में यह बात कहां से आई, वे बाहर गये थे वहां से पता करके आये या मुख्य मंत्री जी ने उन्हें बताया कि हाईवे पैट्रोलिंग बनाया जाये। उपाध्यक्ष महोदय, हाई-वे पेट्रोलिंग की व्यवस्था हर 30 कि.मी. पर करके बहुत ही बेहतरीन काम किया गया है। वहां पर एम्बूलेंस का प्रावधान किया गया है, वहां हर चीज का प्रावधान किया गया है, पुलिस का भी इंतजाम किया गया है। इसके अतिरिक्त मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि हर शहर में एक ऐसा पार्क बनाया जाये जहां स्कूली बच्चों को यातायात नियमों की जानकारी दी जा सके। यदि ऐसे पार्क बनाये जायेंगे तो यह इस दिशा में एक और बड़ा कदम होगा। उपाध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त जिन नैशनल हाईवेज पर मुख्य क्रोसिंग हैं वहां पर ट्रैफिक लाईट्स का प्रावधान होना चाहिए। कुछ स्थानों पर तो है लेकिन दूसरी जगह जहां भी मुख्य क्रोसिंग है वहां भी ट्रैफिक लाईट्स होनी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, यदि मैं नगर पालिकाओं के बारे में चर्चा नहीं करूंगा तो I think I will be failing in my duty. You will kindly give me few minutes more.

श्री उपाध्यक्ष : अनिल विज जी, नगर पालिकाओं के बारे में पहले भी काफी चर्चा हो चुकी है। इनके बारे में आपका कालिंग अटेंशन मोशन भी आ चुका है। प्लीज आप वाईंड अप करें। (विघ्न)

श्री अनिल विज : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने आम जनता की भावनाओं को कद्र करते हुए हाउस टैक्स रिड्यूस किया है। उसकी जितनी सराहना की जाये वह कम है। (विघ्न) पहले आम जनता पर बहुत टैक्स था। वे लोग रोते रहे लेकिन उस तरफ किसी भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। मैं इस सरकार को मुबारकबाद देता हूँ और यह कहना चाहता हूँ कि मुख्य मंत्री महोदय ने उस कहावत को सिद्ध किया है कि लोक राज लोक लाज से चलता है और मुख्य मंत्री जी ने इसी कदम को आगे बढ़ाया है। **(इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए।)** 30 करोड़ रुपये सालाना कम किया है (शोर एवं व्यवधान) जो कि बहुत अच्छी बात है। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से डेरियों की शिफ्ट करने की योजना बनाई जा रही है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : साईलैंस प्लीज। गुप्ता जी प्लीज शांति बनाये रखें। प्लीज बैठे-बैठे न बोलें।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, विज साहब को हाउस टैक्स के बारे में क्या मालूम।

प्रो. सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं कैप्टन साहब को बताना चाहूँगा कि अम्बाला कैंट हरियाणा की सबसे इंटैलीजैंट कांस्टीच्यूंसी है और विज साहब उसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, विज साहब दो बार वहां से कांग्रेस और बी.जे.पी. के कैंडीडेटस को हराकर आये हैं। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : विज साहब आप वाईंड अप करें।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय ने मुझ पर बड़ी कृपा रखी। आप भी थोड़ी सी कृपा

[श्री अनिल विज]

करके मुझे थोड़ा समय बोलने के लिए और दें। इसके अतिरिक्त मैं यह कह रहा था कि वित्त मंत्री जी ने बजट में 25 करोड़ रुपये का प्रावधान नगरपालिकाओं को ग्रांट देने के लिए रखा है जो अच्छी बात है। लेकिन साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि नगरपालिकाओं की तरफ जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, जो रिकवरीज हैं वे बहुत ज्यादा हैं। लगभग 258 करोड़ रुपये की रिकवरी हैं कृपया इस ओर लोकल बॉडीज मिनिस्टर ध्यान दें। सरकार अपने संसाधनों से नगरपालिकाओं को 25 करोड़ रुपये दे रही है लेकिन इसके साथ-साथ हमें नगरपालिका पर भी अपना शिकंजा कसना चाहिए। यह जो मैंने बताया है 258 करोड़ रुपया इसमें से 22 करोड़ रुपया तो पिछले पांच साल से भी ज्यादा पुराना है। इसकी रिकवरी करने की तरफ नगरपालिका ध्यान दें तो ही हमारा सुधार हो सकता है। एक और महत्वपूर्ण मुद्दा मैं आपके द्वारा सदन के ध्यान में लाना चाहता हूँ कि जो अन-अथोराइज्ड कालोनीज बन गई हैं उनकी तरफ भी सरकार ध्यान दे। इसके लिए मैंने एक क्वैश्चन भी दिया था। इस सम्बन्ध में मैं अपने शहर का ही जिक्र करता हूँ। हमारी म्यूनिसिपल कमेटी के एरिया में ही 40-45 ऐसी कालोनीज हैं जिनमें लोग अपने नक्शे पास करवा कर मकान बनवाते हैं। उन लोगो ने 60 रुपया डिवैल्पमैंट टैक्स नक्शा पास करवाने पर दिया है। जब वे लोग बिजली का कनैक्शन लेते हैं तो 25 रुपये उनसे और लिए जाते हैं, जो ठीक नहीं है। जो कालोनीज नगरपालिकाओं के अन्दर आ गई हैं और जिन्होंने डिवैल्पमैंटल चार्जिज दे दिये हैं, जिनको हमने डिवैल्प कर दिया है, हमने मकान बना दिये हैं उनसे इस तरह के पैसे अलग से न लिये जायें। यह तो ठीक है कि आगे से एक भी कालोनी मत बनने दें। यदि कोई बनाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करें लेकिन जो बन चुकी हैं उनके बारे में कोई न कोई नीति जरूर बनायी जानी चाहिए। लोगों के खून पसीने की कमाई है, जरा उसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, जो एम.पीज. को लोकल एरिया डिवैल्पमैंट फण्ड दिया जाता है, उस बारे में भी कुछ कहना चाहता हूँ। यह ठीक है कि उनको पैसा दिया जाता है लेकिन एम.पीज. को शहरों की जरूरत का पता नहीं होता। (विघ्न)

चौ. भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, इनको बोलते हुए काफी देर हो गई है।

श्री अध्यक्ष : चौधरी भजन लाल जी, आप इनको बोलने दें। (विघ्न)

श्री अनिल विज : चौधरी साहब, आप मेरी बात ध्यान से सुनें। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : चौधरी भजन लाल जी, आप मेरी बात ध्यान से सुनिये। मैं सोमवार से पान का प्रबन्ध करवाऊंगा। जो ज्यादा बोलता है उनको पान खिला देंगे फिर वे बोलेंगे नहीं। (हंसी) चौधरी भजन लाल जी को पान दिलवा दूंगा, फिर ये बैठे-बैठे नहीं बोलेंगे। (विघ्न)

श्री मांगे राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, इनको बोलते हुए काफी देर हो गई है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : गुप्ता जी, जब आप बोल रहे थे, तब कोई नहीं बोल रहा था। (विघ्न)

श्री मांगे राम गुप्ता : आधा समय मैं बोला हूँ और आधा समय मेरे बीच में सत्तापक्ष के सदस्य बोले हैं। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : विज साहब, आप अपनी बात पूरी करें।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, अब मैं एक बहुत ही गम्भीर बात कहना चाहता हूँ। मैं सदन से हट कर बात करना चाहता हूँ, मैं पार्टी पोलिटिक्स से हट कर बात करना चाहता हूँ। मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारे सदन के सभी सदस्य चाहे वे किसी भी पार्टी से हों.... (विघ्न) मैं भजन लाल जी से, चौधरी बंसी लाल जी से और हाउस के नेता से यानि सबसे कहना चाहता हूँ कि जो बात मैं कहने जा रहा हूँ उस पर चर्चा हाउस में करने में कोई दिक्कत हो तो, हाउस की परम्परा टूटती हो तो हम सब हाउस से बाहर बैठ जाएं लेकिन मेरे द्वारा कही जाने वाली बात पर चर्चा अवश्य करें। इस चर्चा के लिए चाहे विपक्ष के नेता सभी सदस्यों को बुला लें, चाहे मुख्य मंत्री जी सभी सदस्यों

को बुला लें अगर कोई नहीं बुलाता तो मैं बुला लूंगा। लेकिन कुछ बातें हैं जिन पर विचार जरूर करें। आज मैं इस राज की बात नहीं कर रहा। (विघ्न) मैं तीसरी बार सदन में आया हूं। मैंने तीनों अलग-अलग राज देखें हैं। इस सारी प्रशासनिक व्यवस्था में एम.एल.एज. की क्या दयनीय स्थिति है, मैं उस पर बात कहना चाहता हूँ। एम.एल.एज. का जो दिन प्रति दिन इमेज गिर रहा है, मैं उसकी बात करना चाहता हूँ। मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस बात पर बैठ कर हम सभी सोचें और विचार करें। कहने को हमें चीफ सैक्रेटरी का दर्जा दिया जाता है। लेकिन असल में एक क्लर्क भी एम.एल.ए. की चिट्ठी का उत्तर नहीं देता। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : अनिल जी अब आप वाईंड अप करें।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मैं इस राज की या उस राज की बात नहीं कर रहा। मैंने पहले भी कहा है कि अगर सदन में चर्चा करने में कोई दिक्कत हो तो अम्बाला छावनी में बात कर लेंगे। वहां पर सभी सदस्य आ जाएं। सारे विधायक व पूर्व विधायक आ जाएं, और जो मैं कह रहा हूँ उस पर चर्चा करें। मैं एल.एल.ए. को अधिक शक्ति देने की बात कर रहा हूँ, उस पर चर्चा करें। जनता हमें सत्ता सौंपती है। लेकिन अगर हमारे हाथ में ताकत नहीं है जिस कारण हम किसी के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते ऐसी बात पूरे हिन्दुस्तान में कहीं पर भी नहीं है लेकिन हम शुरू करेंगे। अगर मेरे सामने कोई सरेआम रिश्वत भी लेता है तो मैं उसको पकड़ नहीं सकता और अगर पकडूंगा तो सरकारी काम काज में दखल देने का दोषी पाया जाऊंगा, मुझे दोषी करार दिया जाएगा। हमारे पास न कोई प्रशासनिक अधिकार है और न ही हमारे पास कोई फाईनैंशियल पावर है। आज डी.सी. के पास कोई दुखी व्यक्ति चला जाए, कोई बीमार आदमी चला जाए या डी.सी. कहीं स्कूल वगैरा का उद्घाटन करने चला जाता है तो वह 5, 10 या 20 हजार रुपये की ग्रान्ट दे सकता है लेकिन विधायक नहीं दे सकेगा। जैसे मन्त्रियों को सरकार ने 15-15 लाख रुपये की ग्रांट दे रखी हैं। इसी तरह एक-एक लाख रुपये की ग्रांट विधायकों को भी दे दें। स्पीकर सर, हमारी यह मजबूरी है और हमें हर जगह जाना पड़ता है और हर विधायक हर जगह जाना ऐफोर्ड नहीं कर सकता। मैं उन विधायकों की बात नहीं करता जो गलत तरीकों से पैसा कमाते हैं। अध्यक्ष महोदय, मुझे माफ करेंगे मेरे पास इसका कोई पर्यायवाची शब्द नहीं अगर यह संसदीय शब्द न हो तो आप उसे तबदील कर लें। वास्तव में यह राजनीति ***** का खेल बन कर रह गई है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : विज साहब ने जो अनपार्लियामैंटरी शब्द कहा यह रिकॉर्ड न किया जाए।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही निवेदन कर दिया है कि आप इसको चैंज कर लें मेरे पास इसके लिए कोई और शब्द नहीं है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : विज साहब, अब आप बैठिये (विघ्न) नो-नो यह रिकार्ड न करें।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मैं पुन: कह रहा हूँ कि मैं इस राज या उस राज की बात नहीं कर रहा हूँ। इसके या उसके राज की बात कह कर या एक दूसरे की तरफ इस बात को हल्का करने की कोशिश न करें। स्पीकर सर, मैं बिल्कुल सत्य बात कह रहा हूँ और ठीक बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ (विघ्न) हम सभी एम.एल.एज, को बैठकर विचार करना चाहिए। (विघ्न) मैं सभी साथियों से आग्रह करूंगा कि मेरी बात को पार्टी पॉलिटिक्स में बांध कर मत देखें। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, इनका राज अधिकतर समय रहा है इसलिए ये भी इसके लिए दोषी हो सकते हैं Don't tell it me. स्पीकर सर, मैं किसी एक के समय की बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने इसलिए कहा कि चौधरी भजन लाल जी, चौधरी बंसी लाल जी और सदन के नेता को मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। यह मेरे अपने दिल की बात है। (विघ्न) मैं एम.एल.ए. चुन कर आया हूँ। अपनी बात कहने का मेरा अधिकार है (विघ्न एवं शोर) इन चीजों के अधिकार हमें दिए जाने चाहिएं (विघ्न)

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : विज साहब, अब आप वाइंड अप करिए।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, लोग तन्खवाह बढ़ाने की बात करते हैं मैं इसका पक्षधर नहीं हूँ हम इसके हकदार नहीं है। हमें अधिकारों की जरूरत है। हम किसी को सस्पैंड नहीं कर सकते और जो बातें मैं कह रहा हूँ मेरे ख्याल से वे इस हाउस के लिए ही नहीं हैं हमारे पड़ोसी हाउस में भी ऐसा ही है, सब जगह ऐसा ही है लेकिन मैं चाहूँगा कि हम शुरू करें। आज नगरपालिका के अध्यक्ष को पावर है, आज एक पंच को, एक सरपंच को पावर है लेकिन अपने-अपने दिलों पर हाथ रख कर बताइये कि हमारे पास क्या पावर है, अपने-अपने दिलों पर हाथ रख कर बताइये कि जो गलत काम करते हैं उनको छोड़ कर कोई भी आदमी अपनी कारगुजारी पर सन्तुष्ट है ? आप भी बताइये। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मेरा निमन्त्रण है सदन के सारे सदस्यों को अगर वे इस पर सहमत हों किसी पार्टी पोलिटिक्स में इस बात को न ले जा कर पोलिटिक्स से हट कर हम हाउस से बाहर बैठ कर इस सारे विषय पर चर्चा करें। जैसे हम पंचायतों को पावर्ज़ दे रहे हैं, जिला परिषदों को पावर्ज़ दे रहे हैं वैसे ही हम एम.एल.एज. को भी पावर्ज़ दी जानी चाहिए। क्योंकि जनता के प्रति हमारी जवाबदेही है, क्योंकि जनता हमें राज देती है और हमसे हिसाब मांगती है। इसलिए हमें इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए। हम यहां पर 10-15 दिन बैठकर एक दूसरे के खिलाफ खाली विरोध करके अपना समय बर्बाद करते हैं अगर इसकी बजाय हम बाहर बैठकर चर्चा करें तो बहुत अच्छी बात होगी। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं अपने हल्के की भी कुछ बात कहना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष : विज साहब, अब आप वाइंड अप करें। आपका समय अब खत्म हो गया है इसलिए आप बैठें। (विघ्न) विज साहब, आप बहुत लम्बा समय बोल लिए हैं इसलिए अब आप वाइंड अप करें। आपने 12.27 पर बोलना शुरू किया था अब आप प्लीज अपनी बात को समाप्त करें। (विघ्न)

श्री अनिल विज : स्पीकर साहब, मैं समाप्त कर रहा हूँ। चौधरी देवी लाल जी के नाम पर पानीपत में 7वीं और 8वीं यूनिट लगाने जा रहे हैं जिसके लिए सरकार ने बजट में 165 में से 159 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। सड़कें बनाने का प्रावधान किया है, सरकार स्टेट हाई-वे को मजबूत करने जा रही है, उनको पक्का कर रही है, सरकार यह बहुत ही बेहतरीन काम करने जा रही है। इस बारे में मैंने बजट में पढ़ा है। इसके अलावा यह सरकार हरियाणा प्रदेश के उन सात गांवों को जो कि अभी तक सड़क से कनैक्टिड नहीं हैं, उनके लिए भी बजट में प्रावधान रखा है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, 6685 गांवों में से सात गांव ऐसे हैं जो सड़क से जुड़े हुए नहीं हैं उनके लिए भी बजट में 63 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है। इसके अलावा 145 करोड़ रुपये स्टेट हाई-वे के लिए, 2 करोड़ रुपये डिस्ट्रक्ट रोडज के लिए भी रखें हैं। यह जो 2 करोड़ का अमाउन्ट है, अमाउन्ट थोड़ा कम है अगर इसको बढ़ा दें तो बहुत अच्छा होगा।

13-00 बजे

श्री अध्यक्ष : अनिल जी, आपका समय समाप्त हो गया है (विघ्न) आप फिर किसी मांग पर बोल लेना। अब आप अपनी सीट पर बैठ जाएं।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने हल्के के बारे में दो-तीन बातें कहना चाहूँगा। अध्यक्ष महोदय, हमारे हल्के में अनाज मण्डी के लिए जमीन अधिग्रहण की गई है। इस सरकार ने ऐसा करके लोगों की बहुत पुरानी मांग पूरी की है और उसके लिए सैक्शन 4 और 6 ईशु हो चुकी है। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूँगा कि वहां पर सरकार द्वारा जल्दी से जल्दी अनाज मण्डी बनाई जाए। इसके अलावा हमारा शहर हर साल बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित होता था और मुख्यमंत्री जी ने वहां पर फ्लड की रोकथाम के लिए आदेश दे दिए हैं, उसके लिए पैसे का भी प्रावधान हो चुका है इसके लिए भी मैं अम्बाला की जनता की तरफ से मुख्य मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में बताना चाहूंगा कि हमारे शहर में बहुत ही बढ़िया पुल बनाया गया है जो कि अम्बाला सैन्ट्रल जेल से लेकर के अम्बाला कैंट तक बनाया गया है। उसमें पता नहीं कैसे एक चूक

रह गई है कि वहां पर लाईटें नहीं लगा पाए हैं। उसके बारे में भी मैं कई बार मुख्य मंत्री जी से कह चुका हूँ और इन्होंने इसके लिए आश्वासन भी दिया है। मेरी आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना है कि उस आश्वासन को शीघ्र अति शीघ्र पूरा किया जाए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अनिल विज जी, आपको बोलते हुए काफी समय हो गया है अब आप सीट पर बैठ जाएं। दूसरे मैम्बर्ज को भी बोलने का मौका दें।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, आप मुझे दो मिनट दे दें मैं अपनी बात कह कर बैठ जाऊंगा। आपको मुझे कहना नहीं पड़ेगा। मैं अपनी बात यहां पर विस्तार से कर लेता लेकिन समय नहीं है। अध्यक्ष महोदय, कैनाल बेस्ड वाटर सप्लाई स्कीम के लिए मुख्य मंत्री जी ने बहुत कृपा की है और उसके लिए पैसे का भी प्रावधान किया है और हमारे यहां एक योजना के तहत प्रोग्राम चल रहा है। मैं इस बारे में भी आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से आग्रह करना चाहूँगा कि वह काम समय सीमा में ही समाप्त हो जाए। अध्यक्ष महोदय, इसी के साथ साहा ग्रोथ सैन्टर है वहां पर मुख्य मंत्री जी ने एक फूड पार्क लगाने की घोषणा की है। अम्बाला की जनता ने इनका इस बात के लिए बहुत स्वागत किया है। अध्यक्ष महोदय, वहां पर 400 एकड़ जमीन एक्वायर की जा चुकी है। मैं इस बारे में कहना चाहूँगा कि इसको भी शीघ्र अति शीघ्र बसाया जाए। अध्यक्ष महोदय, हमारा जो सिविल अस्पताल है वह कम से कम 150-200 साल पुराना है, मैं चाहता हूँ कि इससे पहले वह गिरे और वहां पर कोई दुर्घटना घटे, उससे पहले उसको भी बनवाने के बारे में विचार किया जाए। अध्यक्ष महोदय, यूरोपियन कम्पनी का जो पैसा आया है उसको भी शीघ्र लगाया जाना चाहिए। इसके अलावा यात्री निवास के लिए मुख्य मंत्री जी से सरकार आपके द्वार प्रोग्राम के तहत हमें आश्वासन मिला था, उस पर सरकार को कार्य शीघ्र करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, एक तोपखाना बाजार शहर से 5 किलोमीटर दूर पड़ता है और वहां से वापिस आने के लिए कन्टोनमैंट एरिये से गुजर कर आना पड़ता है। वहां पर रात को पहरे लगा दिए जाते हैं जिससे लोगों को बहुत कठिनाई होती है। इस बारे में सरकार कुछ करे। अध्यक्ष महोदय, सरकार आपके द्वार प्रोग्राम के तहत एक डिस्पैंसरी के लिए कहा था और मुझे खुशी है कि मुख्य मंत्री जी ने वहां पर सारी बातें शुरू से लेकर आखिर तक स्वीकार कर ली थी और उनमें से कई कामों का पैसा भी आ चुका है, मेरी आपके माध्यम से प्रार्थना है कि उस पैसे का प्रयोग किया जाए।

श्री अध्यक्ष : अनिल जी, अब आप बैठ जाएं आप अपनी बाकी बातें लिख कर दे देना। (शोर एवं व्यवधान) आप यों ही नहीं बोलें, आप तो बड़े कल्चर्ड आदमी हैं।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री महोदय से कहना चाहूँगा कि अम्बाला का कन्जयूमर फोरम पिछले दो साल से खाली पड़ा हुआ है उसके लिए भी कुछ किया जाए। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैंने यहां कुछ बातें कही है उस बारे में मैं कहना चाहूँगा कि हमें सबको पार्टी पोलिटिक्स से ऊपर उठकर इस सदन की अपनी जो मर्यादाएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए हमें यहां पर अपनी बातें कहनी चाहिएं। इसके अतिरिक्त एक जो यहां पर एक दूसरे का विरोध करने की परम्परा है उसको भूल कर हम सबको कहीं बाहर बैठकर इस बारे में विचार करना चाहिए कि कैसे इस माहौल को सुधार सकते हैं।

श्री लक्ष्मण दास अरोड़ा (सिरसा) : अध्यक्ष महोदय, जहां तक बजट पर बोलने की बात है तो हाउस में एक प्रथा बन गई है कि रूलिंग पार्टी वाले इसके पक्ष में बोलते हैं और अपोजिशन वाले इसके विरोध में बोलते हैं। मैं सदन में यह कहना चाहता हूँ कि बजट में जो अच्छी बात हो उसके पक्ष में बोला जाए और जो गलत बात हो उसके विरोध में बोला जाए चाहे वह मैम्बर रूलिंग पार्टी का हो या अपोजिशन का हो।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक ही बात मुख्य मंत्री महोदय जी से कहना चाहता हूँ कि यह जो हाउस टैक्स लगाया

[श्री लक्षमण दास अरोड़ा]

गया है इससे शहर में बवेला सा मच गया है। अगर आज कोई झोंपड़ी, कच्चा मकान और वक्फ बोर्ड की जमीन पर कहीं पर भी छोटा-मोटा मकान बनाकर बैठा हुआ है, वह आज डर से कांप रहा है। मुख्य मंत्री जी इस बारे में मेहरबानी करके कुछ विचार करें। धन्यवाद।

श्री चन्द्र भाटिया (फरीदाबाद) : आदरणीय अध्यक्ष जी, आपने बजट पर बोलने के लिए मुझे जो समय दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मेरे से पहले भी बोलते हुए अनेक साथियों ने अपनी बातें कही हैं। मैं भी बजट पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। वित्त मंत्री, हरियाणा प्रो. सम्पत सिंह ने जो बजट पेश किया है उसमें मैं यह समझता हूँ कि सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है चाहे किसान वर्ग हो या चाहे व्यापारी वर्ग हो, सभी वर्गों की बात कही गयी है। अभी हमारे कांग्रेस के एक साथी ने भी एक बात कही कि जो अच्छी बाते हैं उनको कहना चाहिए और जो गलत बातें हैं उनके लिए हमें बताना भी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, इनकी यह बिल्कुल सही बात है लेकिन हमारे कुछ साथियों को यह बात शायद समझ में नहीं आती। मैं दूसरी बार विधान सभा में चुनकर आया हूँ। फरीदाबाद के लोगों ने दोबारा मुझे विधान सभा में भेजा है। पिछले समय में भी जब हम विधायक थे और जब हमारे बुजुर्ग आदरणीय चौधरी बंसीलाल जी मुख्य मंत्री थे, हमने वह समय भी देखा था। हमने उससे पहले का कांग्रेस की हकूमत का समय भी देखा है। दो बार विधान सभा में आने के बाद हमने देखा कि यहां पर जो सही बातें हैं उनका भी विरोध किया जाता है। जो अच्छे काम थे उनको भी अच्छा नहीं कहा गया क्योंकि हमारे जो विपक्ष के साथी हैं वे यह सोचते हैं कि अगर वे हमेशा विपक्ष वाली बात नहीं कहेंगे या सही बात को भी गलत बात नहीं कहेंगे तो वे विपक्ष की भूमिका को नहीं निभा पाएंगे, उनकी भूमिका विपक्ष की नहीं मानी जाएगी। अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री द्वारा जो बजट पेश किया गया मैंने पहले ही कहा कि उसमें सभी वर्गों की बात कही गयी है। मेरे से पहले भी इस बारे में सभी साथियों ने अपनी बातें कहीं। चौधरी बंसीलाल जी इस समय यहां पर बैठे नहीं है। उन्होंने अपनी बात कहते हुए कुछ सुझाव मुख्य मंत्री जी के सामने रखे लेकिन जब उनको उनकी बातों का जवाब मिला तो वे उस बात को घुमा फिराकर खत्म करने की कोशिश करते थे। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा सरकार एक बड़ा परिवार है इसके मुखिया माननीय मुख्य मंत्री जी है। मैं यह मानता हूँ कि कोई न कोई कमी इतने बड़े परिवार में रह भी सकती है। हमें उस बारे में सुझाव देने चाहिएं। अध्यक्ष महोदय, मुझे यह लगता है कि आज जो पीड़ा हमारे इन विपक्ष के साथियों को हो रही है वह ठीक नहीं है। एक समय वह भी था जब इनकी सरकार थी, इनका अपना राज था। उस समय इनके राज के दौरान क्या-क्या होता था वह हरियाणा की जनता अच्छी तरह से जानती है और आप भी जानते हैं। (विघ्न) मैं बजट पर ही बोलने जा रहा हूँ। मैं उसी बात को सामने ला रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं एक और प्रार्थना आपसे करना चाहूँगा कि आप मुझे बजट पर बोलने के लिए थोड़ा समय ज्यादा दें क्योंकि पिछले दिनों बुजुर्ग चौधरी बंसीलाल जी की मेहरबानी से हम जेल में भी रहकर आए हैं हमारा वह समय जो हमें पिछले दिनों नहीं मिला हमें दिया जाए। मैं कहना चाहता था कि वह भी एक समय होता था जब इनके पास हुकूमत होती थी और आज सुझाव देने में भी कोई दम नहीं दिखता है। जब राजपाट था, जब सरकार होती थी तब उन बातों की तरफ कोई ध्यान नहीं जाता था। आज बंसी लाल जी हाउस टैक्स की बात कह रहे हैं। यही चौधरी बंसीलाल थे जब बल्लबगढ़ से आनंद शर्मा विधायक होते थे तथा मैं फरीदाबाद से विधायक होता था। तब मैंने कहा था कि फरीदाबाद में जो हाउस टैक्स लगाया जा रहा है, उसे ठीक करें तब हमारी बात नहीं सुनी जाती थी। अब फरीदाबाद में कहीं तोड़फोड़ होती है तो ये कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम कोई तोड़फोड़ नहीं होने देंगे और जब ये मुख्य मंत्री थे तो फरीदाबाद और बल्लबगढ़ के अन्दर तथा साथ लगते विधानसभा क्षेत्र में बुल्डोजर चलाए जाते थे, झुग्गी झोंपड़ियों को तोड़ा जाता था। मैं यह कहना चाहता हूँ कि जब इनके पास पावर होती थी तो क्या किया जाता था। अब ये लोग कहते हैं कि ओम प्रकाश चौटाला जी घोषणा मंत्री हैं और सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत जो घोषणाएं करके आते हैं उन पर काम नहीं होता जबकि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत बहुत सारे काम हो रहे हैं और जो भी घोषणाएं मुख्य मंत्री जी करके आते हैं

यह पूरी होती हैं। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम कोई बुरा काम नहीं है यह एक अच्छा काम है। बंसी लाल जी तो अपने कमरे से बाहर नहीं निकलते थे और निकलते थे तो ऐ.सी. गाड़ी में बैठकर निकलते थे, लोगों के बीच में नहीं जाते थे। (विघ्न)

श्री रामकिशन फौजी : अध्यक्ष महोदय *********.

श्री अध्यक्ष : फौजी की कोई बात रिकार्ड न की जाए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री चन्द्र भाटिया : अध्यक्ष महोदय, कल जब बंसी लाल जी बोल रहे थे और मैं खड़ा होकर कुछ कहना चाहता था तो उन्होंने मुझे टोक दिया था इसलिए मैं बीच में नहीं बोला। आज अगर वे बैठे होते तो मैं उनको अपनी बात कहता। वे चुपचाप चले गए जबकि सैशन में पूरे समय बैठना चाहिए। उन्होंने अपनी बात कह दी और चले गए। उनको मुख्य मंत्री जी की बात भी सुननी चाहिए थी। (विघ्न) मैं यह कहना चाहता हूँ कि आज बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। जिस मुख्य मंत्री जी को घोषणा मंत्री कहा जाता था आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई मुख्य मंत्री गांव में जाता हो, कोई व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि हमने मुख्य मंत्री जी को रू-ब-रू नहीं देखा है या हमने कोई काम कहा हो और इन्होंने न किया हो। जितने भी सदस्य बैठे हैं मैं कहना चाहूँगा कि कोई भी सदस्य ऐसा नहीं होगा और कोई भी विधान सभा क्षेत्र ऐसा नहीं होगा जहां विकास के काम नहीं चल रहे हों। कहने को कह भी दें लेकिन प्रैक्टिकल जो लोगों के बीच में काम हो रहे हैं वे दिख भी रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी ने बजट पेश किया है उसमें बसों की बात को भी रखा गया है। हमारे परिवहन मंत्री जी ने बहुत बढ़िया सुविधाएं लोगों को प्रदान की हैं। इसी तरह खेलों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। अच्छे कामों की सराहना करनी चाहिए, यह हमारा फर्ज बनता है और जो काम वाजिब हों तथा न हो रहे हों वह बात भी मुख्य मंत्री जी के समक्ष रखनी चाहिएं। (विघ्न) मैं बंसी लाल जी को सारी बात सुनाना चाहता था कि उन्होंने हरियाणा प्रदेश की जनता के साथ क्या-क्या ज्यादतियां की थीं। अध्यक्ष महोदय, चौधरी बंसी लाल जी ऐसे मुख्य मंत्री थे जो लोगों के पास नहीं जाते थे, लोगों के पास जाने में इनको शर्म आती थी। यह लोगों से गाड़ी में बैठकर बातें किया करते थे। उस समय कोई विधायक, कोई मंत्री इनके घर नहीं जा सकता था। श्री करतार सिंह भड़ाना जी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। आज वे इस सदन में बात करते हैं कि खानों में हजारों रुपये की पर्चियां काटते हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने उनको उसका जवाब दे दिया था कि किस प्रकार 80 लाख रुपये मौजूदा सरकार ने वसूल किये हैं और 50 लाख तथा 30 लाख रुपये और वसूल कर लेंगे। इससे आगे मैं क्या बताऊं। अध्यक्ष महोदय, चौधरी बंसीलाल जी की दिल्ली में जो कोठी बनी हुई है उसको बनाने में 15 करोड़ रुपये लगे हुए हैं। उस प्लाट की उस वक्त कितनी कीमत थी इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, यह सब गरीबों की खून पसीने की कमाई में से बनाई चीज है। मैं तो वही बातें बता रहा हूँ जो चीज सामने हैं। अध्यक्ष महोदय, चौधरी बंसीलाल जी के राजपाट में हमारे को बोलने के लिए समय नहीं दिया जाता था। चौधरी बंसीलाल जी के राज में जब पुलिस में भर्ती हुई तो मैंने खड़े होकर कहा कि चौधरी साहब पुलिस की भर्ती में खुल्लेआम पैसे लिये जा रहे हैं। लेकिन उस समय हमारी बात को सुना नहीं जाता था और हमें बैठा दिया जाता था। आज इस सरकार के समय में जो पुलिस की भर्ती हुई है वह बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से हुई है। कोई व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि मेरे से पुलिस की भर्ती के लिए पैसे लिये हैं। हमारे जो फरीदाबाद के पुलिस अधीक्षक श्री रणबीर शर्मा जी हैं उन्होंने उसी नौजवान को पुलिस के लिए चुना है जो पुलिस में भर्ती के लायक था, उसी को पुलिस में भर्ती किया गया है जो इसके काबिल था। आज जो काम इस सरकार ने किये हैं उनके बारे में हरियाणा के लोग मुख्य मंत्री महोदय की प्रशंसा करते हैं। 22 फरवरी को इस सरकार को बने हुए दो साल हो गये हैं और अभी तीन साल बाकी रह रहे हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि चौधरी बंसीलाल जी की उम्र लम्बी हो और

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

[श्री चन्द्र भाटिया]
जो वे स्वप्न देख रहे हैं वह सपना अब पूरा होने वाला नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रामकिशन फौजी : अध्यक्ष महोदय, *******

श्री अध्यक्ष : रामकिशन फौजी की कोई बात रिकार्ड न की जाये।

श्री चन्द्र भाटिया : अध्यक्ष महोदय, सपने की बात की जा रही थी। हमारे मन में एक बात थी कि चौधरी बंसीलाल जी अगली बार चुनाव जरूर जीत कर आयें लेकिन विपक्ष में बैठे नजर आयें। पहले तो यह लग रहा था की इनकी छुट्टी होने जा रही है लेकिन फिर पता लगा कि यह हमारे साथ बैठे हैं बड़ा अच्छा लग रहा है। वह सपना हमारा पूरा हुआ है हम यही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी लम्बी उम्र हो वे हमारे बुजुर्ग हैं और वे अगले तीन साल में जो विकास के कार्य हों उनको देखें। एक बात जरूर है कि चौधरी बंसीलाल जी बुजुर्ग हैं वे सुझाव खूब दे सकते हैं। जब वे सत्ता में होते हैं तो उनको कोई सुझाव याद नहीं आता लेकिन जब विपक्ष में बैठते हैं तो उनको सुझाव देने याद आ जाते हैं। अब उनको याद आ गया कि बुलडोजर चलवा रहे हैं, खदानों में गड़बड़ हो रही है। ये कभी बिजली की बात करते हैं तो कभी एस.वाई.एल. की बात करते हैं। कभी कह रहे हैं कि नारनौल-महेन्द्रगढ़ वाली सड़क खराब है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि जब चौधरी बंसीलाल जी मुख्य मंत्री थे उस समय कभी इनको सड़कों की बात याद नहीं आई कि कोई सड़क भी बनानी है। यह बिल्कुल सही है कि आज मुख्य मंत्री महोदय ने जो विकास के काम किए हैं वे सराहनीय हैं इसमें कोई दो राय नहीं है। आज जगह-जगह सड़कें बन रही हैं। अध्यक्ष महोदय, अब मैं एस.वाई.एल. नहर के बारे में जिक्र करना चाहूँगा जिस बारे में चौधरी बंसीलाल जी कह रहे थे कि यह काम उन्होंने करवाया था। कोई अच्छा काम हो जिसमें सराहना मिलने वाली बात हो तो उसमें चौधरी बंसी लाल जी कहते हैं ये काम उन्होंने करवाया है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं वही बात कहूँगा जिसमें सच्चाई है। एस.वाई.एल. नहर के बारे में इन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। लेकिन आज जब मुख्य मंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने इस नहर के ऊपर एक कदम उठाया है तो इनको तकलीफ हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जब इस नहर को बनजाने के लिए एक साल का समय दिया है तो इनको खुशी नहीं हो रही है। आज जहां ये सरकार इतने विकास के कार्य करा रही है तो मुझे उम्मीद है कि यह सरकार एस.वाई.एल. नहर का काम करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। इनको इस बात का बड़ा दर्द हो रहा है कि यदि यह काम पूरा हो गया तो ये जनता को क्या कहेंगे ? अध्यक्ष महोदय, इनके समय में जहां पत्थर लगे थे वहां पत्थर लगे के लगे रह गए, उन पर कोई काम नहीं होता था। अब मैं कानून और व्यवस्था की बात करना चाहूँगा। मेरे पास बंसीलाल जी के समय में कानून व्यवस्था का क्या हाल था उसका पूरा बही खाता है। इनके शासनकाल में गुड़गांव में 100 करोड़ रुपये का घपला हुआ था, इसकी पूरी डिटेल मैं यहां सदन के सामने रखने जा रहा हूँ। मैं चाहूँगा कि इस 100 करोड़ रुपये के घपले वाले केस में सभी साथी मेरा साथ जरूर दें कि मुख्य मंत्री महोदय इस केस में इन्कवायरी करवायें। गुड़गांव में शकुन्तला यादव नाम की औरत थी, पिछले दिनों उसकी रिश्तेदारी के 5-7 लोग फरीदाबाद के क्षेत्र के लोगों से मिले और वे मेरे पास भी आए।

श्री रामकिशन फौजी : ********

श्री अध्यक्ष : रामकिशन जी, आप बिना परमीशन के न बोले इसलिए आप बैठें। रामकिशन जी जो कुछ बोल रहे हैं वह रिकॉर्ड न किया जाए।

श्री चन्द्र भाटिया : अध्यक्ष महोदय, मैं जो बात कहना चाहूँगा इसको बड़े ध्यान से सुनें। 116 कैनाल 11 मरले की जगह पर शकुन्तला यादव रहती थी, उसके पति लाल सिंह जिसकी मौत 20-5-91 को हो गई थी। 116

* चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

कैनाल 11 मरले की जगह लाल सिंह के नाम थी। उसकी मौत के बाद शकुंतला यादव पत्नी लाल सिंह पटवारी के पास वह जमीन अपने और अपने लड़कों के नाम करवाने के लिए गई तो पटवारी ने यह बताया कि यह जमीन पहले ही जतविन्द्र सिंह के नाम इन्तकाल हो चुकी है और इस बारे अदालत दीवानी, गुड़गांव ने बताया कि 20-10-90 को एक डिग्री जतविन्द्र के हक में कराई गई थी जिसके ऊपर इन्तकाल जतविन्द्र सिंह के नाम 8-5-91 को हो गई है जिसका पहले लाल सिंह मालिक था। 2-7-91 को श्रीमती शकुंतला यादव पत्नी लाल सिंह ने अदालत गुड़गांव में फाइल देखने के लिए दरख्वास्त दी। जिस फाइल में लाल सिंह की सारी जमीन 116 कैनाल 11 मरले जतविन्द्र के नाम करने का हुक्म था जो कि दीवानी केस नम्बर 1588/90 के तहत किया गया था। वह फाईल अदालत में नहीं मिली और फाईल गुम होने की शकुन्तला यादव ने पुलिस में दरख्वास्त दी तथा एफ.आई.आर. दर्ज करवाई। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, जो लोग मेरे पास आये थे वे कह रहे थे कि लाल सिंह मरा नहीं उसे शराब पिलाकर मारा गया था और नाजायज तरीके से उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया गया। शकुन्तला यादव को धमकियां दी जा रही हैं कि इस केस की पैरवी न करे। अध्यक्ष महोदय, 2-7-1991 को इस औरत ने दरखास्त दी थी कि इस केस की इन्क्वायरी की जाये। उस समय कांग्रेस की सरकार थी उस औरत की अर्जी पर कोई एक्शन आज तक नहीं हुआ है। यह मामला कोर्ट में गया, वहां सारी बातें हुई लेकिन उन लोगों ने मुझे बताया कि इस पर अब स्टे की कार्यवाही चल रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूँगा कि श्रीमती शकुन्तला यादव ने जो दरख्वास्त 2-7-1991 को दी थी जिस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई, जिसके ऊपर धारा 420, 467 और 471 के तहत एफ.आई.आर. दर्ज हुई थी। इस बारे में मुख्य मंत्री महोदय, सी.बी.आई. से इन्क्वायरी करवायें यदि सी.बी.आई. से इन्क्वायरी संभव नहीं तो विजीलैंस इन्क्वायरी इस मामले पर जरूर होनी चाहिए ताकि सबको पता लग जाये कि इसके अन्दर किन-किन लोगों का हाथ है तथा कौन लोग हैं जिन्होंने घपला किया है। अध्यक्ष महोदय, उस औरत को डर है कि जिन लोगों ने उनकी जमीन पर कब्जा किया है वे लोग उसको मार न डालें। इसमें काफी ऐसे लोग आयेंगे जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता। इसमें हमारे फरीदाबाद का एक आदमी शामिल है क्योंकि जो आदमी यहां नहीं बैठा मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता। अध्यक्ष महोदय, यह 100 करोड़ रुपये का घपला है, उस औरत के साथ बहुत जुल्म हो रहे हैं इसमें विजीलैंस इन्क्वायरी होनी चाहिए और आगे जब भी सदन बैठे तब सबको बताया जाये कि इसमें किन-किन लोगों का हाथ है। इसमें कुछ कांग्रेसी साथियों का हाथ भी है इसकी मैं पूरी डिटेल में नहीं जाना चाहता यदि मैं पूरी डिटेल में जाऊंगा तो बहुत समय लगेगा। इन्क्वायरी होने के बाद जो लोग इसमें शामिल हैं उनकी तस्वीर शीशे की तरह साफ हो जायेगी।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष : यदि हाउस की सहमति हो तो हाउस का समय 15 मिनट के लिए बढ़ा दिया जाए।

आवाजें : ठीक है जी।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, हाउस का समय 15 मिनट के लिए बढ़ाया जाता है।

वर्ष 2002-2003 के लिए बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री अध्यक्ष : अध्यक्ष महोदय, यह मामला मेरे हल्के से संबंधित है। मैं सदन का ध्यान इसके बारे में आकर्षित करना चाहूँगा क्योंकि कल भी एक मामला गुड़गांव से रिलेटिड उठाया गया था। कल एक साथी ने गुड़गांव के बारे में 399 करोड़ रुपये के घपले का मुद्दा उठाया। मेरे साथी को मालूम होना चाहिए कि 399 करोड़

[श्री अध्यक्ष]

रुपये बजट का बहुत बड़ा हिस्सा होता है और उन्होंने कह दिया कि 399 करोड़ रुपये का घपला हुआ। इससे ज्यादा कोई इर-रैलेवैंट बात नहीं हो सकती। 1500 रुपये गज के भाव को बढ़ाकर 1950 रुपये गज किया गया तो इससे सरकार को नुकसान नहीं होता, करोड़ों रुपये का फायदा होता है। उस चर्चा को देखा जाये तो भाटिया जी जो चर्चा कर रहे हैं गुड़गांव के बारे में यह बड़ा बर्निंग इशू है। इसमें पिछले टाइम के मंत्री तक इनवोल्व हैं। आज भी विपक्ष के कई बड़े-बड़े नेता इसमें इनवोल्व हैं, जो अपने आपको पार्टी का नेता कहते हैं। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, यह मामला डी.एल.एफ. के अंदर एक सरोल गांव का है। यह गांव हमारे राव धर्मपाल जी का गांव है। उसके अंदर यह बड़ी ही कीमती जमीन है जिसके एक एकड़ की कीमत करोड़ों रुपये है। राव लाल सिंह की मृत्यु के बाद उसके भतीजे जतविन्द्र ने उस वक्त के मंत्री के साथ मिलकर जिसकी ससुराल उस गांव में होती थी इस जमीन पर गलत तरीके से कब्जा कर लिया और गलत कागज बनाकर लिये। मैं नाम नहीं लेना चाहता इसमें उस समय के फरीदाबाद के भी एक मंत्री शामिल हैं। यह एक पूरा दल है जिसने यह घपला किया है। मैं तो यह कहूँगा कि माननीय मुख्य मंत्री इस सारे मामले की जांच करवायें। चौधरी साहब, मैं तो कहूँगा कि पिछली सरकारों में जो लूट चल रही थी उस लूट पर आज अंकुश है। मैंने पहले भी कहा कि गुड़गांव का विधायक इतना कमजोर नहीं है कि वहां पर जो किसी की मर्जी होगी वह होगा। अगर गुड़गांव में कहीं पर कोई बेकायदगी पहले कहीं पर हुई है तो वे भी मैंने उजागर की हैं। आज भी मैं कहूँगा कि गुड़गांव में जो कहीं पर भी बेकायदगी होगी वह उजागर की जायेगी। इस सारे मामले को जिसको भाई चन्द्र भाटिया जी ने उठाया है यह बहुत बड़ा मामला है इसलिए इसकी जांच कराई जाये। इस जांच से पुराने मुद्दे उखड़ेंगे और आगे भी भविष्य में रोक लगेगी। यही बात मैं कहना चाहता हूँ।

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, श्री चन्द्र भाटिया जी द्वारा जो मुद्दा उठाया गया है और जिसकी जानकारी उपाध्यक्ष जी ने भी दी है, यह बड़ा अहम् मुद्दा है। मैं इन दोनों साथियों से कहूँगा कि इस मामले में जो कोई भी डाकूमैंटस हैं वे प्रस्तुत कर दें, हम इसकी विजिलैंस से इन्कवायरी करवायेंगे।

चौधरी भजन लाल : ठीक है, इन्क्वायरी हो जाने पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जायेगा, यह अच्छी बात है।

श्री अध्यक्ष : भाटिया जी, आप पाँच मिनट में वाइंड अप करें।

श्री चन्द्र भाटिया : अध्यक्ष महोदय, अभी मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि इसकी विजीलैंस से इन्क्वायरी की जायेगी इस बारे में एक प्रार्थना और करूंगा कि जिस भी अधिकारी से इसकी जांच करायें वह एक निश्चित समय के अन्दर इसकी इन्क्वायरी करवायें। अध्यक्ष महोदय, साथ में जो कांग्रेस पार्टी के साथी बैठे हुए हैं इन्होंने भी इसकी जांच की मांग माननीय मुख्य मंत्री जी से की है, मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ क्योंकि यह काम भी उसी वक्त का था, कांग्रेस की हुकूमत के समय का था। जांच से सारी बातें खुल कर लोगों के सामने आएंगी। अध्यक्ष महोदय, अब मैं साथ ही साथ अपने हल्के के बारे में भी कुछ बातें आपके माध्यम से सरकार के सामने रखना चाहता हूँ। हमारे फरीदाबाद के अन्दर नगर निगम पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, हमारे विधान सभा क्षेत्र में इन पिछले दो सालों के अन्दर यानि फरीदाबाद के अन्दर लगभग ऐसी कोई सड़क नहीं है जो टूटी हुई हो। माननीय मुख्य मंत्री के आदेश पर मेरे विधान सभा क्षेत्र की सभी सड़कें बनकर तैयार हैं। नगर निगम के अन्दर मुख्य मंत्री के आदेश पर करोड़ों रुपये का काम किया जा रहा है। यदि कहीं पर बिजली की बात आती है तो बिजली की तारों को बदला जा रहा है, कहीं पर ट्रांसफार्मर बदले जा रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है कि हम किसी भी बात को लेकर चलें हर काम वहां पर हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय, हमारे फरीदाबाद में पानी की समस्या थी। जब हमने यह समस्या माननीय मुख्य मंत्री जी

के सामने रखी तो इन्होंने हमारी बात को बड़े ध्यान से सुना। पिछली सरकार के वक्त में रेनी वैल योजना का काम चालू करने के लिए कहा गया था। जब हमारा बंसी लाल जी से संघर्ष चल रहा था तो उस वक्त जब हम यह समस्या उनके सामने रखते थे यानि अपनी बात कहते थे इनको तकलीफ होती थी। उस वक्त इस काम को रोक दिया गया था। जब हम यह बात मुख्य मंत्री जी के नोटिस में लाये तो इन्होंने इस योजना पर तेजी से काम करने के आदेश दिए। यह काम शायद अप्रैल में पूरा होगा। इस योजना पर 40 करोड़ रुपये की लागत आ रही है। इस योजना के चालू हो जाने पर फरीदाबाद के लोगों को पानी की कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अध्यक्ष महोदय, अब मैं कानून व्यवस्था के बारे में बात करना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष : भाटिया जी, आप अपनी बात जल्दी खत्म करें।

श्री चन्द्र भाटिया : अध्यक्ष महोदय, मैं कानून व्यवस्था की बात करने से पहले एक बात मुख्य मंत्री जी से जरूर कहूँगा कि आज हमारे फरीदाबाद में विकास के काम बहुत हो रहे हैं। मैं मुख्य मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूँ कि पिछली हुकूमत में जब हाउस टैक्स देने की बात होती थी उस बारे में नगर निगम की उनके वक्त में एक कमेटी बनी हुई थी। जिस वक्त वहां पर नगर निगम बना तो उस वक्त प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। यानि उस वक्त वहां पर हाउस टैक्स से संबंधित नगर निगम की जो कमेटी बनी थी उसने एक रैज्योल्यूशन किया था कि हाउस टैक्स बढ़ाया जाये। पीछे चौधरी बंसी लाल जी ने कहा था कि हाउस टैक्स कम किया जाये। अध्यक्ष महोदय, आज की सरकार ने हरियाणा के अन्दर सब जगह पर टैक्स कम किए, यह बहुत ही सराहनीय काम है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि हमारा फरीदाबाद नगर निगम एक बहुत बड़ा नगर निगम है। हमारे मुख्य मंत्री जी ने यह सोचा है कि हरियाणा के अन्दर फरीदाबाद के अन्दर खासतौर पर विकास कार्य हों और वहां पर जो हाउस टैक्स है वह बढ़ा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि क्योंकि मुख्य मंत्री जी की जो सोच है वह यह है कि अगर पैसा आयेगा तो विकास के काम जरूर होंगे। जैसे कि मैंने कहा है फरीदाबाद के अन्दर काम होने की कोई कमी है। कुछ लोग तो यह चाहते हैं कि नगर निगम फरीदाबाद के अन्दर जो हाउस टैक्स बढ़ा हुआ है वह कम न हो लेकिन मैं यह कहना चाहूँगा कि हाउस टैक्स कम होने से पैसा बहुत ज्यादा आएगा। अध्यक्ष महोदय, आज लोग हाउस टैक्स का पैसा जमा करवा रहे हैं लेकिन कुछ पैसा तो आम आदमी से भी आना चाहिए वह पैसा भी आएगा। हरियाणा के अन्दर जो हाउस टैक्स लगा हुआ है उसके बारे में मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहूँगा कि इसी प्रकार से फरीदाबाद को भी हाउस टैक्स में बराबर किया जाए। अध्यक्ष महोदय, इसी के साथ मैं यह भी कहना चाहूँगा कि यदि मुझे और समय दिया जाए तो मैं चौधरी बंसी लाल जी के बारे में कहना चाहूँगा। उनके कारनामों की यह मेरे पास लिस्ट है जिसमें एक से लेकर 27 तक केसिज हैं चौधरी बंसी लाल के खिलाफ (विध्न)। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया उसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ तथा इस बजट का बड़े जोर-शोर से समर्थन करता हूँ। जयहिन्द।

चौ. जय प्रकाश (बरवाला) : अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि क्योंकि आप मुझे पांच मिनट का समय देंगे और मुझे पता है कि पांच मिनट में ही आप हाउस को ऐडजोर्न कर देंगे।

श्री अध्यक्ष : जय प्रकाश जी, आपके पास दस मिनट का समय है, आप पूरे 10 मिनट बोलें।

चौ. जय प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, वित्त मन्त्री जी जिन्होंने बजट भाषण हाउस में दिया और मुख्य मंत्री जी भी कह रहे थे कि बजट पर बोलें। मुख्य मंत्री जी की बात तो सारे हाउस को माननी चाहिए जब इन्हीं के सहयोगी साथी इनकी बात को नहीं मान रहे हैं तो हम इनकी बात मानने के लिए क्यों विवश है। अध्यक्ष महोदय, मैं पर्टिकुलरली एक बात कहना चाहूँगा क्योंकि मेरे से पहले विज साहब बोले, भाटिया जी बोले मेरे कहने का तात्पर्य

[चौ. जय प्रकाश]

यह है कि मैंने देख लिया है कि सबसे पहले राजनीति की बात कही कि यमुना नगर के अन्दर बड़ी भारी जीत हुई है सरकार की नीतियों की। इसमें कोई दो राय नहीं है कि यमुना नगर में इनेलो पार्टी का प्रत्याशी बहुत बड़े बहुमत से जीता है लेकिन इसके मायने यह नहीं हैं कि यह पार्टी की नीतियों की जीत है। यमुना नगर का प्रत्याशी केवल इनैलो का ही प्रत्याशी नहीं था, मुख्य मंत्री जी, इस बात को सारे प्रदेश के लोग जानते हैं कि वहां से इनेलो का प्रत्याशी नहीं बल्कि सरकार का प्रत्याशी जीता है। सरकार ने सारा सरकारी तन्त्र सारा सरकारी ताम-झाम खासकर अधिकारी वर्ग को वहाँ झोंका हुआ था। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : जय प्रकाश जी, आप बजट पर बोलें। (विघ्न) आपके हाथ में किताब है, आप बजट पर बोलें। (विघ्न)

चौ. जय प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, सारा सरकारी तंत्र, सारे बड़े अधिकारी यमुना नगर में डाल दिए गए हम तब भी मानते हैं कि चलो कोई बात नहीं। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : आप इसके लिए इलेक्शन पैटीशन कर सकते हैं। इलेक्शन पैटीशन करना आपका अधिकार है, लेकिन इस बारे यहां प्र. मत बोलें। (विघ्न)

चौ. जय प्रकाश : जो मेरे से पहले बोलें हैं उनकी बात आपने सुन ली अब मेरी बात भी सुन लें। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : आप तो खुद पार्लियामैंट में रहे हैं इसलिए आप अच्छे ढंग से बोलो।

चौ. जय प्रकाश : इस बात के लिए इनेलो के लोगों ने ही जिक्र किया है। 1996 में विधान सभा का उपचुनाव हुआ था। इस बात के लिए इनेलो के लोगों को हौंसले बहुत ज्यादा बुलन्द नहीं करने चाहिएं। ज्यादातर बाई-इलैक्शन सरकार के हक में होते हैं। 1993 में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला नरवाना से 18,000 मतों से जीते थे और 1996 में अगर नीतियों पर मुहर होती तो कांग्रेस का प्रत्याशी जीतता और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला तीसरे नम्बर पर रहे थे। यह किन नीतियों की बात कर रहे हैं। (विघ्न)

पशुपालन राज्य मंत्री (चौधरी मुहम्मद इलियास) : स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट ऑफ ऑर्डर है। स्पीकर साहब, मैं आपके जरिये से माननीय साथी सदस्य को बताना चाहूँगा कि जैसे कि भाई जय प्रकाश जी ने कहा है कि वहां पर सरकारी तन्त्र का इस्तेमाल हुआ, सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल हुआ। सन् 1984 में हरियाणा प्रदेश के अन्दर बाई-इलैक्शन हुआ था और तावडू विधान सभा से बाई-इलैक्शन हुआ था। हमारे विपक्ष के आदरणीय नेता उस वक्त हरियाणा प्रदेश के मुख्य मंत्री होते थे। अगर सरकारी तन्त्र से ही इलैक्शन जीता जाता तो मैं विपक्ष के माननीय नेता से पूछना चाहता हूँ कि आपकी पार्टी उस वक्त वह इलैक्शन क्यों हारी थी ? (विघ्न एवं शोर)

चौ. भजन लाल : अब आप उधर जाकर बैठ गए उस वक्त उस हार में आप भी हमारे साथ ही थे।

चौ. मुहम्मद इलियास : हरियाणा प्रदेश की जनता ने और यमुनानगर की जनता ने भी यह साबित कर दिया है। चौधरी साहब, यह कहने वाली बात नहीं है लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि 36 साल के पीरियड में कोई विकास हुआ है, अगर कोई सम्मान जनता को मिला है तो वह इस सरकार के समय में मिला है। (शोर एवं व्यवधान)

चौ. जय प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, मैंने यही बात कही कि अगर पार्टियों की नीति पर मोहर लगती तो 1993 में कांग्रेस हारी और 1996 में कांग्रेस जीत गई। यह तो समय का तकाजा है। इस बात के लिए इनैलो के साथियों को ज्यादा खुशफहमी में नहीं रहना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जय प्रकाश जी। आप बजट पर बोलें। (शोर एवं व्यवधान)

चौ. जय प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, ये खुद इस तरह की बातें करते हैं और जब कोई दूसरा बात करे तो इनको भी दूसरे आदमी को इस बात के लिए रोकना नहीं चाहिए। अध्यक्ष महोदय, यह सरकार कहती है कि अगर किसानों को नुकसान होगा तो हम सर्वेसर्वा कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब जो बजट अभिभाषण प्रो. सम्मत सिंह ने सदन में पढ़ा है उसमें कृषि के लिए पिछले साल की तुलना में अब की बार कम पैसा दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, 1980 में जब मैं लोकसभा का चुनाव लड़ रहा था तो आज के मौजूदा मुख्य मंत्री जी जींद में चौधरी देवी लाल जी का जन्मदिन मना रहे थे और इन्होंने वहां पर कहा था कि अगर हमारी सरकार आएगी तो बिजली के बिल माफ कर दिए जाएंगे, बिजली मुफ्त कर दी जाएगी। आज उसी का नतीजा है कि कण्डेला के अन्दर किसानों पर जो कि शांतिपूर्वक अपनी बात कहना चाहते थे, उन पर गोलियां चलाई गई और 31 किसानों को घायल कर दिया गया।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, ये लोग बार-बार इस मुद्दे को बहुत प्रचारित करते हैं। जबकि हमने हमारे चुनाव घोषणा पत्र में जोकि 6 फरवरी, 2000 को रीलिज किया था और 7 फरवरी, 2000 की अखबार में छपा था उसमें लिखा था कि बिना पैसे बिजली नहीं दी जाएगी और जिनकी तरफ बिजली के बिल बकाया हैं, वे वसूल किए जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, यहां पर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष श्री हुड्डा जी बैठे हुए हैं। मेरे पास 25-8-1999 के अखबार की एक खबर है, इसमें चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा का ब्यान है, अब जिस हुड्डा का यह ब्यान है यह हुड्डा कोई और है तो मुझे पता नहीं। हुड्डा ने कहा है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो बिजली पानी मुफ्त उपलब्ध करवाई जाएगी, चुंगी भी माफ की जाएगी। इसके बाद हुड्डा जी कहते हैं कि मैं प्रदेश की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अगर ऐसा करने में हम नाकामयाब रहे या हमें देरी हुई तो हम तुरन्त इस्तीफा दे देंगे। यह बात भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने कही है। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, चौधरी जय प्रकाश को मुगालता रह गया होगा। कईयों को तो फौबिया है, उनको तो ओम प्रकाश चौटाला के सिवाए कुछ दिखाई ही नहीं देता है। (शोर एवं व्यवधान)

वैयक्तिक स्पष्टीकरण--

(iii) श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा द्वारा

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने मेरा नाम लिया है मैं इस बारे में पर्सनल एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, जो मुख्य मंत्री जी ने ब्यान पढ़कर बताया है वह चुनाव से पहले का है। हमारे घोषणा पत्र में क्या था ये वह भी पढ़ लें। उसमें हमने कहा था कि सस्ती बिजली देंगे और आज भी हम किसानों को सस्ती बिजली देने के लिए वचनबद्ध हैं।

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : मैं यह कटिंग हुड्डा जी आपके पास भेज देता हूँ आप इसको पढ़ लें कि आपने किसानों को सस्ती बिजली देने के लिए कहा था या बिजली मुफ्त देने के लिए कहा था।

(इस समय अखबार की कटिंग की फोटोस्टेट कापी श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी को भेजी गई।)

श्री अध्यक्ष : हुड्डा जी, आप यह कटिंग सदन में पढ़ कर सुनाएं।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : हमने जो वायदा किया था वह किसको देने का किया था, जो गरीब से गरीब आदमी होंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप यह कटिंग पढ़कर सुनाएं।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : इसको मैंने पढ़ लिया है और सुन भी लिया है। अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी हमारा घोषणा पत्र भी देख लें और उसको पढ़ लें। (शोर एवं व्यवधान) आज सारा हरियाणा जानता है कि इन्होंने झूठ बोलकर ओथ ली है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब, आप इसको पढ़कर सुनाएं। (शोर एवं व्यवधान)

चौ. भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, रूलिंग पार्टी वाले बीच में बार-बार बोल रहें हैं। इनको आप रोकें और श्री जय प्रकाश जी को बोलने दें। मैंने भी कम से कम 15 मिनट और बोलना है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : चौधरी भजन लाल जी, आप बैठें। आपको भी समय दिया जाएगा। (शोर एवं व्यवधान) सदन के नेता खड़े हैं इसलिए आप बैठ जाएं और मुख्य मंत्री जी क्या कह रहे हैं उनको सुनें।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का अच्छी तरह से पता है कि भजन लाल और हुड्डा दोनों यहां पर दुर्भाग्य से इकट्ठे हैं वैसे ये इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मुझे पता था कि अगर मैं इनकी बात कहूंगा तो भजन लाल जी भी बोलेंगे इसलिए मैं इनके ब्यान की दूसरी कापी भी लेकर आया हूँ। अध्यक्ष महोदय, आप किसी सरकारी कर्मचारी को बुलाएं और उसको यह कहें कि यह कापी श्री भजन लाल जी को भी दे दे। (शोर एवं व्यवधान)

(इस समय अखबार की कटिंग की फोटोस्टेट कापी श्री भजन लाल जी को भेजी गई।)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : मुख्य मंत्री जी, आप हमारा घोषणा पत्र भी पढ़ लेना। (शोर एवं व्यवधान) पंजाब सरकार भी किसानों को बिजली पानी मुफ्त दे रही है और वहां पर भी कांग्रेस की सरकार है। (शोर एवं व्यवधान)

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष : यदि हाउस की सहमति हो तो हाउस का समय 5 मिनट के लिए बढ़ा दिया जाए।

आवाजें : ठीक है जी।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, हाउस का समय 5 मिनट के लिए बढ़ाया जाता है।

वर्ष 2002-2003 के लिए बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

चौ. जय प्रकाश : स्पीकर सर, यह बात मैं 1999 या 2000 की नहीं कर रहा हूँ। मैं यह बात 1998 की कर रहा हूँ। चीफ मिनिस्टर साहब भी इस बात को मानेंगे। उस समय लोक सभा के चुनाव थे और लोक सभा के चुनाव में उस समय इनेलो और बसपा के प्रत्याशी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। अध्यक्ष महोदय, उस समय मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि हम मुफ्त में बिजली देने के लिए तैयार हैं। इन्होंने इस तरह की बातें करके उस समय लोगों को भ्रमित कर दिया। इन्होंने कहा था कि जब इनेलो की सरकार बनेगी तो बिजली के बिल माफ कर देंगे लेकिन इन्होंने ये माफ नहीं किए। इसी कारण लोगों ने बिजली के बिल नहीं भरे। इसी कारण सरकार के दो मंत्री दो बार वहां पर जा चुके हैं लेकिन आज तक उस मामले का समाधान नहीं निकल सका है। भाई राम पाल जी दो दिन से लगातार एक बात कह रहे थे कि बिजली विभाग के इंफ्रास्ट्रकचर के लिए सरकार ने करोड़ों रुपये खर्च कर दिए।

मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से आपके माध्यम से पूछना चाहूँगा कि 1991 से लेकर आज तक हरियाणा प्रदेश के किसान की खेती में जो बिजली प्रयोग में लायी गयी उसके रेट कितने बढ़े हैं ? एक तरफ पंजाब है वहां के किसानों को बिजली मुफ्त मिल रही है। इसी तरह से दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश है जहां पर इनकी पार्टी के केवल एक प्रत्याशी को छोड़कर सबकी जमानत जब्त हो गयी, वहां पचास रुपये प्रति हार्स पावर के हिसाब से किसान को बिजली मिलती है। हरियाणा प्रदेश का किसान इस बजट से बड़ा निराश है, बड़ा दुखी है। बिजली के मामले में किसान को कोई सहूलियत नहीं दी गयी है। इसी तरह से जहां तक किसान के पानी की बात है, एस.वाई.एल. का मामला कल जब हाउस में आया तो हमारे सी.एल.पी. लीडर ने भी और हमारे पार्टी प्रैजीडैंट ने भी उस रैजोल्यूशन का समर्थन किया। मैं आज भी कहता हूँ कि एस.वाई.एल. कैनाल का पानी आए लेकिन मैं मुख्य मंत्री महोदय को उनकी उस घोषणा को भी याद दिलाना चाहूँगा जो उन्होंने चुनाव से पहले मेरे विधान सभा क्षेत्र में की थी कि मतलौडा और खेड़ी जालम माईनर्ज खुदवाए जाएंगे। अगर इन दोनों माईनर्ज को खुदवाने के लिए इन्होंने न कहा हो तो मैं अपने शब्द वापस लेने के लिए तैयार हूँ। मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री महोदय से पूछना चाहूँगा कि जो वहां पर मतलौडा का इलाका, या बोबुआ का सूखा इलाका है उसके लिए ये कब इन माईनर्ज को खुदवाएंगे ?

चौ. भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। मेरा कहना है कि जय प्रकाश जी को बोलने नहीं दिया है इसलिए आप उनको दो बजे तक बोलने दें। यानि सिर्फ दस मिनट।

श्री अध्यक्ष : भजन लाल जी, आप बैठे।

वित्त मंत्री (प्रो. सम्पत सिंह) : स्पीकर सर, टाइम अलॉट करने की आपकी अपनी सीमा है लेकिन जैसा विपक्ष के नेता ने जो यह कहा कि उनको बोलने नहीं दिया गया, यह बिल्कुल सरासर गलत बात है। जब आपने गवर्नर ऐड्रस पर टाइम बढ़ाया था तो इन्होंने विरोध किया था।

श्री अध्यक्ष : भजन लाल जी, जब हमने उस समय टाइम बढ़ाया था तो आप विरोध कर रहे थे।

चौ. जय प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, सम्पत सिंह जी मेरा समय खराब कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से जानना चाहूँगा कि जो इन्होंने उन दोनों माईनर्ज को खुदवाने की घोषणा की थी तो ये बता दें कि कब तक ये उनको पूरा करवाने का कष्ट करेंगे। मुख्य मंत्री महोदय और इमेलो के सभी लोग बार-बार कहते हैं और मैं भी यह बात मानता हूँ कि चौधरी देवी लाल कहा करते थे कि लोक राज लोक लाज से चलता है लेकिन अब लोक लाज नाम की चीज नहीं रह गयी है। यदि हरियाणा प्रदेश में लोक लाज होता तो जिन माईनर्ज की घोषणा चुनाव से पूर्व मुख्य मंत्री द्वारा की गयी थी वे अब तक पूरे हो जाते। मैं उनसे कहना चाहूँगा कि तुरन्त प्रभाव से ये दोनों माईनर्ज बनवाए जाएं ताकि वहां के जो सूखे खेत हैं उनको पानी मिल सके, उनकी आबपाशी हो सके। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से माईनिंग की चर्चा यहां बड़ी देर से चल रही है। मैं इस बात को तो मानने के लिए तैयार हूँ कि पिछली सरकारों के बनिस्बत इस सरकार के खजाने में ज्यादा पैसा आया है लेकिन मैं सारे सदन को सूचित करना चाहता हूँ कि पिछली सरकारों के समय में एक जमुना सैंड की ट्राली 150 रुपये में मिलती थी जबकि अब इसकी कीमत 600 रुपये है। उपभोक्ता बुरी तरह से परेशान है। इस सरकार की नीतियों की वजह से आज फरीदाबाद और गुड़गांव के अंदर जो क्रैशर जोन है उनकी हालत आप देखिए। पहले उपभोक्ता को जो रोड़ी चार सौ रुपये प्रति सैंकड़ा मिलती थी वही आज उसका भाव 1200 या 1300 रुपये प्रति सैंकड़ा है। यह किसको नुक्सान हुआ है यह हरियाणा प्रदेश के उपभोक्ता को नुक्सान हुआ है। आज एक कोकस हरियाणा में बना है और इनका ही हरियाणा में माईनिंग पर कब्जा है। इनको ही आज फायदा हुआ है। मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से कहना चाहूँगा कि इसकी जांच सी.बी.आई. से करवायी जाए। अंत में मैं एक बहुत जरूरी बात कहना चाहूँगा। मुझे पता है कि मुझे ज्यादा समय नहीं मिलेगा। यहां पर एक चर्चा बड़ी चलती है। कई भाई बड़ा शोर करते हैं कि वह पैसा खा गया, वह पैसा खा गया। मुख्य मंत्री जी

[चौ. जय प्रकाश]

बता दें कि 1952 से लेकर आज तक जितने भी राजनीतिक लोग है आज तक जितने भी एम.पी.,एम.एल.ए. बने हैं सबकी सम्पत्ति की जाँच कराई जाए। आपका बहुत भला होगा। ये कहते हैं कि मैं रिश्वत नहीं खाता, वे कहते हैं मैं रिश्वत नहीं खाता। जबकि खाते सारे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपका समय समाप्त होता है, अब आप बैठ जाएं। (शोर एवं व्यवधान) Hon'ble Members, now the House stands adjourned till 2.00 P.M., the 18th March, 2002.

*13.50 hrs. (The Sabha then *adjourned till 2.00 P.M. on Monday, the 18th March, 2002.)

34831—H.V.S.—H.G.P., Chd.